चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

किसान आंदोलन चौथी दुनिया और सुप्रीम कोर्ट

पेज-3

सच कहने की सज़ा

पेज-4

विपक्ष का गुरूर चकनाचूर

पेज-5

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 11 जुलाई–17 जुलाई 2011 | मूल्य 5 रुपये

तेल कंपनियां या सरकार

देश कौन चला रहा है

ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों को सरकार नहीं चलाती है, तेल कंपनियां ही सरकार को चला रही हैं. अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि जब देश पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है तो ऐसे में तेल की क़ीमत बढ़ा दी जाती है. जबसे मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तबसे वह पेट्रोलियम से सरकारी नियंत्रण हटाने की जुगत में लग गई. डीजल और किरोसिन के दाम बढ़ते ही देश में हाहाकार मचा गया, लेकिन एक देश की सरकार है, जो आंकड़े दिखाकर सफलता का ढिंढोरा पीट रही है, ग़रीबों का मज़ाक उड़ा रही है.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

यह कैसी सरकार है, जो जनता के ख़र्च को बढ़ा रही है और जीवन स्तर को गिरा रही है. वैसे दावा तो यह ठीक विपरीत करती है. वित्त मंत्री कहते हैं कि सरकार अपनी नीतियों के ज़रिए नागरिकों की कॉस्ट ऑफ लिविंग को घटाना और जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहती है. पर वह कौन सी मजबूरी है, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं. पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी कहते हैं कि वह अर्थशास्त्र और लोकप्रियता के बीच फंस गए. वैसे यह अच्छा बहाना है. वह कहते हैं कि दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है. यह एक झूठ है. वह इसलिए, क्योंकि सिर्फ़ पेट्रोल को सरकार ने डी-रेगुलेट किया है. मतलब यह कि सिर्फ़ पेट्रोल की क़ीमत का रिश्ता अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत से है. मिट्टी तेल, डीजल और रसोई गैस का जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से कुछ लेना-देना नहीं है तो फिर सरकार ने डीजल और रसोई गैस की क़ीमतों में क्यों इज़ाफ़ा किया? सरकार इस झूठ के साथ-साथ कई और झूठ फैला रही है. एक झूठ यह है कि तेल कंपनियां घाटे में चल रही हैं. मई के महीने में महंगाई की दर 9 फ़ीसदी के आसपास थी. डीजल के दाम बढ़ते ही सारी चीज़ों के दामों में इज़ाफ़ा हो गया. महंगाई की दर 10 फ़ीसदी से ज़्यादा हो जाए, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है. इस बीच प्रधानमंत्री ख़ुद के चुने हुए पांच अख़बारों के संपादकों से बातचीत करते हैं. वह उन्हें बताते हैं कि मार्च 2012 तक महंगाई पर नियंत्रण कर लिया जाएगा. प्रधानमंत्री ने साथ में एक शर्त भी रख दी कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत में बढ़ोत्तरी नहीं होती है.

अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में जब कच्चे तेल के दामों में वृद्धि होती है तो सरकार तुरंत पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा देती है, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट आती है तो सरकार उसे देश में लागू क्यों नहीं करती.

पांच राज्यों के चुनाव ख़त्म हुए और केंद्र की यूपीए सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए. सरकार कहती है कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है. इसके बाद प्रणव मुखर्जी ने राज्य सरकारों से टैक्स कम करने की अपील क्यों की? कांग्रेस शासित दो राज्यों में दाम कम भी किए गए. पता नहीं, राजनीतिक दलों को यह भ्रम कैसे हो गया है कि देश की जनता मूर्ख है. क्या सरकार ऐसे फ़रमान जारी करके यह साबित करना चाहती है कि वह जनता के दु:ख-दर्द के प्रति चिंतित है? असलियत तो यह है कि सरकार जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनहीन हो चुकी है. उसकी प्राथमिकता केवल निजी कंपनियों और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना है.

जब पेट्रोल की क़ीमत बढ़ाई गई, तब सरकार ने देश से सबसे बड़ा झूठ बोला कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत बढ़ गई है. एक बात समझ में नहीं आई कि जिस दिन पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, उस दिन अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत 112 डॉलर प्रति गैलन थी. आज इसकी क़ीमत लगभग 90 डॉलर प्रति गैलन है. सरकार अगर यह दलील देती है कि कच्चे तेल की क़ीमत बढ़ने से दाम बढ़ाए गए हैं तो अब जब इसकी क़ीमत में गिरावट आई है तो उसे देश में पेट्रोल की क़ीमत कम करनी चाहिए थी. सवाल यह उठता है कि क्या सरकार तेल उस तरह ख़रीदती है, जिस तरह घर में सब्ज़ियां ख़रीदी जाती हैं. क्या भारत हर दिन के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से कच्चा तेल ख़रीदता है. हम कच्चा तेल ख़रीदते हैं, उसे देश में लेकर आते हैं, जामनगर जैसी रिफाइनरी में प्रोसेसिंग के बाद उसे ट्रकों में भरा जाता है, चेकिंग वग़ैरह होती है, फिर कहीं उसे पेट्रोल पंपों में भेजा जाता है. कच्चा तेल ख़रीदने और उसे पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने में कम से कम 75 दिनों का वक़्त लगता है. सवाल यह उठता है कि मान लीजिए, तीन दिन पहले कच्चे तेल का दाम बढ़ जाता है तो उसका असर 75 दिनों के बाद दिखना चाहिए. सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों मची है कि वह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में दाम बढ़ते ही देश में क़ीमत बढ़ा देती है, लेकिन जब दाम गिर जाते हैं तो फिर रोलबैक नहीं करती? पेट्रोल की क़ीमत बढ़ाने के साथ-साथ उसे तेल आपूर्ति करने वाली कंपनियों के साथ किए गए

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सरकार पर रिलायंस को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप

आजकल सरकार बेचैन है. रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है. आरोप बेबुनियाद नहीं है. आरोप का आधार सीएजी रिपोर्ट है. वैसे यह आधिकारिक रूप से संसद के सामने पेश नहीं हुई है, इसकी ख़बर मीडिया में लीक हो गई है. सरकार पर आरोप यह है कि उसने जान-बूझकर रिलायंस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया और इससे देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुक़सान हुआ. यह नुक़सान 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले से भी बड़ा है. रिलायंस कंपनी पर सरकार ने दरियादिली का इज़हार कुछ ऐसे किया कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन के गैस की क़ीमत तय करने के लिए सचिवों का एक समूह बना. पिछले कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष बनाए गए. आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी की तीन चिट्ठियों को आधार बनाया गया था. रेड्डी का सुझाव था कि सरकारी कंपनी एनटीपीसी से रिलायंस को 2.97 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू गैस मिलती थी. यह दर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के ज़रिए तय की गई थी, सो इसे ही बाज़ार दर माना जाए. इस समूह ने यह भी कहा कि गैस की क़ीमत अगर एक डॉलर भी बढ़ती है तो रासायनिक खाद सेक्टर का ख़र्च बढ़ेगा, जिससे सरकार पर कई हज़ार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ आएगा. पर मंत्री समूह ने इन सारी दलीलों को ख़ारिज कर गैस की क़ीमत 4.2 डॉलर तय की. इस तरह रिलायंस को फ़ायदा पहुंचाया गया. सरकार को कितना नुक़सान हुआ, इसका आकलन करने में सीएजी ने हाथ खड़े कर दिए हैं. सीएजी का कहना है कि नुक़सान का आंकड़ा इतना बड़ा होगा कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल है. ज़ाहिर है, संसद के अगले सत्र में संचार के साथ-साथ पेट्रोलियम घोटाला भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा. अगर यह मुद्दा नहीं बना तो आप स्वयं ही समझ लीजिए कि सरकार के साथ-साथ देश के दूसरे राजनीतिक दलों को कौन चला रहा है.

अगर सरकार भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है तो सबसे पहले उसे पेट्रोलियम मंत्रालय को दुरुस्त करना होगा. देश में पेट्रोल, केरोसिन और डीजल का कारोबार माफ़िया चलाते हैं. सरकार को जवाब देना चाहिए कि तेल की चोरी और कालाबाज़ारी के चलते हर साल 70,000 करोड़ रुपये का नुक़सान होता है, उसे ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया है.

"Cotton ki Jhappi!"
T.T.
Healthy Innerwear
Vest • Brief • Bra-Panties • T-Shirts
Ph. : 011-45060708, E-mail: export@tttextiles.com

वर्तमान परिस्थितियों पर नज़र डालें तो मथाई को एक साथ कई मोर्चे पर काम करना होगा.

दिल्ली का बाबू

मथाई और विदेश नीति

अगले विदेश सचिव के तौर पर रंजन मथाई के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है. इसी के साथ अगला विदेश सचिव कौन की दौड़ भी खत्म हो गई है. मथाई 2007 से फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे. पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त शरत सभरवाल और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय राजदूत हरदीप पुरी इस पद के अन्य दावेदारों में थे, लेकिन आखिरकार मथाई को ही इस पद के लिए चुना गया. निवर्तमान विदेश सचिव निरूपमा राव को अमेरिका का राजदूत बना दिया गया है और वह बहुत जल्द वाशिंगटन के लिए रवाना हो जाएंगी. ऐसी स्थिति में मथाई के पास अपनी नई चुनौतियों की बारीकियां समझने के लिए बहुत कम समय है. वर्तमान परिस्थितियों पर नजर डालें तो मथाई को एक साथ कई मोर्चे पर काम करना होगा. विशेष रूप से पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध के मुद्दे पर उनकी सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होने वाली है. इस समय पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध सहज नहीं हैं. चीन, अफगानिस्तान और नेपाल में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं. विदेश मामलों की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों का मानना है कि मथाई को पड़ोसी देश में काम करने का कम अनुभव है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे सकी और वरिष्ठता को ही वरीयता दी गई.

दिलीप चेरियन

बाबुओं की चिंता

घोटालों और भ्रष्टाचार के इस दौर में नेताओं और बाबुओं का चिंतित होना लाजिमी है. यही वजह है कि वे अपना हर कदम फूंक-फूंक कर रख रहे हैं. उन्हें चिंता इस बात की है कि कहीं उनसे कोई ऐसा काम न हो जाए, जो उनकी परेशानी का कारण बन जाए. पी जे थॉमस को सीवीसी बनाए जाने पर जो किरकिरी सरकार की हुई, उसे वह दोहराना नहीं चाहती. इसी कारण इस पद पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई है. पूर्व दूरसंचार सचिव सार्थक बेहुरा का नाम 2-जी घोटाले में आने के बाद हुई उनकी गिरफ्तारी का बड़े अधिकारियों पर काफी प्रभाव पड़ा है. अब किसी भी फाइल पर कोई भी फैसला लेने से पहले वे उसकी अच्छी तरह जांच-पड़ताल करने लगे हैं, ताकि कोई भूल न हो जाए. उन्हें पता है कि सीबीआई सभी पर नजर रख रही है और एक भूल उनका करियर चौपट कर सकती है. इन वजह से सभी सावधान हैं. कई बड़े काम अटके पड़े हैं. वरिष्ठ बाबू यह उमीद लगाए हुए हैं कि उनके और राजनीतिक आकाओं के बीच एकपक्षीय एवं अनियंत्रित संबंध के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, ताकि उनकी परेशानी कम हो सके. बहरहाल, ये बाबू किसी तरह संकट के इस दौर से खुद को सुरक्षित निकाल ले जाने के खेल में ही व्यस्त हैं.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

बाबू बिन विभाग

सरकार के तीन महत्वपूर्ण विभाग बिना उच्चाधिकारी के काम कर रहे हैं. सरकार इन पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अधिकारी की तलाश कर रही है. पी जे थॉमस की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद से ही सीवीसी का पद रिक्त है. इसी तरह एनएचएआई और आईटी विभाग में भी सचिव का पद खाली है.

कई बाबू परेशान

एक ओर जहां 1977 बैच के कई आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति सचिव के रूप में की गई, वहीं इसी बैच के दो वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी कर दी गई. ये दो अधिकारी हैं, शेखर अग्रवाल और नावेद मसूद. शेखर अग्रवाल रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं, जबकि मसूद स्वास्थ्य मंत्रालय में इसी पद पर हैं. कई नौकरशाह चिंतित हैं कि कहीं ऐसा दूसरे बैच के साथ भी न किया जाने लगे.

विश्वनाथ की जगह रवनीत

रवनीत कौर को सी विश्वनाथ की जगह डब्लूडीआरए का नया संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. रवनीत कौर पंजाब कैडर के 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. दूसरी तरफ सी विश्वनाथ को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है.

गुजराल सचिव बनेंगे

वर्ष 1976 बैच के आईएएस अधिकारी आर एस गुजराल को राजस्व सचिव बनाया जाएगा. गुजराल को सुनील मित्रा के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा. मित्रा 1975 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो रिटायर होने वाले हैं.

यशपाल बनेंगे जेएस

वर्ष 1984 बैच के आईएएस अधिकारी यशपाल सिंह केमिकल और पेट्रो केमिकल विभाग के संयुक्त सचिव बनाए जा सकते हैं. उन्हें एस सी गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा.

देश कौन चला रहा है

पृष्ठ एक का शेष

क़रार को भी सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि देश की जनता को यह पता चले कि सरकार ने किस रेट पर कच्चा तेल ख़रीदने का सौदा तय किया है.

समझने वाली बात यह है कि क्या भारत सरकार तेल को घर के सामान की तरह ख़रीदती है. दुकानदार कहता है कि आज दाम बढ़ गए हैं तो साबुन के दाम दो रुपये ज़्यादा हो गए हैं. जितने भी तेल के सौदे होते हैं, उन्हें फाइनेंस के टर्म में कमोडिटी डेरीवेटिव्स कहते हैं, उसे हम फ्यूचर्स कहते हैं. कहने का मतलब यह है कि जब सौदेबाज़ी होती है, वह किसी सट्टे की तरह होती है. बेचने वाला और ख़रीदने वाला अनुमान लगाता है. दोनों ही अनुमान लगाते हैं कि अगले सात महीनों में पेट्रोल का दाम क्या होने वाला है. ख़रीदने वाले की मजबूरी यह है कि उसे पता है कि पूरे मुल्क की ज़रूरत क्या है. भारत के अनुभव से यह साबित हो चुका है कि जब तक कच्चे तेल की क़ीमत 90 डॉलर प्रति गैलन रहे, तब तक भारत की इकोनॉमी पर कुछ भी फ़र्क़ नहीं पड़ता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि जब अमेरिका में गिरावट आई, तब वे 40 डॉलर प्रति गैलन से कच्चे तेल की क़ीमत 90 डॉलर तक लेकर चले गए. यह वायदा कारोबार की वजह से हुआ. वायदा कारोबार करने वालों ने एक गिरोह खड़ा कर लिया. ये लोग असल में तेल नहीं ख़रीदते, बल्कि काग़ज़ ख़रीदते हैं और जब वास्तव में तेल लेने का समय आता है तो ये उसे बेच देते हैं. अक्सर होता यह है कि एक निर्धारित समय पर डिमांड अचानक से बढ़ जाती है और तेल के दाम बढ़ जाते हैं. हालत यह हो गई कि जो तेल 40 डॉलर प्रति गैलन बिक रहा था, इस वायदा कारोबार की वजह से उसकी क़ीमत 140 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई. तेल की क़ीमत तब बढ़ती है, जब इसकी खपत बढ़ती है. दो सौ साल तक कच्चे तेल की क़ीमत 40 डॉलर प्रति गैलन से कम रही. सवाल यह उठता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि इसकी क़ीमत आसमान छूने लगी. कच्चे तेल की क़ीमत बढ़ने का कारण खपत में वृद्धि नहीं है, बल्कि वायदा कारोबार है. जबसे अमेरिका के उद्योगपति वायदा कारोबार में शामिल हुए, पेट्रोलियम का बाज़ार उनके हाथों बंधक बन गया.

चलिए एक हिसाब लगाते हैं कि आख़िर पेट्रोल की सही क़ीमत क्या हो. जिस समय पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत 112 डॉलर प्रति बैरल थी यानी 5085 रुपये के क़रीब. एक बैरल में 158.76 लीटर होते हैं. तो इसका मतलब है कच्चे तेल की क़ीमत 32 रुपये प्रति लीटर बनती है. तेल कंपनियों के मुताबिक़, कच्चे तेल को रिफाइन करने में 52 पैसा प्रति लीटर खर्च होता है और अगर रिफाइनरी की कैपिटल कॉस्ट को इसमें जोड़ जाए तो तेल की क़ीमत में क़रीब 6 रुपये और जोड़ने पड़ेंगे. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का ख़र्च ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये और डीलरों का कमीशन 1.05 रुपये प्रति लीटर. इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो एक लीटर पेट्रोल की कीमत 45.57 रुपये होती है. लेकिन दिल्ली में 63.4 रुपये, मुंबई में 68.3 रुपये और बंगलुरू में 71 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल बिक रहा है. अब सवाल उठता है कि यह पैसा हम क्यों ख़र्च कर रहे हैं, यह पैसा कहां जा रहा है? इसका जवाब है कि हम टैक्स में दे रहे हैं. यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल से कितना टैक्स वसूलती है. कुछ राज्यों में तो 50 फ़ीसदी से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है. और तो और, यह टैक्स तेल के बेसिक दाम पर लगता है. इसका मतलब यह है कि तेल के दाम बढ़ाने से सरकार को फ़ायदा होता है. फिर सरकार यह घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही है कि तेल कंपनियों को नुक़सान हो रहा है. इस टैक्स को तर्कसंगत करने की ज़रूरत है. इससे सरकारी कंपनियों को फ़ायदा होगा, वरना यही समझा जाएगा कि सरकार निजी कंपनियों को लूट मचाने की खुली छूट दे रही है. सवाल तो यह उठता है कि क्या आज तक मुकेश अंबानी या दूसरी अन्य तेल कंपनियों ने यह कहा कि उन्हें घाटा हो रहा है, तेल कंपनियों को घाटे की वजह से बंद करना पड़ सकता है. हक़ीक़त यह है कि निजी कंपनियां ज़्यादातर माल विदेशी बाज़ार में बेचकर मुनाफ़ा कमा रही हैं. आज अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की जो क़ीमत है, उसके मुताबिक़ पेट्रोल का दाम 35 रुपये प्रति लीटर से एक भी पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत मई 2011 में 112 डॉलर प्रति गैलन थी, जो अब घटकर 90 डॉलर के आसपास हो गई है. आने वाले दिनों में इसकी क़ीमत में और भी गिरावट होने की संभावना है. फिर भी देश में पेट्रोल की क़ीमत गिरने वाली नहीं है. पेट्रोल की क़ीमत में गिरावट तो दूर, तेल कंपनियों के दबाव में सरकार डीजल, केरोसिन और रसोई गैस की क़ीमत भी बढ़ाने को मजबूर हो गई. इसके बाद अगर कोई यह आरोप लगाए कि भारत की सरकार तेल कंपनियों के हाथों की कठपुतली बन गई है तो इसका क्या जवाब होगा. इसके बावजूद बड़ी निर्लज्जता से यह दलील भी जाती है कि तेल कंपनियों को नुक़सान हो रहा है, ताकि कोई सरकार के फ़ैसले पर सवाल न खड़ा कर सके. तो क्या सरकार ने तेल कंपनियों को हुआ घाटा पूरा करने के लिए पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया?

सवाल सिर्फ़ क़ीमत बढ़ाने के फ़ैसले का नहीं है. अगर केंद्र सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में सोचती है तो सबसे पहले उसे पेट्रोलियम मंत्रालय को दुरुस्त करना होगा. देश में पेट्रोल, केरोसिन और डीजल का कारोबार माफ़िया चलाते हैं. सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि तेल की चोरी और कालाबाज़ारी की वजह से हर साल 70,000 करोड़ रुपये का नुक़सान होता है, उसे ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया है. यह सवाल इसलिए उठाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में तेल माफ़िया ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज़िंदा जला दिया था. तेल की सप्लाई से लेकर पेट्रोल पंप के आवंटन तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने क्या किया है. क्या तेल माफ़िया इसलिए बेलगाम हैं, क्योंकि उन्हें नेताओं का संरक्षण हासिल है. या यूं कहें कि सरकार इसलिए ख़ामोश है, क्योंकि तेल के कारोबार पर देश के राजनीतिक नेताओं का कंट्रोल है. तेल की क़ीमत बढ़ाने से पहले सरकार को इस सेक्टर में मौजूद कालाबाज़ारी को ख़त्म करने की पहल करनी चाहिए.

पेट्रोल और डीजल का महंगाई से गहरा रिश्ता है. इनके दाम बढ़ते ही ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाती है, जिससे सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं. जब देश में पेट्रोलियम का उदारीकरण हुआ तो उस वक़्त देश पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा था. ऐसे समय में उदारीकरण करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है, अर्थशास्त्र के सारे तर्क भी झुठला देता है. जबसे कच्चा तेल वायदा कारोबारियों की गिरफ्त में आया, तबसे इसकी क़ीमत में भूचाल आ गया, इसकी क़ीमत में कभी स्थिरता नहीं आई. यह अपने आप में एक वजह है कि पेट्रोलियम के उदारीकरण को लागू न किया जाए. लेकिन सरकार पर तेल कंपनियों का, ख़ासकर निजी कंपनियों का दबाव था. सरकार ने नया तरीक़ा निकाला, उसने रंगराजन कमेटी बना दी. इस कमेटी से सरकार को उम्मीद थी कि यह पेट्रोलियम की क़ीमतों और करों के उदारीकरण का सुझाव देगी, लेकिन रंगराजन कमेटी ने उदारीकरण की सलाह नहीं दी. सरकार ने दूसरी कमेटी बना दी. इस बार योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख को एक्सपर्ट ग्रुप का प्रमुख बनाया गया. इस बार उदारीकरण का सुझाव दिया गया. सरकार ने तुरंत इस सुझाव को मान लिया. सरकार की तरफ़ से दलील दी गई कि तेल कंपनियों को नुक़सान हो रहा है, इसलिए पेट्रोल के दाम को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ना ज़रूरी हो गया है. अब सवाल यह है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया. सबसे सीधा जवाब तो यही है कि सरकार ने जनता को राहत देने के बजाय निजी तेल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना उचित समझा. ख़ासकर उन निजी तेल कंपनियों को, जिन्हें पेट्रोलियम सेक्टर में घुसने और विस्तार करने का हर मौक़ा दिया गया. सरकार की क्या मजबूरी है कि तेल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना उसने अपना परम कर्तव्य मान लिया है?

देश की सरकार वर्ल्ड बैंक के इशारे पर काम करने में कोई गुरेज़ नहीं करती, लेकिन उसकी ग़रीबी रेखा की परिभाषा को नहीं मानती. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक़, जिस आदमी की रोज़ाना आमदनी एक डॉलर से कम है, उसे ग़रीबी रेखा के नीचे माना जाए. एक डॉलर का मतलब 42 रुपये के लगभग की आमदनी. इस परिभाषा के मुताबिक़ भारत के 75 फ़ीसदी लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका ज़्यादातर पैसा ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी भोजन पर ख़र्च होता है. भारत सरकार तो अर्थशास्त्रियों की सरकार है. ग़रीब जनता पर जब महंगाई की मार पड़ती है तो वह क्या करे, कैसे ज़िंदा रहे? दाम बढ़ाने से पहले सरकार को भारत के इन 75 फ़ीसदी लोगों की परेशानी नज़र नहीं आई. भारत में महंगाई दर 9.06 फ़ीसदी है, जो अमेरिका की तुलना में दोगुनी है और जर्मनी से चार गुनी. इसी महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, वह केवल किसी तरह अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर है. डीजल और केरोसिन के दाम बढ़ते ही देश की ग़रीब जनता में हाहाकार मच जाता है. क्या सरकार को यह पता नहीं है कि देश के 75 फ़ीसदी लोगों का 80 फ़ीसदी ख़र्च सिर्फ़ खाने-पीने पर होता है. सरकार ने तेल की क़ीमत बढ़ाकर जनता को महंगाई की मार झेलने के लिए बेसहारा छोड़ दिया है. सरकार अगर महंगाई से लड़ना चाहती है तो हर सरकारी विभाग को एक समग्र योजना पर काम करना होगा. सबसे पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा. तेल के उत्पादन और वितरण में पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है. समस्या यह है कि सरकार भ्रष्टाचार, राजनीति और उद्योग के भंवर में फंस गई है. अपनी ग़लतियों की वजह से वह इस तरह फंसी है, जैसे कोई मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है. वह जितना हाथ-पैर चलाती है, मुश्किल उतनी ही बढ़ जाती है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 18
दिल्ली, 11 जुलाई -17 जुलाई 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के -2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/011-23418962
0120-6450888, 0120-6452888
0120-6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120-4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4+4+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

किसान के लिए ज़मीन सिर्फ़ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं होती. ज़मीन किसान की पहचान है, ज़मीन किसान के जीने का सहारा है, शायद इसीलिए मथुरा से दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे बुद्ध सिंह ज़मीन को धरती मां कह रहे हैं.

सभी फोटो– प्रभात पाण्डेय

किसान आंदोलन
चौथी दुनिया और सुप्रीम कोर्ट

शशि शेखर

वर्तमान हालात में जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता का स्वरूप क्या हो सकता है? इसकी एक मिसाल चौथी दुनिया की उन रिपोर्टों में देखने को मिलती है, जो देश भर में चल रही जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई से संबंधित हैं. दरअसल, पिछले दो सालों के दौरान लिखी गईं उक्त रिपोर्ट्स आने वाले समय में समस्याओं की चेतावनी दे रही थीं. पहले शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसान, मज़दूर और आदिवासी जब दिल्ली आए, तब भी चौथी दुनिया ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि अगर इस तरह के शांतिपूर्ण आंदोलनों की मांग सरकार जल्द से जल्द नहीं मानेगी तो फिर इसे संभालना मुश्किल हो सकता है. चौथी दुनिया ने पिछले दो सालों के दौरान अपनी रिपोर्ट्स में हमेशा इस बात का ज़िक्र किया कि सवा सौ साल पुराने भूमि अधिग्रहण क़ानून को बदलने की ज़रूरत है. लेकिन इस पर बहस तब शुरू हुई, जब अलीगढ़, मथुरा, आगरा, नोएडा, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या कहें कि पूरे देश के किसान जबरन भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ सड़क पर उतर आए. पुलिसिया डंडा चला, गोली चली, लाशों पर राजनीति शुरू हुई.

बहरहाल, चौथी दुनिया सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सथाशिवम एवं न्यायमूर्ति ए के पटनायक को धन्यवाद देता है. भूमि अधिग्रहण के मसले पर इन माननीय न्यायाधीशों की टिप्पणी से चौथी दुनिया की उन रिपोर्ट्स की सत्यता की ही पुष्टि होती है, जिनमें यह साफ-साफ लिखा गया था कि सरकार प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है. उन रिपोर्ट्स को बल मिलता है, जिनमें ये सवाल उठाए गए थे कि आख़िर यह भूमि अधिग्रहण किसके हित में हो रहा है और इस देश में और कितने सिंगुर और नंदीग्राम बनेंगे. दरअसल, भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी सथाशिवम एवं न्यायमूर्ति ए के पटनायक ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अब देश को और नंदीग्राम नहीं चाहिए. नोएडा को नंदीग्राम नहीं बनने देंगे. सरकारें किसानों की कृषि योग्य ज़मीन बिल्डरों को देती रहे और हम आंखें मूंदे बैठे रहें, अब ऐसा नहीं होगा. पीठ ने कहा कि हम आंखें मूंद कर बैठे नहीं रहेंगे. आप एक पक्ष से खेती लायक़ ज़मीन लेकर दूसरे को दे देते हैं, यह ख़त्म होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें इसमें दख़ल देना पड़ेगा. यह एकपक्षीय विकास है. पीठ ने सवाल किया कि इस जमीन पर बनने वाले मकान किसके फ़ायदे के लिए हैं, इन्हें कौन बना रहा है, इनकी क़ीमत क्या है? कोर्ट ने खेतिहर ज़मीन के अधिग्रहण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सरकार के पास और कोई बंजर ज़मीन नहीं थी.

ज़ाहिर है, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इस देश में सवा सौ साल से चले आ रहे काले क़ानून (भूमि अधिग्रहण क़ानून) की प्रासंगिकता पर भी कई सवाल खड़े करती है? इस टिप्पणी से जो एक बात साफ-साफ ज़ाहिर होती है, वह यह कि राज्य सरकारें इसी काले क़ानून की आड़ में किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती ले रही हैं. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि ऐसे अधिग्रहण सरकारी कार्यों के लिए कम, निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अधिक हो रहे हैं. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में उम्मीद की एक किरण ज़रूर दिख रही है. एक ऐसी किरण, जो किसानों के जीवन को अंधेरे में डूबने से बचा सकती है. हम सब को भी विश्वास रखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि उम्मीद की यह किरण और प्रखर हो.

हमने कब, क्या कहा

पिछले दो सालों के दौरान चौथी दुनिया ने जल, जंगल और ज़मीन के लिए देश भर में चल रहे आंदोलनों को प्रमुखता से प्रकाशित किया. इनमें उन मुद्दों को उठाया गया था, जिनकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी भी करती है. चौथी दुनिया की कुछ ऐसी ही चुनिंदा ख़बरें:

यह विद्रोह की आहट है
अगस्त, 2010

पंद्रह अगस्त के दिन हमारे देश के हर शहर में जश्न मनाया जा रहा था. उधर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, महामायानगर और गौतमबुद्ध नगर में तिरंगे की जगह किसान हाथ में लाठी लेकर पुलिस-प्रशासन से जूझ रहे थे. पुलिस की लाठियां खा रहे थे, गोलियों का सामना कर रहे थे. किसान भूमि अधिग्रहण से इतने नाराज़ हैं कि अलीगढ़ की आग पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई. बलिया से लेकर वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और इलाहाबाद में भी किसान भूमि अधिग्रहण से नाराज़ हैं. फ़िरोज़ाबाद में 1775 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण के ख़िलाफ़ 29 गांवों के किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसान आंदोलन विद्रोह का रूप ले रहा है और उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बन गया है.

किसान आंदोलन : ज़मीन जाएगी तो नक्सली बनेंगे
सितंबर, 2010

किसान के लिए ज़मीन सिर्फ़ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं होती. ज़मीन किसान की पहचान है, ज़मीन किसान के जीने का सहारा है, शायद इसीलिए मथुरा से दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे बुद्ध सिंह ज़मीन को धरती मां कह रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार बुद्ध सिंह की 20 बीघा ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती है, हाईटेक सिटी बनाने के लिए. बुद्ध सिंह के साथ आए कई किसान यह भी कह रहे थे कि अगर सरकार ज़बरदस्ती ज़मीन पर क़ब्ज़ा करती है तो उनके पास नक्सली बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा.

सरकार प्रॉपर्टी डीलर बन गई है
सितंबर, 2010

किसान आंदोलन की यह आग आगरा, मथुरा और अलीगढ़ के रास्ते पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गई. किसानों के इस उग्र विरोध के पीछे सरकार का अक्खड़ रवैया है, जो 10,000 करोड़ रुपये के यमुना एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट के लिए उनकी ज़मीनों को औने-पौने दामों पर अधिग्रहीत करना चाहती है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है. अलीगढ़, मथुरा और आगरा क्षेत्र के किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने के बाद यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नया दौर शुरू होने वाला है.

यह गूजर नहीं, किसान आंदोलन है
जनवरी, 2011

गूजरों का आंदोलन कोई आकस्मिक आंदोलन नहीं है. वे किसी हत्याकांड के विरोध में आंदोलन नहीं कर रहे हैं. गूजर कई सालों से रोज़ी-रोटी के सवाल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. यह आंदोलन दिल्ली से सटे इलाक़ों और राजस्थान में फैला है. गूजरों की मांग यह है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण. अब सवाल यह है कि गूजर अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर सरकारी नौकरियां करना क्यों चाहते हैं.

एक और किसान आंदोलन
फरवरी, 2011

फ़िरोज़ाबाद रोड स्थित वायुसेना कैंप के निकट वायुसेना की यूनिट खोलने के लिए टूंडला ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायतों पचोखरा, देवखेड़ा, छिकाऊ, हिम्मतपुर और गढ़ी हरराय की 1785 एकड़ यानी 10 हज़ार बीघा ज़मीन अधिग्रहीत की जाएगी. इन पंचायतों के अंतर्गत 29 गांव आते हैं, जिनकी कुल आबादी 85 हज़ार है. सबसे अधिक पचोखरा पंचायत प्रभावित होगी, जिसकी 1475 एकड़ उपजाऊ भूमि अधिग्रहीत होगी. इस ख़बर से क्षेत्र के किसानों में खलबली मच गई है, लेकिन वे संगठित हैं. उनका कहना है कि वे अपनी जान दे देंगे, पर भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे.

एकता परिषद : इस चेतावनी को सिर्फ़ रैली न समझें
मार्च, 2011

वर्ष 2007 में जब 25 हज़ार लोग ग्वालियर से पैदल चलकर दिल्ली आए, तब तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया. 2009 में जब एक बार फिर ये लोग दिल्ली आए, तब भी इन्हें आश्वासन ही मिला. नतीजतन, इस बार 15 हज़ार लोग जब दिल्ली आए, तो सिर्फ़ चेतावनी देने. चेतावनी इस बात की कि अगर नई भूमि सुधार नीतियों का पालन ठीक से नहीं किया गया, अगर नेशनल लैंड रिफॉर्म काउंसिल को सक्रिय नहीं किया गया तो हम लाखों की संख्या में दिल्ली आकर बैठ जाएंगे.

सिर्फ़ नोएडा नहीं, पूरे देश में किसान हिंसक हो सकते हैं
मई, 2011

सरकार भूमि अधिग्रहण से संबंधित सवा सौ साल पुराने क़ानून में संशोधन की दिशा में कोई क़दम नहीं उठाती और राहुल गांधी उसी क़ानून के तहत होने वाले भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हैं. भट्टा-पारसौल में भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे किसानों पर फायरिंग होती है. अगर राहुल गांधी किसानों के सच्चे हितैषी होते तो गांव भट्टा जाने के बजाय वह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय जाते और भूमि अधिग्रहण क़ानून के संशोधित विधेयक को पारित कराते, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया.

पूर्वांचल : जान देंगे, ज़मीन नहीं
जून, 2011

भट्टा-पारसौल में भूमि अधिग्रहण मामले की आग ठंडी भी नहीं हो पाई थी और सरकारी नुमाइंदे पूर्वांचल के चंदौली ज़िले के कटेसर और कोडोपुर गांव में ज़मीन अधिग्रहण के लिए पहुंच गए. पुरखों की ज़मीन हाथ से जाते देख किसान सड़क पर उतर आए. कटेसर के किसान रामलखन की पूरी चार बीघा ज़मीन जा रही थी. विरोध स्वरूप वह एक चिता पर बैठ गए और बोले, जान दे दूंगा, लेकिन ज़मीन देकर अपने हाथ-पैर नहीं कटाऊंगा.

मेवात किसान आंदोलन
जुलाई, 2011

हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (रोजका) बनाने के नाम पर मेवात के किसानों से 1600 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया है, लेकिन किसानों का मानना है कि उन्हें अपेक्षाकृत बहुत ही कम मुआवज़ा दिया जा रहा है और अब ये किसान इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई महीने से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. बहरहाल, यह लड़ाई हरियाणा से चलकर दिल्ली तक पहुंच गई है. 16 जून को हज़ारों मेवाती किसान, महिलाएं जंतर-मंतर पहुंचे. इस उम्मीद में कि वह राहुल गांधी उनकी बात को सुनेंगे, जो भट्टा-पारसौल में जाकर किसानों के दर्द पर मरहम लगाते हैं.

shashishekhar@chauthiduniya.com

समाचार चैनल आईबीएन-7 के दो पत्रकारों के साथ कथित रूप से हुए दुर्व्यवहार के मामले को संज्ञान में लेते हुए गिल्ड ने मायावती से सभी ज़रूरी क़दम उठाने के लिए कहा है.

उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमला

सच कहने की सज़ा

अजय कुमार

मायावती सरकार और उसके नुमाइंदों ने हर उस आवाज़ को कुचल देने की कसम खाई है, जो मुख्यमंत्री मायावती या उनके राजकाज के ख़िलाफ़ उठाई गई हो. विरोधियों पर लाठी-डंडों की बौछार और व्यापारियों का उत्पीड़न करने, क़ानून के रक्षकों एवं शिक्षा मित्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने वाले मायावती के कथित गुर्गों का निशाना अबकी बार मीडिया बना. डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सचान की हत्या को मौत साबित करने में लगे शासन-प्रशासन को जब यह लगा कि मीडिया के कारण सच का पर्दाफाश हो सकता है तो पुलिस द्वारा उसकी आवाज़ दबाने की मुहिम चला दी गई, लेकिन पत्रकारों की एकजुटता के सामने सरकार को झुकना पड़ा. मामला इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े एक पत्रकार का था, जिसे सिर्फ़ इसलिए पुलिस के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, क्योंकि वह डॉक्टर सचान हत्याकांड की सच्चाई बेबाक होकर दिखा रहा था. बताया जाता है कि सीएमओ बी पी सिंह की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी डिप्टी सीएमओ वाई एस सचान की बीते 22 जून को ज़िला जेल अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के बारे में इस समाचार चैनल की रिपोर्टिंग कथित तौर पर सरकार के लिए असुविधाजनक थी. विपक्ष के दबाव और भारी फ़ज़ीहत के बाद राज्य सरकार को झुकना पड़ा और लखनऊ में इस समाचार चैनल के ब्यूरो प्रमुख के साथ कथित रूप से मारपीट करने के आरोप में दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया.

यह मुक़दमा समाचार चैनल आईबीएन-7 के ब्यूरो प्रमुख शलभ मणि त्रिपाठी ने राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में अपर पुलिस अधीक्षक बी पी अशोक और क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार के ख़िलाफ़ भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 342 (अवैध तरीक़े से बंधक बनाना), 504 (जानबूझ कर अपमान करना) और 506 (डराना-धमकाना) के तहत दर्ज कराया. ग़ौरतलब है कि पुलिस अफसरों बी पी अशोक और अनूप कुमार ने शलभ मणि को बीते 26 जून को उनके कार्यालय के पास से कथित तौर पर जबरन उठवा लिया था और उनके साथ बदसलूकी तथा मारपीट की थी. पुलिस ने त्रिपाठी के सहयोगी मनोज राजन को भी पकड़ने की कोशिश की थी. इस घटना से नाराज़ पत्रकारों ने मुख्यमंत्री मायावती के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था. बाद में मुख्यमंत्री के सचिव नवनीत सहगल ने दोनों आरोपी पुलिस अधिकारियों के निलंबन की घोषणा करते हुए शलभ मणि से इन अफसरों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराने के लिए कहा. सहगल ने पत्रकारों को बताया कि दोनों पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ त्रिपाठी की शिकायत के आधार पर जांच कराई जाएगी. पत्रकारों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ़ त्रिपाठी के साथ धक्कामुक्की की, बल्कि उनके सहयोगी को पीटा और ज़बरदस्ती उन्हें थाने ले गए. उनका आरोप है कि पुलिस ने त्रिपाठी को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी. घटना के विरोध में राजधानी के पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री मायावती के सरकारी आवास के पास प्रदर्शन किया तो बाद में त्रिपाठी को छोड़ दिया गया. पत्रकारों के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से लेकर दिल्ली तक में धरना-प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया.

29 जून को लखनऊ में पत्रकारों ने जोरदार तरीक़े से प्रदर्शन करके मांग की कि जिस तरह की कार्रवाई सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वालों के साथ की जाती है, वैसी ही कार्रवाई पत्रकारों के काम में बाधा पहुंचाने वालों के साथ भी होनी चाहिए. पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब से जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक एक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया. इनमें प्रमुख रूप से राम दत्त त्रिपाठी, शरत प्रधान, योगेश मिश्रा, अजय कुमार, सुनील दूबे, हसीब सिद्दीकी, मुदित माथुर, अनूप श्रीवास्तव एवं संजय सक्सेना आदि मौजूद थे. पत्रकारों ने ज़िला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा. इसके साथ ही पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल बी एल जोशी से भी मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया.

उधर गिल्ड ने अपने एक बयान में कहा कि आईबीएन-7 के दो पत्रकारों शलभ मणि त्रिपाठी और मनोज राजन को कथित रूप से इसलिए पुलिस का दुर्व्यवहार झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने लखनऊ जेल के अस्पताल में मुख्य सहायक चिकित्सा अधिकारी वाई एस सचान की हत्या के पीछे की साजिश का ख़ुलासा करने में मदद की थी. गिल्ड के अध्यक्ष टी एन नेनन और सचिव कूमी कपूर ने अपने बयान में कहा कि उक्त पत्रकार लखनऊ पुलिस की ओर से उनके ख़िलाफ़ दर्ज झूठे मामलों से इसलिए बच पाए, क्योंकि उनमें से एक पत्रकार पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब रहा और शहर के पूरे मीडिया समूह ने ग़लत गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया. इसके साथ ही गिल्ड ने मायावती सरकार द्वारा दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के क़दम का स्वागत किया. ये पुलिसकर्मी इन दोनों पत्रकारों को गिरफ़्तार करने और धमकी देने के लिए ज़िम्मेदार थे. गिल्ड ने इस बात पर चिंता जताई कि राज्य में मीडिया का पुलिस उत्पीड़न बहुत आम बात हो गया है. एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने मुख्यमंत्री मायावती को पत्र लिखकर उनके शासन-प्रशासन की ओर से पत्रकारों के ख़िलाफ़ बढ़ रहे धमकी, भय और हिंसा के मामलों पर अपना विरोध जताया है. समाचार चैनल आईबीएन-7 के उक्त दो पत्रकारों के साथ कथित रूप से हुए दुर्व्यवहार के मामले को संज्ञान में लेते हुए गिल्ड ने मायावती से सभी ज़रूरी क़दम उठाने के लिए कहा है, ताकि राज्य में मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके.

इस संदर्भ में लखनऊ सचिवालय एनेक्सी स्थित मीडिया सेंटर में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति की एक आपात बैठक हुई. समिति के अध्यक्ष हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी ने पत्रकार शलभ मणि एवं मनोज राजन के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई अभद्रता को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग सरकार से की गई. साथ ही यह भी कहा गया कि यदि पत्रकारों के साथ कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी आगे से ऐसी हरकत करे तो उसके ख़िलाफ़ तुरंत सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए. बैठक में समिति के उपाध्यक्ष मुदित माथुर, सचिव डॉ. योगेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष रामदत्त त्रिपाठी, प्रमोद गोस्वामी एवं उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकर गोस्वामी आदि मौजूद थे.

feedback@chauthiduniya.com

सभी फोटो-अजय भल्ला

पुलिस का असली चेहरा

उत्तर प्रदेश पुलिस लाठी और गोली के बल पर सबका मुंह बंद करने की महारथ रखती है. गुनाहगारों की तारणहार और बेगुनाहों के लिए भस्मासुर की तरह काम करने वाली राज्य पुलिस अपने कारनामों से अक्सर चर्चा में रहती है. यही वजह है कि उसके ख़िलाफ़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सर्वाधिक शिकायतें मिली हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010-11 में आयोग को उत्तर प्रदेश पुलिस के ख़िलाफ़ 8,768 शिकायतें मिलीं. इनमें हिरासत में मौत, प्रताड़ना, अत्याचार, फर्जी मुठभेड़ और क़ानूनी कार्रवाई करने में नाकामी जैसे मामले सबसे अधिक हैं.

हर तरफ़ भर्त्सना

प्रदेश में पत्रकारों पर हमले की चारों तरफ़ निंदा हो रही है. विभिन्न सामाजिक एवं मज़दूर संगठनों और विपक्षी दलों ने मीडियाकर्मियों पर पुलिस के हमले को कलंक बताया. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मीडियाकर्मियों पर हमले से यह ज़ाहिर होता है कि राज्य में अब कोई भी शख्स सुरक्षित नहीं है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वारदात में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. सपा-लोकदल ने भी इसे गंभीर घटना बताते हुए मायावती सरकार से सूबे के पत्रकारों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की मांग की, ताकि वे अपना काम निर्भीकता के साथ कर सकें. समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो पुलिस अफसरों द्वारा पत्रकारों के साथ कथित मारपीट की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों को निलंबित नहीं, बल्कि बर्ख़ास्त किया जाना चाहिए. यादव ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों की जांच कराई जाएगी और इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. उन्होंने प्रदेश में क़ानून व्यवस्था ख़राब होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह राज्यपाल बी एल जोशी को पत्र लिखकर मायावती सरकार को बर्ख़ास्त करने की मांग करेंगे. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता एवं महासचिव सुबोध श्रीवास्तव ने लोकतंत्र के चौथे खंभे पर खाकी के हमले को सत्ता पक्ष का तानाशाही रवैया बताते हुए कहा कि बिना सरकार की मर्जी के कोई अधिकारी मीडिया से लड़ने की कोशिश नहीं करेगा. जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए पुलिस से अधिक मायावती सरकार ज़िम्मेदार है.

पंचायत चुनाव में कश्मीर के ग्रामीणों का बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना यह भी साबित करता है कि वे अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, जहां कम से कम उन्हें बुनियादी सुविधाएं तो मयस्सर हो सकें.

पूर्णिया उपचुनाव

विपक्ष का ग़ुरूर चकनाचूर

सरोज सिंह

पूर्णिया उपचुनाव में विपक्ष के नेताओं ने यह साबित कर दिया कि वे सुधरने वाले नहीं हैं. विधानसभा चुनाव में पस्त हो चुके लालू प्रसाद एवं राम विलास पासवान का अहंकार उन्हें अगर आने वाले समय में राजनीतिक हाशिए पर डाल दे तो कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि लगता है, उन्होंने आपस में ही लड़ने की कसम खा ली है.

पूर्णिया उपचुनाव में दम और दिमाग की अग्नि परीक्षा में बिहार का विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया. किरण केसरी की जीत ने एक बार फिर यह साबित किया कि एनडीए सूबे में बेहतर तालमेल के साथ अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रहा है, जबकि विपक्ष विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खाने के छह महीने बाद भी सबक सीखने को तैयार नहीं है. छूच्छे नवाबी का शौक रखने वाला विपक्ष पूर्णिया में अपने ही जाल में ऐसा फंसा कि उसे भाजपा से लड़ने की फुर्सत ही नहीं मिली. नतीजा किरण केसरी अपने पति राज किशोर केसरी से भी ज़्यादा मतों से बहुत ही आसानी के साथ चुनाव जीत गईं और विपक्ष के कागजी शेर हाथ मलते रह गए.

राजद एवं लोजपा की आंतरिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि किसी भी समय वहां विद्रोह का बिगुल फूंका जा सकता है. लालू प्रसाद अगर इसी तरह दिल्ली में जमे रहे तो राजद का विभाजन टालना मुश्किल हो जाएगा. बताया जाता है कि राजद के दो तिहाई विधायक जदयू के संपर्क में हैं, लोजपा में भी इसी तरह के हालात हैं, लेकिन इन पार्टियों के सुप्रीमो हैं कि सच्चाई देखने को तैयार ही नहीं हैं.

दरअसल, पूर्णिया भाजपा की परंपरागत सीट रही है, पर विपक्षी नेताओं ने वहां उसकी ताकत को आंकने में एक बार फिर गलती कर दी. सारा जोर इस बात पर रहा कि विपक्ष का अगुवा कौन रहेगा. भाजपा कैसे हारेगी, यह मसला गौण हो गया. नतीजा यह हुआ कि भाजपा की किरण केसरी 23 हजार मतों से जीत गईं और कांग्रेस के राम चरित्र यादव को पिछले चुनाव की तुलना में आठ हजार और माकपा के अमित सरकार को पिछले चुनाव की तुलना में पांच हजार वोट कम मिले. गुरूर में चूर विपक्षी नेता यहां जानबूझ कर गलती पर गलती करते चले गए और भाजपा को खुला मैदान मिलता चला गया. राज किशोर केसरी की हत्या के कारण हुए इस उपचुनाव में विपक्ष शुरू से ही बंटा हुआ दिखा. अमित सरकार के न चाहते हुए भी दबाव में डालकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया.

दिल्ली और पटना की राजनीति चाहे जो मांग करती हो, पर पूर्णिया में एक मजबूत साझा विपक्षी प्रत्याशी की मांग

थी, पर ऐसा नहीं हो पाया. ठीक उसके बाद ठसक में चूर लालू प्रसाद ने माकपा को अपना समर्थन दे दिया, जबकि बात यह तय हुई थी कि अंतिम समय में जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा, उसे राजद और लोजपा का समर्थन मिलेगा. बात से हमेशा मुकर जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली की राजनीति के मद्देनजर माकपा को अपना समर्थन दे दिया. तर्क यह दिया गया कि राजद धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करना चाहता है. राजद के इस एकतरफा फैसले के बाद लोजपा ने भी अपनी राजनीतिक सहूलियत को देखते हुए कांग्रेस को अपने समर्थन की घोषणा कर दी. पूर्णिया में हाल यह हो गया कि भाजपा से लड़ने के बजाय कांग्रेस और माकपा ही एक-दूसरे के खिलाफ लड़ती नजर आईं. होड़ इस बात की लग गई कि कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, ताकि जनता को यह बताया जाए कि हमने जिसे समर्थन दिया, वह भले ही न जीत पाया हो, पर कम से कम वह दूसरे नंबर पर रहा, यानी विकल्प तो हम ही हैं.

जनता पर अपनी तथाकथित पकड़ का गुरूर इतना दिखा कि न तो लालू प्रसाद यादव और न राम विलास पासवान ने इस उपचुनाव में प्रचार किया, जबकि एनडीए की तरफ से खुद नीतीश कुमार और सुशील मोदी पूर्णिया गए. यह इस बात को बताता है कि एनडीए बिहार में अपनी चुनावी चुनौती को कितनी गंभीरता से लेता है, जबकि आरजेडी और लोजपा अपनी पुरानी लाइन को पीटती रह जाती हैं. नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष वोटों के बिखराव के कारण हम चुनाव हारे. अब कोई यह पूछे कि इस बिखराव के लिए उनसे किस डॉक्टर ने बोला था. विधानसभा चुनाव में लगभग समाप्त हो चुके इन विपक्षी नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जान-बूझकर गलती पर गलती करके वे अपनी अंतिम सांस भी खत्म कर रहे हैं. सूबे की जनता नए तरीके से चीजों को देख और समझ रही है, पर लालू प्रसाद यादव एवं राम विलास पासवान जैसे नेता बदलने को तैयार नहीं हैं. मतलब साफ है कि वे किसी नए विकल्प का रास्ता तैयार कर रहे हैं.

राजद एवं लोजपा की आंतरिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि किसी भी समय वहां विद्रोह का बिगुल फूंका जा सकता है. लालू प्रसाद अगर इसी तरह दिल्ली में जमे रहे तो राजद का विभाजन टालना मुश्किल हो जाएगा. बताया जाता है कि राजद के दो तिहाई विधायक जदयू के संपर्क में हैं, लोजपा में भी इसी तरह के हालात हैं, लेकिन इन पार्टियों के सुप्रीमो हैं कि सच्चाई देखने को तैयार ही नहीं हैं. बिहार की जनता बीस तरह की समस्याओं से जूझ रही है, पर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने से भाग रहा है. कांग्रेसी नेताओं ने तो और भी हद कर दी. सदानंद सिंह का बयान आया कि कांग्रेस को किसी के भी समर्थन की जरूरत नहीं है. उनके इस बयान से भी विपक्षी एकता का शीशा टूटा. दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता यह नहीं चाहते थे कि राम चरित्र यादव यहां से चुनाव जीतें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर यह हुआ तो एक बार फिर रंजीता रंजन एवं पप्पू यादव का सितारा बुलंद हो जाएगा.

यही वजह रही कि कांग्रेस प्रत्याशी को कई जगहों पर विश्वासघात का भी सामना करना पड़ा. चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस बिखरी-बिखरी नजर आई, जबकि भाजपा का चुनाव प्रचार पूरी तरह संगठित था. इसी कारण भाजपा को इस बार ग्रामीण इलाकों में भी काफी वोट मिले. किरण केसरी शहरी क्षेत्र में 19 हजार और ग्रामीण क्षेत्र में चार हजार वोट से आगे रहीं, जबकि पिछले चुनाव में राज किशोर केसरी ग्रामीण इलाके में पिछड़ गए थे. दरअसल, भाजपा ने चुनाव से दो महीने पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और अपनी सारी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त कर लिया था. कहा जाए तो पूर्णिया का उपचुनाव विपक्ष के लिए एकजुट होने का एक सुनहरा मौका था, जिसे गंवा दिया गया. हम बड़े कि हम बड़े जैसी प्रवृत्ति ने इन नेताओं को बिहार में इतना बौना बना दिया है कि जनता के सामने अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है. कहा जाता है कि ऐसी ही परिस्थिति में एक नया विकल्प बनता है और पुराने चेहरे भुला दिए जाते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

जम्मू-कश्मीर

पंचायत चुनाव ने उम्मीद जगाई

हाल में जम्मू-कश्मीर में संपन्न हुए पंचायत चुनाव से राज्य में एक नई बयार देखने को मिली. बड़ी तादाद में घरों से निकल कर लोगों ने मतदान करके न सिर्फ़ लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की, बल्कि चुनाव बहिष्कार करने वालों को स्पष्ट संकेत भी दे दिया. इस चुनाव में सबसे ख़ास बात यह रही कि पंच और सरपंच समेत कई पदों पर नौजवान उम्मीदवार चुने गए, जो राज्य में नई पीढ़ी की बदलती सोच को दर्शाता है. शांतिपूर्ण चुनाव और राज्य के लोगों की बढ़-चढ़कर भागीदारी इस बात का स्पष्ट इशारा है कि कश्मीर की फ़िज़ा में बदलाव आ रहा है. भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती राज्य की जनता की उन उम्मीदों पर खरा उतरना है, जो उसने नवगठित पंचायतों एवं प्रतिनिधियों से लगाई है.

कश्मीर में आज भी ऐसे कई इलाक़े हैं, जहां विकास का नामोनिशान तक नहीं है. अगर कुछ है तो पिछले दो दशकों से राज्य में चल रही आतंकवाद की मनहूस छाया, जिसने हज़ारों मासूमों की जान ले ली और कइयों के सुहाग उजाड़ दिए. कश्मीर के कुछ ऐसे भी गांव हैं, जहां पुरुष आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं और गांव में रह गईं उनकी विधवाएं और मासूम बच्चे. सीमावर्ती इलाक़ा कुपवाड़ा से तक़रीबन 25 किलोमीटर दूर करालपुरा ब्लॉक का ऐसा ही एक गांव हैं दर्दपुरा. पहाड़ों के बीच बसा तक़रीबन दस हज़ार की आबादी वाला यह गांव जितना ख़ूबसूरत है, इसकी वास्तविकता उतनी ही भयानक है. जम्मू-कश्मीर में जब आतंकवाद की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान सीमा से सटे होने की वजह से इस गांव को घुसपैठ के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे रोकने के लिए सुरक्षाबलों ने गांव में अपना डेरा डाल दिया. सरहद पार से घुसपैठ की कोशिश और सुरक्षाबलों द्वारा रोकने के लिए चलाई गई गोलियों ने दर्दपुरा के कई नौजवानों को मौत के मुंह में धकेल दिया तो कई लोग बारूदी सुरंग के शिकार होकर विकलांग हो गए. अपनों को खोने का गम और विकलांगता ने उनकी ज़िंदगी को बोझ बना दिया. ऐसे समय में राजनीतिक दलों की उपेक्षा और विकासात्मक परियोजनाओं के अभाव ने दर्दपुरा के लोगों के ज़ख्मों को और भी गहरा कर दिया. यही वजह है कि इस गांव में बुनियादी सुविधाओं का हमेशा अभाव रहा है. टूटी-फूटी सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने दर्दपुरा के लोगों को अपनों के बीच अजनबी बना दिया. इलाज के लिए गांव में कोई सरकारी अस्पताल तक नहीं है. बीमारों की जान बचाने के लिए करालपुरा या फिर कुपवाड़ा तक जाना पड़ता है. इस दूरी को तय करने के लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था तक नहीं है. अगर कहीं से इंतज़ाम कर भी लिया तो सड़कें इस कदर खस्ताहाल हैं कि मरीज़ वक़्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं.

कश्मीर में आज भी ऐसे कई इलाक़े हैं, जहां विकास का नामोनिशान तक नहीं है. अगर कुछ है तो पिछले दो दशकों से राज्य में चल रही आतंकवाद की मनहूस छाया, जिसने हज़ारों मासूमों की जान ले ली और कइयों के सुहाग उजाड़ दिए. कश्मीर के कुछ ऐसे भी गांव हैं, जहां पुरुष आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं और गांव में रह गईं उनकी विधवाएं और मासूम बच्चे. सीमावर्ती इलाक़ा कुपवाड़ा से तक़रीबन 25 किलोमीटर दूर करालपुरा ब्लॉक का ऐसा ही एक गांव हैं दर्दपुरा.

कुछ ऐसा ही हाल जन वितरण प्रणाली का है. ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की यह सरकारी योजना दर्दपुरा तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ती नज़र आती है. पहाड़ी क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली सालों से बंद पड़ी है और लोगों को राशन लाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है. बर्फबारी के दौरान जब दर्दपुरा के अधिकतर हिस्से देश के अन्य भागों से कट जाते हैं तो ऐसे में वहां के लोग किस तरह गुजारा करते होंगे, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है. इस संबंध में वहां के नौजवान सरपंच गुलाम मोहीउद्दीन का तर्क है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए कई परियोजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन तालमेल की कमी की वजह से उनमें से अधिकतर परियोजनाएं काग़ज़ों तक सिमट कर रह जाती हैं. इस संबंध में आला सरकारी अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन मामला आज भी जस का तस बना हुआ है.

दर्दपुरा के हालात को अपनी कविता के माध्यम से बयां करने वाले शायर मीर दर्दपुरी के शब्दों में यहां के निवासी सीमा से सटे होने का ख़ामियाजा भुगत रहे हैं. आतंकवादियों और सुरक्षाबलों की गोलियां दर्दपुरा के नौजवानों को लीलती रही हैं. परिणामस्वरूप गांव में रह गए बूढ़े, विकलांग और उनमें सबसे ज़्यादा विधवाएं. यही कारण है कि घाटी में दर्दपुरा को विधवाओं का गांव के नाम से भी जाना जाता है. आय का साधन छिन जाने के बाद बच्चों की भूख को शांत करने के लिए इन विधवाओं को भीख तक मांगनी पड़ी. इसकी वजह एक तरफ़ जहां इलाक़े की ज़मीन का पथरीला होना है, वहीं यहां पर पानी के स्रोत भी सीमित हैं. ऐसे में खेती करना आसान नहीं है. अलबत्ता पशुपालन से कुछ आमदनी हो जाती है, लेकिन यह इतना काफी नहीं होता कि घर के सभी सदस्यों के पेट की आग को शांत किया जा सके. ऐसा ही कष्टप्रद जीवन जीते हुए यहां की पीढ़ी जवान हुई है. नई नस्ल की आंखों में कई सपने भी पले-बढ़े हैं, लेकिन देश के अन्य भागों की तरह बेरोज़गारी यहां भी विकराल समस्या बनी रही. समस्याओं की ऐसी लंबी-चौड़ी सूची अकेले दर्दपुरा की नहीं है, बल्कि कश्मीर के कई सुदूर क्षेत्रों में ऐसे ही हालात देखने को मिल जाएंगे.

बहरहाल, पंचायत चुनाव में कश्मीर के ग्रामीणों का बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना यह भी साबित करता है कि वे अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, जहां कम से कम उन्हें बुनियादी सुविधाएं तो मयस्सर हो सकें. लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या उनका ख्वाब पूरा करने में पंचायत एक माध्यम बन सकती है या एक बार फिर उन्हें मायूसी ही हाथ लगेगी? (चरखा)

ख्वाजा परवेज़ दिलबर
feedback@chauthiduniya.com

देश में हर रोज़ क़रीब सवा आठ करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जबकि हर साल लाखों टन अनाज सड़ जाता है.

भूखों को रोटी देने की क़वायद

फ़िरदौस ख़ान

देश में खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंज़ूरी मिलने से भुखमरी से होने वाली मौतों में कुछ हद तक कमी आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है. हाल में प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 को मंज़ूरी दी है. इसका मक़सद भुखमरी के शिकार लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना है. अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो देश की जनता को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सकेगा. विधेयक के मुताबिक़, 46 फ़ीसदी ग्रामीण और 28 फ़ीसदी शहरी परिवारों को प्राथमिकता वाले समूह में शामिल किया गया है. ये परिवार प्रति सदस्य सात किलो खाद्यान्न यानी 3 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल और एक रुपये किलो की दर से मोटा अनाज ले सकेंगे. 49 फ़ीसदी ग्रामीण और 22 फ़ीसदी शहरी परिवारों को सामान्य समूह के तहत रखा गया है. उन्हें चार रुपये प्रति किलो की दर से अनाज मिलेगा.

देश की 32 फ़ीसदी आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है. हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो फ़सल काटे जाने के बाद खेत में बचे अनाज और बाज़ार में पड़ी गली-सड़ी सब्ज़ियां बटोर कर किसी तरह उससे अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं. महानगरों में भी भूख से बेहाल लोगों को कूड़ेदानों में से रोटी या ब्रेड के टुकड़ों को उठाते हुए देखा जा सकता है. रोज़गार की कमी और ग़रीबी की मार के चलते कितने ही परिवार चावल के कुछ दानों को पानी में उबाल कर पीने को मजबूर हैं. एक तरफ़ गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ता है तो दूसरी तरफ़ लोग भूख से मर रहे होते हैं. ऐसी हालत के लिए क्या व्यवस्था सीधे तौर पर दोषी नहीं है? इसलिए यह ज़रूरी है कि सरकार विधेयक को पारित कराने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि इस योजना पर ईमानदारी से अमल हो. यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से अब तक ग़रीबों की भलाई के लिए योजनाएं तो अनेक बनाई गईं, लेकिन लालफ़ीताशाही के चलते वे महज़ काग़ज़ों तक ही सिमट कर रह गईं. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो इसे स्वीकार करते हुए यहां तक कहा था कि सरकार की ओर से चला एक रुपया ग़रीबों तक पहुंचते-पहुंचते पंद्रह पैसे ही रह जाता है.

देश में हर रोज़ क़रीब सवा आठ करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जबकि हर साल लाखों टन अनाज सड़ जाता है. कुछ अरसा पहले अनाज की बर्बादी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख़ अपनाते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि गेहूं को सड़ाने से अच्छा है, उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया जाए. कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई थी कि एक तरफ़ इतनी बड़ी तादाद में अनाज सड़ रहा है, वहीं लगभग 20 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं. बीते वर्ष 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी एवं न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए थे कि हर प्रदेश में एक बड़ा गोदाम बनाया जाए और प्रत्येक डिवीज़न एवं ज़िलों में भी गोदामों का निर्माण किया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा था कि सूखे और बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मज़बूत किया जाए. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि उचित मूल्य की दुकानें महीने भर खुली रहें. इससे पहले 27 जुलाई को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां लोग भूख से मर रहे हों, वहां अनाज का एक भी दाना बेकार छोड़ना गुनाह है. मगर कोर्ट के आदेश पर कितना अमल हुआ, किसी से छुपा नहीं है. हालांकि कुछ माह तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को अनाज बांटा गया, लेकिन उसमें भी धांधली बरते जाने की ख़बरें सामने आईं.

पिछले काफ़ी अरसे से हर साल लाखों टन गेहूं बर्बाद हो रहा है. बहुत सा गेहूं खुले में बारिश में भीगकर सड़ जाता है, वहीं गोदामों में रखे अनाज का भी 15 फ़ीसदी हिस्सा हर साल ख़राब हो जाता है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक़, भारतीय खाद्य निगम (एफ़सीआई) के गोदामों में वर्ष 1997 से 2007 के दौरान 1.83 लाख टन गेहूं, 6.33 लाख टन चावल, 2.20 लाख टन धान और 111 टन मक्का सड़ चुका है. इतना ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज के अभाव में हर साल क़रीब 60 हज़ार करोड़ रुपये की सब्ज़ियां और फल भी ख़राब हो जाते हैं. एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले छह वर्षों में देश भर के गोदामों में 10 लाख 37 हज़ार 738 टन अनाज सड़ चुका है. साथ इन गोदामों की सफ़ाई पर क़रीब दो करोड़ 70 लाख रुपये ख़र्च हुए हैं. एफ़सीआई के मुताबिक़, पिछले साल जनवरी तक 10,688 लाख टन अनाज ख़राब हो चुका है. अमूमन सालाना दो लाख टन अनाज ख़राब हो जाता है.

केंद्र सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन में आई स्थिरता एवं बढ़ती जनसंख्या के खाद्य उपभोग को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2007 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना शुरू की थी. इसका मक़सद गेहूं, चावल एवं दलहन की उत्पादकता में वृद्धि लाना है, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा की हालत को बेहतर किया जा सके. यह योजना विभिन्न प्रदेशों में चल रही है.

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक़, पिछले साल सरकारी एजेंसियों ने छह करोड़ टन अनाज ख़रीदा, जबकि भंडारण की क्षमता 447.09 लाख टन अनाज की है. ऐसे में बाक़ी बचे अनाज को खुले में रखा गया है. इस वक़्त देश में क़रीब 28 हज़ार करोड़ रुपये क़ीमत का अनाज खुले में पड़ा है. अफ़सोस की बात तो यह भी है कि एक तो पहले ही गोदामों की कमी है, इसके बावजूद सरकारी गोदामों को निजी कंपनियों को किराये पर दे दिया जाता है और अनाज खुले में सड़ता रहता है. जिन गोदामों में अनाज रखने की जगह बची हुई है, लापरवाही के चलते वहां भी अनाज नहीं रखा जाता. खुले में पड़े अनाज को तिरपाल या प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है, लेकिन बारिश और जलभराव के कारण अनाज सुरक्षित नहीं रह पाता. पानी में भीगा अनाज अंकुरित हो जाता है और कुछ दिनों बाद सड़ जाता है. गोदामों में रखे अनाज को कीड़ों और चूहों से बचाने के भी इंतज़ाम नहीं किए जाते, जिससे अनाज में कीड़े लग जाते हैं और अनाज को चूहे खा जाते हैं. अधिकारियों द्वारा चोरी-छुपे सरकारी अनाज बेचने के आरोप भी लगते रहे हैं. गोदामों से कम हुआ अनाज चूहों के हिस्से में लिख दिया जाता है.

हैरानी की बात तो यह भी है कि एक तरफ़ देश के पास अनाज का इतना भंडार है कि इसे रखने तक की जगह नहीं है, दूसरी तरफ़ देश की एक बड़ी आबादी को भरपेट भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है. यह आबादी भुखमरी और कुपोषण की चपेट में है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स (विश्व भुखमरी सूचकांक) में अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था (आईएफ़पीआरआई) के 88 देशों के विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का 66वां स्थान है. भारत में पिछले कुछ सालों में लोगों की ख़ुराक में कमी आई है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण करने की औसत दर 1972-1973 में 2266 कैलोरी प्रतिदिन थी, जो अब घटकर 2149 रह गई है. देश में आबादी 1.9 फ़ीसदी की दर से बढ़ी है, वहीं खाद्यान्न उत्पादन 1.7 फ़ीसदी की दर से घटा है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक़, देश में 46 फ़ीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. यूनिसेफ़ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के कुल कुपोषणग्रस्त बच्चों में से एक तिहाई आबादी भारतीय बच्चों की है. भारत में पांच करोड़ 70 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं. विश्व में कुल 14 करोड़ 60 लाख बच्चे कुपोषणग्रस्त हैं. विकास की मौजूदा दर अगर ऐसी ही रही तो 2015 तक कुपोषण दर आधी कर देने का लक्ष्य 2025 तक भी पूरा नहीं हो सकेगा. रिपोर्ट में भारत की कुपोषण दर की तुलना अन्य देशों से करते हुए कहा गया है कि भारत में कुपोषण की दर इथोपिया, नेपाल और बांग्लादेश के बराबर है. इथोपिया में कुपोषण दर 47 फ़ीसदी तथा नेपाल और बांग्लादेश में 48-48 फ़ीसदी है, जो चीन की आठ फ़ीसदी, थाइलैंड की 18 फ़ीसदी और अफ़ग़ानिस्तान की 39 फ़ीसदी के मुक़ाबले बहुत ज़्यादा है.

केंद्र सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन में आई स्थिरता एवं बढ़ती जनसंख्या के खाद्य उपभोग को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2007 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना शुरू की थी. इसका मक़सद गेहूं, चावल एवं दलहन की उत्पादकता में वृद्धि लाना है, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा की हालत को बेहतर किया जा सके. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 14 राज्यों के 136 ज़िलों को चुना गया है. इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए 9 राज्यों के 141 ज़िलों को चुना गया. इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल शामिल हैं. इसी तरह दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 14 राज्यों के 171 ज़िलों को चुना गया. इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल शामिल हैं. इस योजना के तहत इन ज़िलों के 20 मिलियन हेक्टेयर धान के क्षेत्र, 13 मिलियन हेक्टेयर गेहूं के क्षेत्र और 4.5 मिलियन हेक्टेयर दलहन के क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जो धान एवं गेहूं के कुल बुआई क्षेत्र का 50 फ़ीसदी है. दलहन के लिए अतिरिक्त 20 फ़ीसदी क्षेत्र का सृजन किया जाएगा. दरअसल, बढ़ती महंगाई ने निम्न आय वर्ग के लिए दो वक़्त की रोटी का भी संकट खड़ा कर दिया है. ऐसे में सिर्फ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक बनाने से कुछ ख़ास होने वाला नहीं है. सरकार को हर क्षेत्र में जनता की बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखना होगा.

firdaus@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... वित्त मंत्री और अंबानी !

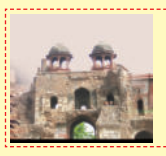

प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह के पिता सर शोभा सिंह ने लुटियन और बेकर के साम्राज्यवादी नक्शे के अनुरूप चूना, पत्थर और संगमरमर तराशने का काम किया.

नई दिल्ली
सौ बरस का सफ़र

नलिन चौहान

किसी भी भारतीय को यह जानकर हैरानी होगी कि आज की नई दिल्ली किसी परंपरा के अनुसार अथवा स्वतंत्र भारत के राजनीतिक नेताओं की वजह से नहीं, बल्कि एक सौ साल (1911) पहले आयोजित तीसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम की घोषणा के कारण देश की राजधानी बनी. इस दिल्ली दरबार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना ब्रिटिश भारत की राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा थी. 12 दिसंबर, 1911 में ब्रिटेन के राजा की घोषणा से पहले इस ऐतिहासिक तथ्य से अधिक लोग वाक़िफ़ नहीं थे. किंग जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण का उत्सव मनाने और उन्हें भारत का सम्राट स्वीकारने के लिए दिल्ली में आयोजित दरबार में ब्रिटिश भारत के शासक, भारतीय राजकुमार, सामंत, सैनिक और अभिजात्य वर्ग के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे. दरबार के अंतिम चरण में एक अचरज भरी घोषणा की गई. तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने राजा के राज्यारोहण के अवसर पर प्रदत्त उपाधियों और भेंटों की घोषणा के बाद एक दस्तावेज़ सौंपा. अंग्रेज राजा ने वक्तव्य पढ़ते हुए राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने, पूर्व और पश्चिम बंगाल को दोबारा एक करने सहित अन्य प्रशासनिक परिवर्तनों की घोषणा की. दिल्ली वालों के लिए यह एक हैरतअंगेज फ़ैसला था, जबकि इस घोषणा ने एक ही झटके में एक सूबे के शहर को एक साम्राज्य की राजधानी में बदल दिया, जबकि 1772 से ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी.

लॉर्ड हॉर्डिंग लिखते हैं कि इस घोषणा से उपस्थित लोगों में आश्चर्यजनक रूप से गहरा मौन पसर गया और चंद सेकंड बाद करतल ध्वनि गूंज उठी. ऐसा होना स्वाभाविक था. अपने समृद्ध प्राचीन इतिहास के बावजूद जिस समय दिल्ली को राजधानी बनने का मौक़ा दिया गया, उस समय वह किसी भी लिहाज़ से एक प्रांतीय शहर से ज़्यादा नहीं थी. लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा (1903) के बाद से ही इसका विरोध कर रहे और एकीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत बंगालियों की तरह दिल्ली वालों ने कोई मांग नहीं रखी और न कोई आंदोलन छेड़ा. किंग जॉर्ज पंचम की घोषणा से हर कोई हैरान था, क्योंकि यह पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी. उनकी भारत यात्रा के छह महीने पहले ही ब्रिटिश भारत की राजधानी के स्थानांतरण का निर्णय हो चुका था. इंग्लैंड और भारत में दर्जन भर व्यक्ति ही इससे वाक़िफ़ थे.

राजा की घोषणा के समानांतर बांटे गए गजट और समाचार पत्रकों को भी पूरी गोपनीयता के साथ छापा गया. दिल्ली में एक प्रेस शिविर लगाया गया, जहां सचिवों, मुद्रकों और उनके नौकरों के लिए रहने की व्यवस्था की गई और वहीं प्रिंटिंग मशीनें लगाई गईं. दरबार से पहले इन शिविरों में कर्मचारियों को लगा दिया गया और दरबार की वास्तविक तिथि से पहले इस स्थान की सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए सैनिकों–पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी गई थीं. सात दिसंबर, 1911 को ब्रिटेन के राजा और रानी (जार्ज पंचम और क्वीन मेरी) दिल्ली पहुंचे. शाही दंपत्ति को एक जुलूस की शक्ल में शहर की गलियों से होते हुए विशेष रूप से लगाए गए शिविरों के शहर (किंग्सवे कैंप) में गाजे–बाजे के साथ पहुंचाया गया. उत्तर–पश्चिम दिल्ली में विशेष रूप से निर्मित एक सोपान मंडप में आयोजित दरबार में चार हज़ार ख़ास मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई और एक वृहद अर्द्ध आकार के टीले से क़रीब 35,000 सैनिक और 70,000 दर्शक दरबार के चश्मदीद गवाह बने. दरबार के दौरान लॉर्ड हॉर्डिंग सहित काउंसिल के सदस्यों, भारतीय राजाओं, राजकुमारों सहित कइयों ने अंग्रेज राजा की कदमबोसी की और हाथ को चूमा. 25 गुणा 30 मील के घेरे में फैले क्षेत्र में 223 तंबू लगाए गए, जहां 60 मील की नई सड़कें बनाई गईं और क़रीब 30 मील लंबी रेलवे लाइन के लिए 24 स्टेशन.

अहमद अली के उपन्यास–ट्विलाइट इन दिल्ली (1940) के अनुसार, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने व्यक्तिगत रूप से दरबार की तैयारियों का जायज़ा लिया. कुल 40 वर्ग किलोमीटर में फैले 16 वर्ग किलोमीटर के घेरे में पूरे भारत से क़रीब 84,000 यूरोपियों और भारतीयों को 233 शिविरों में ठहराया गया. 1911 में बसंत के मौसम के बाद क़रीब 20,000 मज़दूरों ने दिन–रात एक करके इन शिविरों को तैयार किया. इस दौरान 64 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ, शिविरों में पानी की व्यवस्था के लिए 80 किलोमीटर की पानी की मुख्य लाइन और 48 किलोमीटर की पाइप लाइनें डाली गईं. मेहमानों के खानपान के लिए दुधारू पशुओं, सब्जी और मांस का इंतज़ाम किया गया. दिल्ली दरबार का आयोजन एक जनवरी, 1912 को होना था, पर इस दिन मुहर्रम होने की वजह इसे कुछ दिन पहले करने का फ़ैसला किया गया.

1877 में लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया की कैसरे हिंद के रूप में उद्घोषणा के अवसर पर पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था. महारानी विक्टोरिया के उत्तराधिकारी के रूप में एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के अवसर पर 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया. यह दरबार 29 दिसंबर से अगले साल दस दिनों तक चला था. इसके एक भाग का आयोजन लालकिले के दीवान–ए–आम में किया गया था. दूसरे दिल्ली दरबार पर खर्च हुए 1,80,000 पाउंड की तुलना में तीसरे दिल्ली दरबार पर 6,60,000 पाउंड की राशि ख़र्च हुई. किनेमाकलर ने तीसरे दिल्ली दरबार की फिल्म–विद अवर किंग एंड क्वीन थ्रू इंडिया (1912 में सबसे पहली बार प्रदर्शित) बनाई. यह फिल्म से अधिक एक मल्टी मीडिया शो थी. किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी ने किंग्सवे कैंप में आयोजित दिल्ली दरबार में 15 दिसंबर, 1911 को नई दिल्ली शहर की नींव के पत्थर रखे. बाद में इन पत्थरों को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के पास स्थानांतरित कर दिया गया और 31 जुलाई, 1915 को अलग–अलग कक्षों में रख दिया गया. स्थापना दिवस समारोह में लॉर्ड हार्डिंग ने कहा कि दिल्ली के इर्द–गिर्द अनेक राजधानियों का उद्घाटन हुआ है, पर किसी से भी भविष्य में अधिक स्थायित्व अथवा अधिक ख़ुशहाली की संभावना नहीं दिखती. रॉबर्ट ग्रांट इर्विंगस की पुस्तक–इंडियन समर में हार्डिंग कहते हैं, हमें मुगल सम्राटों के उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता के प्राचीन केंद्र में अपने नए शहर को बसाना चाहिए. वायसराय ने बतौर राजधानी दिल्ली के चयन का ख़ुलासा करते हुए कहा कि यह परिवर्तन भारत की जनता की सोच को प्रभावित करेगा. तत्कालीन भारत सरकार के गृह सदस्य सर जॉन जेनकिंस ने कहा कि यह एक साहसिक राजनयिक क़दम होगा, जिससे चहुंओर संतुष्टि के साथ भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी. अंग्रेजों की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के दो प्रमुख कारण थे. पहला, बंगाली अंग्रेजों के लिए काफी समस्याएं पैदा कर रहे थे और अंग्रेजों की नज़र में कलकत्ता राजनीतिक आतंकवाद का केंद्र बन चुका था. वहां लोग रायटर्स बिल्डिंग पर बम फेंक रहे थे, जबकि दिल्ली में ऐसे हालात नहीं थे. लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के बाद अंग्रेज बंगालियों को उपद्रवकारी और राजनीतिक रूप से सजग मानने लगे थे. दूसरा, यह एक तरह से मुसलमानों को ख़ुश करने का भी फ़ैसला था. अंग्रेजों की सोच यह थी कि वे एक ही समय में हिंदू और मुसलमानों को नाराज़ नहीं कर सकते. इस सिलसिले में 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार की ऐतिहासिक घटनाओं के ब्योरे वाला अहमद अली का उपन्यास दिल्ली में आहत मुस्लिम सभ्यता की पड़ताल करता है. इस किताब के ज़रिए लेखक ने तत्कालीन भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद की कहानी बयान करते हुए उपनिवेशवादी ताक़त से टक्कर पर मुस्लिम नज़रिए को सामने रखते हुए साम्राज्यवादी साहित्य को चुनौती दी है.

नीरद सी चौधरी ने आजादी मिलने के तुरंत बाद प्रकाशित अपनी आत्मकथा–द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन में उनकी (बंगालियों) प्रतिक्रिया का स्मरण करते हुए लिखा कि 1911 में मौत का साया, जिससे हम सब अपरिचित थे, पहले ही कलकत्ता पर पसर चुका था. मुझे अभी भी अपने पिता द्वारा उनके मित्रों के साथ राजधानी के दिल्ली स्थानांतरण का समाचार पढ़ने की बात याद है. कलकत्ता का स्टेट्समैन गुस्से में था, पर वह भविष्य के बजाय इतिहास के बारे में ज़्यादा सोच रहा था और वह कासनड्रा की तरह भविष्यवाणियां करने का इच्छुक नहीं था. हम बंगाली कासनड्रा की तरह भविष्यवक्ता नहीं थे. हम बातूनी थे. मेरे पिता के एक दोस्त ने रूखेपन से कहा कि वे साम्राज्यों के क़ब्रिस्तान दिल्ली में दफ़न होने जा रहे हैं. इस बात पर वहां मौजूद हर कोई हंस पड़ा. हम सभी की तीव्र इच्छा का लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य का दफ़न होना ही था, पर उस दिन हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होने में केवल छत्तीस साल लगेंगे. अंग्रेज सत्रह सौ सत्तावन से कलकत्ते में राज करते रहे. दिल्ली राजधानी बनाने के छत्तीस साल बाद उनके विश्वव्यापी साम्राज्य का सूरज डूब गया. 1912 में एडविन लैंडसिर लुटियन और उनके पुराने दोस्त हरबर्ट बेकर को बतौर वास्तुकार नए शहर को बसाने की ज़िम्मेदारी दी गई. लुटियन के चुनाव में उनके काम के अनुभव का कम और रिश्ते का जोर ज़्यादा था. सरकारी इमारतें और शहर के वास्तु से उनका दूर–दूर तक कोई लेना–देना नहीं था. महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने लॉर्ड लिटन, जिन्होंने 1877 में महारानी विक्टोरिया के समय दिल्ली दरबार की अध्यक्षता की थी, की एकलौती बेटी एमली लिटन से शादी की थी. लुटियन का खास मित्र और सहयोगी गर्टरूड जेकल, जो अच्छा बाग वास्तुशास्त्री भी था, भी एक अच्छे संपर्कों वाला व्यक्ति था. लॉर्ड हॉर्डिंग भी मार्च 1912 के अंत में अपने लाव–लश्कर के साथ दिल्ली पहुंच गए. 1911 में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय का पुराना वायस रीगल लॉज वायसराय का निवास बना. प्रथम विश्व युद्ध से लेकर क़रीब एक दशक तक वायसराय इस स्थान पर रहे, जब तक रायसीना पहाड़ी पर लुटियन निर्मित उनका नया आवास नहीं बना.

शहर का नाम	स्थापना काल	संस्थापक	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
लाल कोट	1000	अनंगपाल	3.40
सिरी	1303	अलाउद्दीन खिलजी	1.70
तुगलकाबाद	1321	गयासुद्दीन तुगलक	2.20
जहांपनाह	1327	मुहम्मद बिन तुगलक	0.20
फ़िरोज़ाबाद	1354	फ़िरोज़शाह तुगलक	0.10
पुराना किला	1533	हुमायूं	0.20
शाहजहांनाबाद	1639	शाहजहां	4.90
नई दिल्ली	1911	एडवर्ड पंचम	12.20

मौजूदा नई दिल्ली शहर दिल्ली का आठवां शहर है. नई दिल्ली के लिए अनेक स्थानों के बारे में सोचा और अस्वीकृत किया गया. दरबार क्षेत्र को अस्वास्थ्यकर और अनिच्छुक घोषित कर दिया गया, जहां बाढ़ का भी ख़तरा था. सब्जी मंडी का इलाक़ा बेहतर था, पर फैक्ट्री क्षेत्र में अधिग्रहण से मिल मालिक नाराज़ हो जाते. सिविल लाइंस में यूरोपीय आबादी को हटाने से उसकी नाराज़गी का ख़तरा था. अत: लुटियन के नेतृत्व में मौजूदा पुराने शहर शाहजहांनाबाद के दक्षिण में नई दिल्ली के निर्माण का कार्य 1913 में शुरू हुआ, जब नई दिल्ली योजना समिति का गठन किया गया. उसने पुराने शहर का तिरस्कार किया और आसपास का इलाक़ा तत्काल ही एक दूसरे दर्जे का शहर यानी पुरानी दिल्ली बन गया. लुटियन के ज़िम्मे नई दिल्ली शहर, गवर्मेंट हाउस और हरबर्ट बेकर के सचिवालय के दो हिस्सों (नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक) और काउंसिल हाउस (संसद भवन) को तैयार करने का भार आया. क़रीब 2,800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली लुटियन दिल्ली का मूल स्वरूप 1911 से 1931 के मध्य में बना, जो साम्राज्यवादी भव्यता का एक खुला उदाहरण था. इसका मुख्य केंद्र ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि वायसराय का महलनुमा परिसर (अब राष्ट्रपति भवन) था. अंग्रेज वास्तुकार नई दिल्ली को पुरानी दिल्ली की अराजकता के विपरीत क़ानून–व्यवस्था का प्रतीक बनाना चाहते थे. हरबर्ट बेकर का मानना था कि नई राजधानी अच्छी सरकार और एकता का स्थापत्यकारी स्मारक होनी चाहिए, क्योंकि भारत को इतिहास में पहली बार अंग्रेज शासन के तहत एकता मिली है. भारत में अंग्रेजी शासन केवल सरकार और संस्कृति का प्रतीक नहीं है, यह एक विकसित होती नई सभ्यता है, जिसमें पूर्व और पश्चिम के बेहतर तत्वों का समावेश है. वायसराय पैलेस का मुख्य गुंबद मुगल स्थापत्य कला की तर्ज पर बनाया गया, पर अंग्रेजों ने अपना महत्व बरक़रार रखने के लिए पैलेस की ऊंचाई शाहजहां की जामा मस्जिद से अधिक रखी.

एक तरह से नई दिल्ली का अर्थ भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक साम्राज्यवादी राजधानी और एक सदी के लिए अंग्रेज हुक्मरानों के सपनों का साकार होना था, हालांकि इसके पूरा होने में 20 साल का वक़्त लगा. यह भी तब, जबकि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के साथ ही नई दिल्ली बनाने का फ़ैसला लिया गया. इस तरह नई राजधानी केवल 16 साल के लिए अपनी भूमिका निभा सकी. नई दिल्ली में निर्माण कार्य 1931 में पूरा हुआ, जब सरकार इस नए शहर में स्थानांतरित हो गई. 13 फरवरी, 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन किया. प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह के पिता सर शोभा सिंह ने लुटियन और बेकर के साम्राज्यवादी नक्शे के अनुरूप चूना, पत्थर और संगमरमर तराशने का काम किया. खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत में नई दिल्ली पर खासी रोशनी डाली है. उनके शब्दों में, मेरे पिताजी को साउथ ब्लॉक बनाने का ठेका मिला था और उनके सबसे जिगरी दोस्त बसाखा सिंह को नार्थ ब्लॉक बनाने का. हमारे मकान के सामने और दक्षिण दिल्ली से कोई बारह किलोमीटर दूर बदरपुर गांव से दिल्ली के लिए, जिसे आज कनाट सर्कस कहते हैं, छोटी रेलवे लाइन गई थी. बदरपुर से निर्माण स्थल तक पत्थर, रोड़ी और बजरी लाने के लिए यह लाइन बिछाई गई थी. जिस दिन छुट्टी होती, हम छोटी सी इंपीरियल दिल्ली रेल के आने का इंतज़ार करते कि कब वह आकर पत्थर उतारे और हम उसमें सवार होकर मुफ्त में कनाट प्लेस की सैर करके आएं.

दिल्ली दरबार रेलवे

दिल्ली दरबार के मद्देनज़र अंग्रेजों ने अतिरिक्त रेल सुविधाएं बढ़ाने और नई लाइनें बिछाने का फ़ैसला किया. सरकार ने इसके लिए दिल्ली दरबार रेलवे नामक विशेष संगठन का गठन किया. मार्च से अप्रैल, 1911 के बीच यातायात समस्याओं के निदान के लिए छह बैठकें हुईं, जिनमें दिल्ली में विभिन्न दिशाओं से आने वाली रेलगाड़ियों के लिए 11 प्लेटफार्मों वाला एक मुख्य रेलवे स्टेशन, आज़ादपुर जंक्शन तक दिल्ली दरबार क्षेत्र में दो अतिरिक्त डबल रेल लाइनों, बंबई से दिल्ली बारास्ता आगरा एक नई लाइन बिछाने जैसे महत्वपूर्ण फ़ैसले किए गए. सैनिक और नागरिक रसद पहुंचाने के लिए कलकत्ता से दिल्ली तक प्रतिदिन एक मालगाड़ी चलाई गई, जो हावड़ा से चलकर दिल्ली के किंग्सवे स्टेशन पहुंचती थी. इस तरह मालगाड़ी क़रीब 42 घंटे में 900 मील की दूरी तय करती थी. नवंबर, 1911 में मोटर स्पेशल नामक पांच विशेष रेलगाड़ियां हावड़ा और दिल्ली के बीच चलाई गईं. देश भर से 80,000 सैनिकों को दिल्ली लाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं.

इतिहास और अगर–मगर

अगर प्रथम विश्व युद्ध न छिड़ा होता तो नई दिल्ली के निर्माण में अधिक धन ख़र्च किया जाता और यह शहर अधिक भव्य बनता. यमुना नदी पुराने किले के साथ बहतीं और राजपथ से गुजरने वाले इसके गवाह बनते. अगर लॉर्ड कर्जन और उनके मित्रों की चलती तो नई दिल्ली को राजधानी बनाने का फ़ैसला रद्द हो जाता. अगर हरबर्ट बेकर ने प्रिटोरिया का निर्माण न किया होता तो लुटियन को नई दिल्ली परियोजना में अवसर न मिलता और न विजय चौक (इंडिया प्लेस) प्रिटोरिया की तर्ज पर तैयार होता. अगर लुटियन की मर्जी चली होती तो राष्ट्रपति भवन (गर्वमेंट हॉउस) सरदार पटेल मार्ग पर मालचा पैलेस के नज़दीक रिज में बना होता. लॉर्ड हार्डिंग के इस प्रस्ताव को ख़ारिज करने के बाद ही रायसीना पहाड़ी पर वायसराय हाउस बना.

feedback@chauthiduniya.com

अन्ना हजारे द्वारा फिर से अनशन की धमकी असल में यह बताती है कि उनकी जो भी नैतिक ताक़त थी, वह अब कमज़ोर पड़ने लगी है.

भाजपा बेवजह दुष्प्रचार कर रही है कि विधेयक में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम की व्यवस्था नहीं है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

जो जितने का पात्र है, उतना उसे क्यों न मिले

दूसरी योजना है कि हर एक को उतना मिले, जितने का वह पात्र है. बहुत से व्यक्ति, ख़ासकर जो आराम से रहते हैं और समझते हैं कि यही ठीक है. जो जितने का पात्र है, उतना उनको मिलता है, मिला हुआ है. जो मेहनती हैं, मितव्ययी हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं है. जो आलसी हैं, काम नहीं करते, बेईमान हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, कई व्यसनों से पीड़ित हैं, उन्हीं की वजह से दरिद्रता है. ये यह भी बतलाते हैं कि अच्छे आचरण के मज़दूर को हमेशा नौकरी मिल जाती है. जो ख़राब आचरण का मज़दूर है, जो व्यर्थ ख़र्च करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है इत्यादि, उन्हें नौकरी नहीं मिलती. इसलिए ये आलसी और दरिद्र हो जाते हैं. पर इस बात से कोई यह सिद्ध नहीं होता. यही ज्ञात होता है कि हमारे व्यसन और हमारी कमज़ोरियां हमें दरिद्र बना देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कई दूसरे ऐसे भी व्यसन हैं, जो हमें मालदार बना देते हैं.

कई व्यक्ति जो कठोर, निर्दयी, कंजूस और स्वार्थी हैं, जो हमेशा अपने पड़ोसियों की अवस्था का अनुचित लाभ उठाने की ताक में रहते हैं, शीघ्र मालदार बन जाते हैं. इसके विपरीत जो व्यक्ति उदार हृदय हैं, परमार्थी हैं, मित्रता का व्यवहार रखने वाले हैं, वे दरिद्र बने रहते हैं. और जैसी कि आज की सामाजिक स्थिति है, कई दरिद्रता में ही जन्मते हैं, कई संपदा में ही पैदा होते हैं और अपना आचरण बना पाएं, इसके पहले ही वे अमीर या ग़रीब श्रेणी में विभाजित भी हो चुके होते हैं. इसलिए यह योजना कि जो जितने का पात्र है, उतना ही उसे प्राप्त हो, यह काबिले विचार भी नहीं है. हर आदमी देख सकता है कि इसका प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ता है. इससे थोड़े से आदमी जो आलसी हैं, काम नहीं करते, ये तो धनिक बन जाएंगे और कई गुना अधिक संख्या वाले मेहनती आदमी दरिद्र बनेंगे.

यह स्वाभाविक ही है कि आप कहेंगे कि भाई, अगर आज यह नहीं है कि जो जितने का पात्र हो, उतना उसे मिले तो यह होना चाहिए. आप तुरंत यही विचार रखेंगे कि आदमी अपनी अच्छाई या बुराई के अनुपात से ही धनिक या दरिद्र होना चाहिए. इसमें अनेक कठिनाइयां हैं. अच्छाई या बुराई का मापदंड क्या? किसी आदमी की अच्छाई आप रुपयों में कैसे आंक सकते हैं? उदाहरण के तौर पर आप किसी गांव के किन्हीं दो व्यक्तियों को लीजिए और उनका अनुपात निर्धारित कीजिए. गांव के एक लोहार को और एक स्कूल अध्यापक को ले लीजिए. अब आप बतलाइए कि लोहार को अध्यापक से कम मिलना चाहिए या ज़्यादा और कितना कम या कितना ज़्यादा? आधा, पौना, सवाया, ड्योढ़ा, दोगुना क्या अनुपात हो? शायद आप कह सकें कि किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, पर कितना कम या ज़्यादा, यह प्रश्न निश्चय ही कठिन है. ज़रा

धैर्य से सोचिए, अध्यापक ने कॉलेज में विद्याध्ययन किया है, पर यह तो इसकी पात्रता नहीं हुई. इसके मां-बाप ने पढ़ाया, यह पात्रता तो उनकी हुई. हां, अध्यापक अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, यह ज़रूर इसकी पात्रता हुई. पर लोहार घोड़े की नाल बना सकता है, फावड़े या हल पर फाल बांध सकता है, यह उसकी पात्रता हुई. इस तरह अपात्र-पात्र का निर्णय उसी खटाई में पड़ जाएगा. पात्रता का माप तो है ही नहीं, तो क्यों न उसकी अपात्रता का माप किया जाए?

मान लीजिए इनकी त्रुटियां या इनके दोष आपको ज्ञात हो गए. पहले तो सही-सही मालूम होना ही मुश्किल काम है, पर समझ लीजिए कि मालूम हो गए तो क्या इसी वजह से इनका वेतन कम कर देना उचित होगा? निश्चय ही जब पात्र-अपात्र का निर्णय उसके गुण-दोषों से देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, तब उनका जो मूल्यांकन रुपयों से होगा, आपको निरर्थक दिखाई देगा. दो पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हों, इस आधार पर कि विजेता को 500 रुपये पुरस्कार मिले और शांति शिक्षा के अग्रगामी दूत महात्मा को 100 रुपये भी न मिले, यह कहां तक उचित है? आप कुश्ती के पहलवान का पुरस्कार उचित मानेंगे और शायद महात्मा की दक्षिणा उचित नहीं मानेंगे. अत: पात्रता-अपात्रता का निर्णय मानव शक्ति या कल्पना के बाहर की बात हो गई. इस कारण यह दूसरी योजना कि जो जितने का पात्र हो, उतना ही उसको मिले, हमको त्याग देनी होगी.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नद्रष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

इनके लिए अनशन कौन करेगा

यह ज़रूरी नहीं है कि सभी अनशन प्रभावकारी साबित हों या वे नैतिक दृष्टि से सही माने जाएं. जब ब्रिटिशों ने अछूतों (जैसा कि उन्हें उस वक़्त कहा जाता था) के लिए अलग निर्वाचक मंडल की घोषणा की, तब गांधी जी ने अनशन किया था. उन्होंने अछूतों को हिंदुओं से अलग करने की इस ब्रिटिश योजना का विरोध किया, लेकिन अंबेडकर गांधी जी के इस निर्णय से नाख़ुश थे. अंत में गांधी जी की जीत हुई. अलग निर्वाचक मंडल की जगह कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं. कुल मिलाकर परिणाम यह निकला कि इन सुरक्षित सीटों से जो जीते, वे दकियानूसी हिंदुओं के वोट से जीते, न कि उन सुधारवादी लोगों की वजह से, जो अपने अछूत साथियों को दासता से मुक्त कराना चाहते थे. इसके बाद दलितों को अपनी ख़ुद की पार्टी और ख़ुद की आवाज़ ढूंढने में पचास साल लग गए. इसके बाद से दलितों के बीच डॉ.अंबेडकर की प्रतिष्ठा भी बढ़ी, जबकि गांधी की मूर्ति पर सवाल उठाए जाने लगे.

अन्ना हजारे द्वारा फिर से अनशन की धमकी असल में यह बताती है कि उनकी जो भी नैतिक ताक़त थी, वह अब कमज़ोर पड़ने लगी है. यह एक करुणाजनक स्थिति है. जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, उनमें न तो उन्होंने धैर्य का परिचय दिया और न उन सवालों को समझने की कोशिश की. भ्रष्टाचार असल में कई सिरों वाला सांप है, जिसका सामना महज़ एक बिल से नहीं किया जा सकता है. चुनाव में पैसे का मुद्दा भी है. ब्यूरोक्रेसी के पास प्रतिबंध लगाने या परमिट देने जैसे अधिकार हैं और इन पर उनका नियंत्रण भी है. इस वजह से भी भ्रष्टाचार के रास्ते खुलते हैं. टैक्स की चोरी और टैक्स देने में आनाकानी से काले धन की समस्या बढ़ती है. विदेशी बैंकों में ऐसे खातों की बढ़ती संख्या भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. इसलिए यह अन्ना के लिए सही नहीं होगा कि 16 अगस्त तक एक बिल न आने की वजह से वह आमरण अनशन पर बैठ जाएं.

भ्रष्टाचार और लोकपाल बिल का मुद्दा महिला भ्रूण हत्या से ज़्यादा ग्लैमरस है. ग़रीबों और बच्चों की भूख का सिविल सोसायटी के नेताओं की भूख के आगे कोई महत्व नहीं है. कारण बहुत साधारण है. आप भ्रष्टाचार को किसी के द्वारा कुछ किए जाने के तौर पर सोचते हैं.

मेरे लिए ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि एक ऐसे राष्ट्र में, जहां लाखों लोग इसलिए भूखे रहते हैं कि उनके पास उतना खाना नहीं है जितना उन्हें चाहिए, लोग यह कहें कि उनके पास खाना तो है, लेकिन वे उसे खाएंगे नहीं. क्या ऐसा कहकर वे यह नहीं दिखाना चाहते कि उनकी स्थिति उन लाखों भूखे लोगों से कहीं बेहतर है, क्या यह उन लाखों लोगों का अपमान नहीं है? इस देश में अक्सर महिलाएं अपने पति या बच्चों की भलाई के लिए धार्मिक दृष्टि से उपवास रखती हैं. इस तरह से महिलाएं अपने पतियों की बुराई को भी सुधारने के लिए यह बोझ अपने सिर उठा लेती हैं. शायद ही कोई पति अपनी पत्नी के लिए उपवास रखता हो. पुरुषों के लिए करवा चौथ जैसा कोई व्रत नहीं है. असल में, इस देश में जन्म से ही औरतें अभाव की ज़िंदगी जीने की आदी हो जाती हैं. यही वजह है कि भारत महिलाओं के रहन-सहन की दृष्टि से दुनिया का सबसे ख़राब देश है. भारत में लिंगानुपात भयावह स्थिति में पहुंच चुका है और जैसे-जैसे भारत की समृद्धि बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे यह अनुपात और भयावह होता जा रहा है. अगर आप प्रत्येक दस सालों में ऐसी महिलाओं की गणना करें, जिनकी हत्या जन्म लेने से पहले या जन्म के तुरंत बाद कर दी जाती है तो यह आपको किसी नरसंहार के बराबर लगेगा. भारत के माथे

पर लगे इस काले धब्बे को हटाने के लिए अब तक किसी ने अनशन पर जाने की घोषणा नहीं की है. यहां तक कि महिला आरक्षण बिल को भारत के दो महान एवं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव लगातार भोथरा बनाने में जुटे हुए हैं. वे प्रगतिशील शब्दों के इस्तेमाल से ख़ुद को स्त्री विरोधी न होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भ्रूण हत्या, कुपोषण और लड़कियों की अनदेखी जैसे मामलों के परंपरागत क्षेत्र रहे हैं.

भ्रष्टाचार और लोकपाल बिल का मुद्दा महिला भ्रूण हत्या से ज़्यादा ग्लैमरस है. ग़रीबों और बच्चों की भूख का सिविल सोसायटी के नेताओं की भूख के आगे कोई महत्व नहीं है. कारण बहुत साधारण है. आप भ्रष्टाचार को किसी के द्वारा कुछ किए जाने के तौर पर सोचते हैं. भारत के विकास के मॉडल ने मध्य वर्ग को स्थूल बना दिया है, यह सोचने के लिए कि साठ साल बाद भी इस देश के ग़रीबों और महिलाओं की समस्याओं को हमारे महान लोकतंत्र के नेताओं ने हमेशा नज़रअंदाज़ करने का ही काम किया है. अंत में कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है. नेता ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे. एक सच यह भी है कि आज से पचास साल बाद भी महिलाएं मारी जाती रहेंगी और कोई उनके लिए अनशन नहीं करेगा.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

प्रतिष्ठा गिरी

बाबा रामदेव अपनी वर्तमान स्थिति के लिए स्वयं ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ धर्मयुद्ध लड़ने के बजाय वह जिस तरह भागे, उससे उनकी प्रतिष्ठा गिरी है. इस संबंध में बाबा चाहे जो तर्क दें, लेकिन उन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता. चाहे पुलिस उन्हें गिरफ़्तार क्यों न कर लेती. उन्हें स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए था. महात्मा गांधी और अन्य दूसरे नेताओं ने अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए कभी औरतों के कपड़े पहन कर भागने की कोशिश नहीं की. उन्होंने सत्याग्रह के दौरान लाठियां ही नहीं खाईं, बल्कि अपनी गिरफ़्तारी भी दी. यदि बाबा रामदेव भी उस दिन रामलीला मैदान में डटे रहते तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता. ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर लेती और बाद में समझा कर छोड़ देती, जैसा कि देश में अन्य आंदोलनकारियों के साथ किया जाता है. बाबा अपने दिमाग़ से नहीं, बल्कि आरएसएस और भाजपा के दिमाग़ से काम कर रहे थे. अब वर्तमान स्थिति का सामना बाबा को करना पड़ रहा है, न कि आरएसएस और भाजपा को.

–मो. रफ़ीक़ चौहान, *ईमेल से.*

महंगा भोजन-पानी

गैस सिलेंडर की क़ीमत से हुई घरइतिन लाल
किचन बजट को लेकर अब उधड़ रही खाल
उधड़ रही खाल, देख मैडम की मनमानी
जबसे सत्ता में आई हैं, महंगा भोजन-पानी
कह आनंद सुनो घरइतिन तोड़ो न तुम धैर्य
इस चुनाव में मैडम जी की, न रखना तुम ख़ैर.

–आनंद फ़ैज़ाबादी, उत्तर प्रदेश.

संपत्ति की जांच हो

आख़िर बाबा रामदेव की ही संपत्ति की जांच क्यों हो? आज जो लोग अपनी संपत्ति की जानकारी दे रहे हैं, क्या वे सही जानकारी दे रहे हैं? इसकी जांच कौन करेगा कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है? अभी तक जिन लोगों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है, वह कितनी सही है, इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए.

–राम, *ईमेल से.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

एक थी चवन्नी

चवन्नी को चलन से बाहर कर दिया गया है. इन्हें सिक्का निर्माण क़ानून 1906 की धारा 15-ए के तहत बनाया जाता था. 15 अगस्त, 1950 से सिक्कों का भारतीय बाज़ार में प्रचलन शुरू हुआ था. एक आना मतलब छह पैसे हुआ करता था. इस लिहाज़ से 25 पैसे को चार आना या चवन्नी कहते थे. एक रुपये का मतलब 16 आना हुआ करता था. 1957 में दशमलव पद्धति के आने के बाद आना को ख़त्म कर एक रुपये को 16 आने के बजाय 100 पैसे के समतुल्य माना गया. 1963 में तीन पैसे के सिक्के की शुरुआत हुई. 1968 में 20 पैसे का सिक्का प्रचलन में आया. महंगाई के बढ़ने के साथ ही 1970 में एक, दो और तीन पैसे के सिक्कों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. 1982 में एशियाड के वक़्त दो रुपये का सिक्का बाज़ार में उतारा गया. 1992 में चवन्नी से थोड़ा बड़ा पांच रुपये का सिक्का चलन में लाया गया, वहीं 2006 में 10 रुपये का सिक्का जारी किया गया था. अब चवन्नी इतिहास में सिमट कर रह जाएगी.

–नवीन कुमार मनीष, वज़ीराबाद, दिल्ली.

लोकायुक्त करोड़पति हो गए

एक मंत्री की वजह से देश की जनता को एक लाख 76 हज़ार करोड़ रुपये का चूना लग जाता है और वही जनता अगर उस भ्रष्ट मंत्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो बहुत संभव है कि उसे देशद्रोही बताकर सलाख़ों के पीछे क़ैद कर दिया जाए. यह भी संभव है कि उक्त मंत्री को अपने किए की कोई सज़ा भी न मिले. आज़ादी के बाद अब तक ऐसा कम ही सुनने को मिला कि किसी मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में सज़ा मिली हो, क्योंकि रिश्वत लेकर फंसते हैं और रिश्वत देकर छूट जाते हैं. जैसे प्रदेशों में बैठे लोकायुक्त करोड़पति हो गए हैं, उसी प्रकार लोकपाल अरबपति हो जाएंगे.

–महेश चंद्र वर्मा, *ईमेल से.*

भूल सुधार

चौथी दुनिया के 7-13 मार्च 2011 के अंक में प्रकाशित आलेख-रामदेव के ख़िलाफ़ संत समाज मुखर में स्वामी चिन्मयानंद के नाम से जो छायाचित्र इस्तेमाल किया गया, वह दरअसल उनका न होकर किसी अन्य का था. इस ग़लती के लिए हमें खेद है

–संपादक

राजकमल प्रकाशन समूह
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274
लेखन विधा सम्मान 2011
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपए की किताबें

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें और प्रमाणपत्र दिया जाएगा
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

आपका और आपकी मुस्कराहट का शुक्रिया

अपने साथियों पर लिखना या टिप्पणी करना बहुत दु:खदायी होता है, क्योंकि हम इससे एक ऐसी परंपरा को जन्म देते हैं कि लोग आपके ऊपर भी लिखें. आप उन्हें आमंत्रित करते हैं. मैं यही करने जा रहा हूं. मैं अपने साथियों को आमंत्रित करने जा रहा हूं कि हमारे ऊपर जहां उन्हें कुछ ग़लत दिखाई दे, वे लिखें. मेरा संदर्भ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ देश के पांच संपादकों की बातचीत का है. इन पांच संपादकों में हिंदी के कम थे, अंग्रेजी के ज़्यादा थे. एक मराठी का था. ये संपादक देश की आस्था के पहरुए साबित नहीं हुए. किसी भी पत्रकार से यह आशा की जा सकती है, आशा की जानी चाहिए कि वह इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान के दु:ख, दर्द, आंसू, परेशानी, भूख-प्यास और मौत के प्रति ज़्यादा ध्यान देगा, उसकी ज़्यादा चिंता करेगा. और जब भी उसका सामना सरकार नामक संस्था से, चाहे सरकार नामक संस्था का कोई सचिव हो या निर्णय लेने वाला अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, से होगा तो उससे वह हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफ के बारे में ज़रूर बात करेगा. यह बातचीत वह जी हुज़ूरी या चापलूसी की भाषा में नहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आंख में आंख डालकर करेगा. प्रधानमंत्री ने जिन पांच संपादकों को बुलाया, सवाल है कि क्या ये पांच संपादक पत्रकारिता के इस बुनियादी सिद्धांत की कसौटी पर खरे उतरे, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री से देश के नागरिकों के सामने मौजूद समस्याओं के ऊपर बातचीत की?

देश के नागरिकों के सामने दो तरह की समस्याएं हैं. एक तो सतत चलने वाली समस्याएं हैं, जिनके हल होने हैं और जिन्हें हल होते-होते सालों बीत जाएंगे. पर कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जिनका रिश्ता अभी से जुड़ा हुआ है. क्या उन समस्याओं के ऊपर इन संपादकों ने एक आदर्श पत्रकार के नाते बातचीत की? इसका जवाब अगर ये संपादक ख़ुद दें तो ज़्यादा बेहतर होगा. पर हम विनम्रता से अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपसे चूक हो गई. अगर आपने यह चूक जान-बूझकर की है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और अगर आपने अनजाने में चूक कर दी है तो इसके लिए उन लोगों से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, जो आज महंगाई के शिकार हैं, जो आज भ्रष्टाचार के शिकार हैं, जो आज सरकारी अकर्मण्यता के शिकार हैं, जो आज के राजनीतिक तंत्र की बेरहमी के शिकार हैं. माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए कि लोगों का भरोसा पत्रकारों के ऊपर तब आकर टिकता है, जब वे हर जगह से निराश हो जाते हैं. निराशा भी इतनी गहरी होती है कि उनके सामने जीने-मरने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है. मरने से पहले वे एक बार चाहते हैं कि किसी भी तरह, सरकार से निराश होकर, हर जगह से निराश होकर वे पत्रकार के पास जाएं और अपना दु:ख-दर्द कहें. उन्हें भरोसा होता है कि अगर पत्रकार ने उनकी बात सुन ली और अपने अख़बार में लिख दी तो शायद उनकी सुनवाई उस जगह से हो सके, जहां से उनकी परेशानी पैदा हुई है या जो परेशानी का कारण है. यह विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है. यह विश्वास आज की तारीख़ में या तो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिला हुआ है या देश के पत्रकारों को. पत्रकारों में भी जो संपादक होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है. पर ऐसा क्यों होता है कि जब हम लिखते हैं तो सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लिखते हैं तो विश्लेषण करते हैं, जब हम लिखते हैं तो लोगों के दु:ख-दर्द को अपना विषय बनाते हैं, लेकिन जब हम किसी हुक्मरान से मिलने जाते हैं तो ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे हमारे मुंह पर ताला लग जाता है और हम वह कोई भी सवाल नहीं पूछ पाते, वह कोई भी संदर्भ नहीं उठा पाते, जिसे हम ख़ुद लिखते रहते हैं.

जिन पांच संपादकों को प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए बुलाया, उनमें किसी की भी इंटीग्रिटी के ऊपर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है. पर संदेह न होना एक चीज है और उनकी मुलाकात का नतीजा न निकलना दूसरी चीज. ये पांचों साथी जब प्रधानमंत्री से मिले तो इन्होंने प्रधानमंत्री से न किसानों की आत्महत्या के बारे में पूछा, न खाद के बढ़ते हुए दाम के बारे में पूछा, न देश में बढ़ती महंगाई के बारे में पूछा, न प्रधानमंत्री से उनके द्वारा की गई घोषणाओं का वक़्त बीतने के बाबत पूछा कि आपने ये-ये घोषणाएं की थीं कि इस-इस समय यह-यह हो जाएगा, वैसा क्यों नहीं हुआ और आपने लोगों से यह भी नहीं कहा कि उस समय हम अपने इन वायदों को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए देश उन्हें क्षमा करें. ये सवाल प्रधानमंत्री से होने चाहिए थे. मौजूदा प्रधानमंत्री जब वित्त मंत्री थे और नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने नई आर्थिक नीति की घोषणा करते हुए अपना मशहूर भाषण दिया था कि 2012 तक इस देश में बिजली की समस्या, ग़रीबी की समस्या या कहें कि जितनी भी बड़ी-बड़ी समस्याएं थीं, सब सुलझ जाएंगी. इसलिए आर्थिक नीतियां बदल गई हैं. हमारे संपादकों को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था कि देश आज कहां है. जब इन्होंने घोषणा की थी सन् 92 में, उस समय और आज की स्थिति में क्या कोई फ़र्क़ है? क्या लोगों की ज़िंदगी में कुछ ख़ुशहाली आई है? समस्याएं, जिन्हें दूर करने का इन्होंने वायदा किया था, उन्हें हल होने में अब और कितने साल लगेंगे? देश का वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री कोई वायदा करता है तो उस वायदे का कोई मतलब होता है. इसी तरह प्रधानमंत्री ने अभी साल भर पहले बताया था कि मार्च महीने तक महंगाई कम हो जाएगी. ऐसा नहीं हुआ. क्या प्रधानमंत्री से इन संपादकों ने पूछा?

देश में किसानों द्वारा आत्महत्या हो रही है, क्या यह सवाल इन संपादकों के दिमाग़ में नहीं आया? इस देश का अल्पसंख्यक अपनी हिस्सेदारी के लिए तड़प रहा है, उसे सिर्फ़ वायदे ही वायदे मिल रहे हैं. क्या कांग्रेस या मौजूदा सरकार ने उससे किए वायदे पूरे किए? क्या इस बारे में कोई सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया? प्रधानमंत्री ने माइनॉरिटी के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया था, वह कार्यक्रम कितना सफल हुआ, क्या इस बारे में संपादकों ने प्रधानमंत्री से पूछा? पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि वायसराय जब अपने वायसराय हाउस में, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, दावत देता था तो कुछ पत्रकारों को भी बुलाता था. पत्रकार वहां जाकर बहुत ख़ुशी के साथ दावत का लुत्फ़ उठाते थे और जब बाहर निकलते थे तो शान से आसपास देखते थे अपने साथियों की तरफ़ और देखने का भाव होता था कि देखा, तुम्हें नहीं बुलाया, मुझे बुलाया. नतीजे के तौर पर, जिन्हें नहीं बुलाया जाता था, वे पत्रकार इस कोशिश में लग जाते थे कि अगली बार उन्हें भी बुलाया जाए. हमारे साथी प्रधानमंत्री के यहां गए, उन्हें चाहिए था कि वे प्रधानमंत्री का मूड इंटरव्यू करते. जब वे सवाल पूछ रहे थे तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर क्या भाव आए, प्रधानमंत्री की आंखों ने क्या कहा, प्रधानमंत्री का शरीर तिलमिलाया, कसमसाया या नहीं कसमसाया? हालांकि उन्होंने सवाल पूछे ही नहीं तो उनके मूड इंटरव्यू का कोई मतलब ही नहीं होता. पर फिर भी, जो भी वहां बातचीत हुई, उसे सबसे पहले उन्हें अपने दफ्तर में जाकर, अपनी टेबल पर बैठकर लिखना चाहिए था और पांचों संपादकों को पांच एक्सक्लूसिव राइटअप अपने अख़बारों में देने चाहिए थे.

ये पांचों संपादक वहां अपने अख़बार के संपादक के नाते नहीं गए थे. सारा देश इन्हें देख रहा था कि ये देश के पहले चुने हुए संपादक हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने मिलने के लिए बुलाया है. इनसे लोगों की अपेक्षाएं थीं कि ये उनकी तकलीफ़, दु:ख-दर्द के बारे में वहां बात करेंगे. लेकिन वहां जो बातचीत हुई, वह हमारे सामने है. मूलभूत विषयों के ऊपर, आज की समस्याओं के ऊपर बातचीत नहीं हुई. महज़ समस्याओं के इर्द-गिर्द जाकर ही बातचीत हुई. इन संपादकों ने यह नहीं पूछा कि आख़िर प्रधानमंत्री को क्यों यह कहने की ज़रूरत पड़ गई कि पार्टी उनके साथ है और वह स्थिर हैं, मज़बूत हैं, वह त्यागपत्र नहीं देंगे. यह सवाल खड़ा किया जाना चाहिए था. कोई तो रीज़न होगा, अफ़वाहें कौन उड़ा रहा है, ये अफवाहें भाजपा उड़ा रही है या कांग्रेस? ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया. इसकी जगह पर हमारे साथी जब प्रधानमंत्री निवास से बाहर निकल कर आए तो विजेता की तरह निकल कर आए. उन्होंने बाहर आकर प्रधानमंत्री कैसे थे, क्या था. यानी कुल मिलाकर उन्होंने जो वर्णन किया, वह प्रधानमंत्री का महिमा मंडन था. प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है और उसका कंसर्न देश के कंसर्न के साथ है या नहीं, यह उन्होंने नहीं बताया.

पत्रकारिता का पेशा बहुत अहम पेशा होता है. पत्रकारों को लोगों के हितों का पहरुआ माना गया है. सरकार के हितों का पहरेदार सच्चा पत्रकार नहीं होता. यही चीज हमारे साथी भूल गए हैं. हम ख़ुद व्यक्तिगत जीवन में अच्छे हैं या बुरे, यह सवाल नहीं है. संपादक का यह धर्म है, पत्रकारिता का यह धर्म है, इस पेशे का धर्म है कि हम जनता के दु:ख-दर्द, उसकी तकलीफ और उसके आंसू के बारे में सरकार से पूछें, अधिकारियों से पूछें, मुख्यमंत्री से पूछें और प्रधानमंत्री से तो ज़रूर पूछें. जब हम यह काम नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं पत्रकारिता के पेशे के साथ न्याय नहीं करते. मैं और भी कठोर शब्द इस्तेमाल कर सकता था कि हम पत्रकारिता के पेशे के साथ क्या-क्या नहीं करते. पर आज मुझे यही कहना चाहिए कि हम न्याय नहीं करते. हम उस पेशे के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को जोड़ देते हैं. हम रिश्ता बनाने लगते हैं. हम किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की एक मुस्कान के ताबेदार हो जाते हैं. उसने अगर हमें देखकर एक मुस्कराहट फेंक दी तो लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं. ऐसा नहीं है. अगर आपके लिखने से चंद लोगों की आंखों के आंसू पुंछ सकें और उन्हें लगे कि जो शख्स गया था, उसने उनकी तकलीफ के बारे में देश के सबसे बड़े निर्णायक आदमी से सवाल पूछा तो शायद उन्हें थोड़ा ढांढस बंधे. यह सवाल पत्रकारों के सोचने के लिए है, संपादकों के सोचने के लिए है. वक़्त आ गया है कि सोचें.

हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री निवास या प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार या उनके यहां जो भी इस चीज को ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं, वे उन संपादकों और पत्रकारों को कभी नहीं बुलाएंगे, जो जनता के पक्ष में लिखते हैं. जो यद्यपि पूरी तरह न सरकार विरोधी हैं और न सरकार के पक्षधर, लेकिन जो जनता के दु:ख-दर्द को समझने वाले हैं. जिनका बुनियादी फ़र्ज़ जनता की तकलीफों को उठाना है. जो जनता की तकलीफों को मैग्निफाइंग ग्लास से देखकर सरकार को दिखाना अपना कर्तव्य समझते हैं. हम जानते हैं, वे देश के प्रति चिंता रखने वाले ऐसे पत्रकारों को प्रधानमंत्री से बात करने के लिए नहीं बुलाएंगे. पर जिन्हें भी बुलाएंगे, वे पत्रकार होंगे या संपादक होंगे और आगे यह कड़ी जारी रहने वाली है, ऐसा इंप्रेशन प्रधानमंत्री निवास की तरफ से आया है. अगर ऐसा है तो जो पत्रकार आगे जाने वाले हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए. हमारा विनम्र निवेदन है कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री से इस देश के लोगों की तकलीफों के बारे में भी पूछें और उन्हें एक आईना दिखाएं, सही पत्रकार होने के नाते आईना दिखाएं कि देश ऐसा है, आप यह बोल रहे हैं, दोनों में कहीं कोई तारतम्य है क्या? सोचना उन संपादकों या पत्रकारों को है, जो आगे प्रधानमंत्री से मिलने जाने वाले हैं. जो मिलकर आए और उन्होंने जो कहा, उसके लिए उन्हें और उनकी मुस्कराहट को शुक्रिया के अलावा हम और क्या कह सकते हैं.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

राम पुनियानी

दंगा मुक्त भारत की ओर

विभाजन के बाद भारत में पहला सांप्रदायिक दंगा 1961 में जबलपुर में हुआ, तबसे दंगों का सिलसिला अनवरत जारी है. 1980 के दशक में सांप्रदायिक हिंसा में ज़बरदस्त बढ़ोत्तरी हुई. विभिन्न समुदायों के बीच शांति एवं सौहार्द स्थापित करने की राह में सांप्रदायिक दंगे बहुत बड़ा रोड़ा बन गए हैं. सबसे भयावह थी सिख विरोधी हिंसा (1984), बाबरी कांड के बाद मुंबई में भड़की मुस्लिम विरोधी हिंसा (1992-93) और गुजरात क़त्लेआम (2002). ईसाई विरोधी हिंसा की शुरुआत छुटपुट घटनाओं से हुई, परंतु पास्टर ग्राहम स्टेंस की हत्या (1999) और कंधमाल हिंसा (2008) से यह स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों के साथ-साथ ईसाई भी सांप्रदायिक तत्वों के निशाने पर हैं. सांप्रदायिक हिंसा के नासूर से देश को मुक्ति दिलाने के लिए यूपीए सरकार ने एक विधेयक पेश किया, जो वर्तमान में राज्यसभा में लंबित है. किन्हीं कारणों से यह विधेयक रोग से बदतर इलाज साबित हुआ. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं अल्पसंख्यकों के संगठनों ने इस विधेयक की कमियों को उजागर किया. इसके बाद यूपीए-2 सरकार ने एक नया दंगा निरोधक क़ानून बनाने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को सौंपी. परिषद के दो सदस्यों (फराह नकवी एवं हर्ष मंदर) के संयोजन में नए विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए एक सलाहकार समूह का गठन हुआ. लगभग डेढ़ साल की कड़ी मशक्कत के बाद बीते मई माह में इस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया. मसौदे को कई वेबसाइटों पर रखा गया है. आम लोगों की प्रतिक्रिया के अध्ययन के आधार पर उपयुक्त संशोधन किए जाने के बाद इसे सरकार को सौंपा जाएगा. मसौदे के अध्ययन से स्पष्ट है कि यह देश में सांप्रदायिक हिंसा पर नियंत्रण पाने का एक महत्वपूर्ण, गंभीर एवं प्रभावी प्रयास है.

इस मसौदे में उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा गया है, जो सांप्रदायिक हिंसा को हवा देते हैं और पीड़ितों को न्याय मिलने की प्रक्रिया में बाधक बनते हैं. मसौदे में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, पीड़ितों के पुनर्वास और उनके नुक़सान की भरपाई जैसे अब तक अनछुए मसलों के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं. यह मानने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मसौदे में कुछ कमियां हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विधेयक राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को मज़बूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. इसके बावजूद भाजपा नेतृत्व (विशेषकर अरुण जेटली) और मीडिया के एक तबके ने इस विधेयक का विरोध शुरू कर दिया है. प्रचार किया जा रहा है कि यह विधेयक केवल अल्पसंख्यकों (मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन) के विरुद्ध हिंसा पर केंद्रित है और इसमें बहुसंख्यकों के ख़िलाफ़ होने वाली सांप्रदायिक हिंसा को नज़रअंदाज़ किया गया है. विधेयक का विरोध करने वाले यह भूल रहे हैं कि इसमें अल्पसंख्यकों को केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है. अल्पसंख्यकों की परिभाषा में भाषाई अल्पसंख्यक भी शामिल हैं. इसमें अनुसूचित जातियों-जनजातियों के विरुद्ध हिंसा से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं. यह विधेयक सांप्रदायिक हिंसा के छह दशकों से अधिक के इतिहास के अनुभवों का निचोड़ है, जो हमें बहुत कुछ बताता है. 1991 में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि यद्यपि मुसलमानों का देश की आबादी में हिस्सा मात्र 12.4 प्रतिशत है, तथापि दंगों में मारे जाने वाले लोगों में 80 प्रतिशत मुसलमान होते हैं. ईसाइयों के विरुद्ध हिंसा से संबंधित आंकड़े भी सबके सामने हैं. दलितों एवं आदिवासियों को हिंसा का निशाना बनाया जाना आम है. विधेयक में इन वर्गों के ख़िलाफ़ हिंसा की रोकथाम के लिए किए गए विशेष प्रावधान पूरी तरह जायज़ हैं.

ये प्रावधान उसी तरह के हैं, जिस तरह के प्रावधान घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में किए गए हैं. घरेलू हिंसा की शिकार मुख्यत: महिलाएं होती हैं. इसी तरह यद्यपि अपवादस्वरूप उच्च जातियों के सदस्य भी दलितों की हिंसा का शिकार बनते हैं, तथापि अधिकांश मामलों में दलित एवं आदिवासी पीड़ित होते हैं. इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुषों के विरुद्ध हिंसा करने वाली महिलाओं या उच्च जातियों के सदस्यों पर हमला करने वाले दलितों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. इसी प्रकार अल्पसंख्यकों की हिंसा में जान-माल गंवाने वाले बहुसंख्यकों को भी न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए वर्तमान क़ानूनों में पर्याप्त प्रावधान हैं. कहने की आवश्यकता नहीं कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध

सुनियोजित दंगों में भी कुछ बहुसंख्यकों को नुक़सान पहुंच सकता है. उन्हें न्याय दिलाना व्यवस्था का कर्तव्य है और इसके लिए क़ानूनी रास्ते उपलब्ध हैं. क्या प्रस्तावित विधेयक हिंदू बहुसंख्यकों की उपेक्षा करता है? हमें यह ध्यान रखना होगा कि विधेयक में अल्पसंख्यकों की परिभाषा में धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के अलावा दलित एवं आदिवासी शामिल हैं. भारत के सात राज्यों (जम्मू-कश्मीर, पंजाब, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एवं अंडमान-निकोबार) में हिंदू अल्पसंख्यक हैं. कई राज्यों में हिंदू एवं भाषायी अल्पसंख्यक भी हैं. जैसे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय, हिंदीभाषी हिंदू. इसी तरह दलितों एवं आदिवासियों में भी हिंदू शामिल हैं. यह विधेयक कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने में भी सहायक होगा, क्योंकि उस राज्य में वे अल्पसंख्यक हैं.

भाजपा बेवजह दुष्प्रचार कर रही है कि विधेयक में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम की व्यवस्था नहीं है. विधेयक का मुख्य लक्ष्य सामूहिक हिंसा को रोकना है, जिसके शिकार अधिकांश मामलों में अल्पसंख्यक होते हैं. पुलिस, नौकरशाही एवं राज्य तंत्र के पूर्वाग्रहों के शिकार भी अल्पसंख्यक होते हैं. यह तथ्य कई अध्ययनों से उजागर हुआ है. पुलिस अधिकारी डॉ. विभूति नारायण राय द्वारा किए गए एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि बहुसंख्यकवादी राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा माहौल बना दिया जाता है, जिसमें अल्पसंख्यक स्वयं को उपेक्षित-आतंकित महसूस करने लगते हैं. उनके विरुद्ध इतनी घृणा फैलाई जाती है कि वे अपना आपा खो बैठते हैं. ऐसे में कई बार पहला पत्थर उनकी ओर से फेंका जाता है और आगे का काम अल्पसंख्यकों के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रस्त पुलिस संभाल लेती है. इस विधेयक का लक्ष्य है सुनियोजित एवं सामूहिक हिंसा पर लगाम लगाना. विधेयक का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें उन अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय की गई है, जो लापरवाही के चलते या जानबूझ कर हिंसा को नहीं रोकते. कई बार वे राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा करते हैं. डॉ. राय के अनुसार, प्रशासन की मिलीभगत के बग़ैर कोई भी दंगा 48 घंटों से अधिक नहीं चल सकता. विधेयक में उन राजनीतिज्ञों को कठघरे में खड़ा करने की व्यवस्था है, जिनके इशारे पर और संरक्षण में असामाजिक तत्व सड़कों पर तांडव करते हैं. जो राजनीतिक ताक़तें इस सुनियोजित हिंसा के पीछे होती हैं, उन्हें क़ानून की गिरफ़्त में लाने के लिए भी इस विधेयक में प्रावधान है. इसमें कमज़ोर समूहों के विरुद्ध घृणा फैलाने और उनका सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार करने वालों से निपटने की व्यवस्था भी है.

भाजपा सहित संघ परिवार के बाल-बच्चों को विधेयक का मसौदा पढ़ते ही सांप क्यों सूंघ गया है. यह विधेयक उनके हिंदू राष्ट्र के निर्माण के सपने की राह का रोड़ा बन जाएगा. विधेयक सांप्रदायिक दंगों पर प्रभावी नियंत्रण करने में सहायक सिद्ध होगा. यह एक ऐसे बहुवादी भारत के निर्माण में मदद करेगा, जिसमें सभी समुदायों के लोग इज़्ज़त से जी सकें. ऐसा होना भाजपा को अपने हितों के ख़िलाफ़ लगता है. विधेयक इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सांप्रदायिक हिंसा हमारी राजनीति को संकीर्णता एवं अराजकता की ओर ले जा रही है और राज्य का कर्तव्य है कि वह हमारी राजनीति की दिशा सकारात्मकता, उदारता एवं सहिष्णुता की ओर मोड़े. राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि हिंसा पीड़ितों का पुनर्वास हो, उन्हें नुक़सान का मुआवज़ा मिले और हिंसा के बाद उनका सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार न हो. इस संदर्भ में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है. विधेयक में प्रावधान होने चाहिए कि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बग़ैर केंद्र सरकार सामूहिक हिंसा की घटनाओं पर पैनी नज़र रख सके. इसके लिए विधेयक में कुछ परिवर्तन करने होंगे. ज़रूरत इस बात की है कि न्याय प्रणाली को दुरुस्त किया जाए और पीड़ितों का सशक्तिकरण हो. विधेयक में सांप्रदायिक सद्भाव, न्याय और नुक़सान की भरपाई के लिए राष्ट्रीय अभिकरण के गठन का प्रस्ताव है. इसके सात सदस्य होंगे, जिनमें चार अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि होंगे. आशा है कि इस संस्था को चुनाव आयोग की तरह पर्याप्त शक्तियां दी जाएंगी, ताकि वर्तमान ढांचे से छेड़छाड़ किए बग़ैर संबंधित अधिकारियों और सरकारी संगठनों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

जूस का नियमित प्रयोग करने से आंखें, दिल, दिमाग़ सब स्वस्थ रहते हैं. एक नई खोज के मुताबिक़, फलों के रस इंसान को सेक्सी भी बनाते हैं.

सूचना का अधिकार — जानने का अधिकार जीने का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

सांसद निधि : कहां और कितना ख़र्च हुआ

विकास कार्य के लिए आपके स्थानीय सांसद को हर साल करोड़ों रुपये मिलते हैं. इसे सांसद स्थानीय विकास फंड कहा जाता है. इस फंड से आपके क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य किए जाने की व्यवस्था होती है. लेकिन क्या कभी आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद निधि से हुए विकास कार्यों के बारे में जानने की कोशिश की? क्या आपने कभी यह सवाल पूछा कि आपके इलाक़े में सांसद फंड से कितना काम हुआ है? आप उस वक़्त को याद कीजिए, जब कोई नेता आपसे वोट मांगने आता है तो वह आपसे कहता है कि आप उसे वोट दें, ताकि वह अगले पांच सालों तक आपकी सेवा करता रहे यानी इस हिसाब से देखें तो जनता मालिक और नेता सेवक. लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है? क्या आपको यह पता चलता है कि आपके सांसद को क्षेत्र का विकास करने के लिए जो करोड़ों रुपये सरकार की तरफ़ से मिलते हैं, वे कहां जाते हैं? आपके क्षेत्र के विकास में सांसद निधि का कितना इस्तेमाल हुआ? कहीं सांसद के चहेतों के बीच उस फंड का बंदरबांट तो नहीं हो गया अथवा फिर ठेकेदार और नेता जी मिलकर इस फंड को हजम तो नहीं कर गए? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे, लेकिन आप ये सवाल अपने सांसद से नहीं पूछते. वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल न पूछ कर आप एक तरह से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देते हैं. ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप सवाल पूछें, ताकि व्यवस्था और आपके सांसद पर दबाव बन सके. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि बिना कोई काम किए या आधा-अधूरा काम करके अब तक जो पैसा भ्रष्ट लोगों की जेब में चला जाता था, वह आपके क्षेत्र के विकास में काम आएगा. ऐसा नहीं है कि एक आवेदन देने भर से ही परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका अकेला आवेदन भी उन भ्रष्ट लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए काफी होगा कि जनता अपने सेवकों पर लगाम लगाना जानती है. यदि आप सचमुच परिवर्तन चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को ऐसे आवेदन डालने के लिए प्रेरित करें. ज़ाहिर है, जब ज़्यादा संख्या में लोग सवाल पूछेंगे तो इससे बनने वाले दबाव का असर भी उतना ही ज़्यादा होगा. चौथी दुनिया आपके हर क़दम पर आपके साथ है. किसी भी समस्या या सुझाव के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. इस अंक में हमने सांसद निधि से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित किया है. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301, ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

सेवा में, **दिनांक.....**

लोक सूचना अधिकारी
जिलाधिकारी कार्यालय
पता.....

विषय: सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

मैं....(नाम)...(गांव का नाम) का निवासी हूं. मेरा लोकसभा क्षेत्र...(क्षेत्र का नाम) है. कृपया इस लोकसभा क्षेत्र में वर्ष....से वर्ष.....के बीच सांसद निधि से कराए गए विकास कार्यों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. प्रत्येक विकास कार्य का नाम.
2. प्रत्येक विकास कार्य का विस्तृत विवरण.
3. प्रत्येक विकास कार्य के लिए जारी रकम.
4. प्रत्येक विकास कार्य शुरू और खत्म होने की तिथि.
5. प्रत्येक विकास कार्य की प्रगति रिपोर्ट, वर्तमान स्थिति.
6. प्रत्येक विकास कार्य करने वाली एजेंसी का नाम.
7. किस दर पर प्रत्येक विकास कार्य ठेकेदार/एजेंसी को दिया गया?
8. अब तक कितना पैसा ठेकेदार/एजेंसी को दिया गया?
9. प्रत्येक विकास कार्य की रूपरेखा (स्केच) की एक कॉपी.
10. प्रत्येक विकास कार्य को करने के लिए किस तरह से निर्णय लिए गए?
11. प्रत्येक विकास कार्य के लिए कितना पैसा अब तक स्वीकृत हो चुका है और अभी कितना पैसा स्वीकृत होना बाकी है?
12. कितने विकास कार्यों के लिए अब तक पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है? इसका कारण क्या है?

मैं बतौर आवेदन शुल्क.....रुपये जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम.....
हस्ताक्षर.....
पता.....

ज़रा हट के

फलों के रस सेक्सी बनाते हैं

अभी तक आपने जूस पीते वक़्त शायद सोचा भी नहीं होगा कि इसका संबंध सेक्स क्षमता से भी हो सकता है. दोस्तों, गर्मी का मौसम है, इस चुभती गर्मी में सिर्फ़ एक गिलास जूस अगर आप सुबह-शाम पीते हैं तो आपको किसी हेल्थ टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यह जूस जहां आपके शरीर में होने वाली पानी की कमी को पूरा करेगा, वहीं आपको तरोताजा भी रखेगा. आपको बता दें, एक गिलास फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस पीने से आपके शरीर में रक्त संचार ठीक से होगा, जिसके चलते आपकी त्वचा कील-मुंहासों से दूर रहेगी. सब्जियों के जूस तो त्वचा को निखारने का भी काम करते हैं.

जूस का नियमित प्रयोग करने से आंखें, दिल, दिमाग़ सब स्वस्थ रहते हैं. एक नई खोज के मुताबिक़, फलों के रस इंसान को सेक्सी भी बनाते हैं. ख़ासकर तरबूज और बेल के रस का सेवन करने से मनुष्य में सेक्स क्षमता का भी विकास होता है. जूस से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे इंसान रोगों की चपेट में नहीं आता है. लेकिन आप जो भी जूस पीजिए, वह साफ-सुथरा और ताजे फलों या सब्जियों का बना होना चाहिए.

जूस से आपकी खुराक भी बढ़ती है, जिससे आपके पाचन संबंधित रोग दूर होते हैं. सारी बीमारियां पेट के कारण होती हैं, इसलिए अगर पेट सही रहेगा तो इंसान ख़ुद-ब-ख़ुद स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा. इसलिए आप आज से ही बाज़ार के शीतल पेय बंद करके ताजे फलों एवं सब्जियों के जूस का सेवन शुरू कर दीजिए, फ़र्क़ आप ख़ुद ही महसूस करेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आपका नाम क्या है?

आप अपने नाम के पहले अक्षर पर ग़ौर कीजिए. कहीं आपका नाम ई से तो नहीं शुरू होता है? अगर ऐसा है तो आप दिलफेंक किस्म के इंसान हैं. यदि किसी लड़की या लड़के का नाम अंग्रेजी के ई अक्षर से शुरू होता है तो आप जान जाइए कि वह इंसान बहुत बोलने वाला है. उसे लोग बातूनी भी कहते हैं. वह मज़ाकिया स्वभाव का होता है, लेकिन अपने ज़्यादा बोलने के कारण ऐसे लोग हमेशा ख़तरे में पड़ जाते हैं. इन्हें लोगों से वैसे ही व्यवहार की अपेक्षा होती है, जैसे ये लोगों से करते हैं. अगर इन्हें अपने व्यवहार जैसा बर्ताव नहीं मिलता तो ये किसी को भी खरी-खोटी सुना देते हैं.

इसलिए ये लोग बड़े ही दिलफेंक होते हैं. विपरीत सेक्स के प्रति ये काफी आकर्षित होते हैं. इसलिए इनके दोस्तों की संख्या काफी होती है. इन्हें एक से ज़्यादा बार मुहब्बत भी हो सकती है, लेकिन ये जो रिश्ता बनाते हैं, उसके प्रति ईमानदार होते हैं. मतलब यह कि भले ही ये चार लोगों से मोहब्बत करें, लेकिन अगर किसी से शादी करते हैं तो अपने हमसफर के प्रति ईमानदार होते हैं. इन्हें पार्टियों में जाना अच्छा लगता है. ये ज़िंदगी को आसानी से जीते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते, इसलिए इन्हें कोई कमी महसूस नहीं होती. इनके पास शिक्षा, व्यवसाय, रुतबा और पैसा उतना ही होता है, जितने की इन्हें चाहत होती है. ये हमेशा ख़ुश रहने वाले होते हैं. इसलिए इन्हें लोग काफी पसंद भी करते हैं. इनकी सेक्स लाइफ काफी मज़ेदार होती है. ऐसे लोग जब तक जीना है, ख़ुशी से जीना है वाले सिद्धांत पर चलते हैं, इसलिए हमेशा सुखी रहते हैं.

राशिफल

मेष — 21 मार्च से 20 अप्रैल

किसी चहेते के साथ किसी बात पर ग़लतफ़हमी हो तो उसके लिए आप अपना पक्ष रखने की कोशिश कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के चलते हो सकता है कि आपके किसी ज़रूरी काम में विलंब हो जाए. फिर भी आप एडवांस में ही अपने ज़रूरी काम निपटा लें.

वृष — 21 अप्रैल से 20 मई

इस सप्ताह किसी कारण आपकी जेब में पैसा नहीं टिक सकता है. कोई अर्जेंट डाक या मेल की प्रतीक्षा करनी भी ज़रूरी है. हो सकता है, सप्ताह मध्य के बाद किसी बड़े आदमी या सिलेब्रिटी से आपकी मुलाक़ात हो जाए.

मिथुन — 21 मई से 20 जून

यह सप्ताह आप अपने घर-परिवार के बिखरे सदस्यों को एक करने में लगाएंगे और मेहमानदारी या आवभगत के कार्यों में व्यस्त रहेंगे. सप्ताह मध्य तक आपके हाथों से किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा या फिर कहीं पर बैठकर रंगीन शाम का जायज़ा लिया जाएगा.

कर्क — 21 जून से 20 जुलाई

जिस महत्वपूर्ण कार्य में लगातार बाधा आ रही है, इस सप्ताह उसके बनने की संभावना है. हो सकता है, अभी भी आपको इस बात की शंका हो कि सफलता मिलेगी या नहीं. सप्ताह के मध्य में इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि आप अपने वेंचर में कामयाब हैं.

सिंह — 21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह अपने कामकाज से आप उत्साहित रहेंगे. दूसरों की गिरती छवि के आगे आपकी पर्सनैलिटी कुछ ज़्यादा ही असरदार नज़र आ रही है. सप्ताह मध्य के बाद किसी आमंत्रण या महत्वपूर्ण सूचना से आपकी गतिविधि और भी हैक्टिक हो जाएगी.

कन्या — 21 अगस्त से 20 सितंबर

इस सप्ताह यदि आपको अपने ठौर-ठिकाने से कहीं दूर या विदेश में कारोबार या नौकरी का प्रस्ताव मिल रहा है तो उसके लिए स्वीकृति दे दें. वैसे ऐसे काम स्वीकृति के बाद भी लंबा समय ले सकते हैं. इसके संपादन में आप तभी सफल हो पाएंगे, जब आज से ही अपने बैकलॉग को क्लीयर करने में जुट जाएंगे.

तुला — 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

काफी समय से लगातार मंदी और धन की आवक पर रोक लगने से खिन्नता और उदासी का सामना करना पड़ रहा है. इस सप्ताह स्थिति कुछ बदली हुई नज़र आ रही है. सप्ताह के मध्य तक फाइनेंस की समस्या भी ख़त्म हो रही है और लाभदायक डील होने से भी फीलगुड का माहौल बन रहा है.

वृश्चिक — 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

जल्दबाज़ी से कभी-कभी फ़ायदा भी होता है. यद्यपि इस सप्ताह आपकी व्यस्तता कई प्रकार के झंझटों से भरी है, फिर भी जिस अंदाज़ में आप अपने साजोसामान का ख्याल रखते हैं, उससे चोर-उचक्कों की नज़र आप पर हो सकती है.

धनु — 21 नवंबर से 20 दिसंबर

इस सप्ताह रिलेशनशिप यानी प्यार के मामले में कुछ उलझनें आपके सामने रहेंगी. पैसे आदि के लेनदेन पर अभी कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होगा. किसी नए काम की शुरुआत के लिए आगे क़दम बढ़ाना इस वक़्त की मांग है.

मकर — 21 दिसंबर से 20 जनवरी

इस सप्ताह आप अपने प्रोग्राम में काट-छांट न करें. एक बार क़दम उठ जाने पर पीछे मुड़ना ठीक नहीं होगा. जिस दिशा में आप जा रहे हैं, वहां से आगे अब कोई अल्टरनेट नहीं है. अत: भरपूर ताक़त लगाकर कार्य पूरा करने की सोचें.

कुंभ — 21 जनवरी से 20 फरवरी

किसी प्रतिबंधित या सुरक्षा पूर्ण एरिया में प्रवेश करने से आपको परेशानी हो सकती है. यदि वाहन चला रहे हों तो जल्दबाज़ी या हड़बड़ी से बचें. अगर कोई विचार आपको उत्तेजित कर रहा है तो कंट्रोल रखें. सप्ताहांत तक मानसिक स्थिरता आ जाएगी और आप गलती करने से भी बच जाएंगे.

मीन — 21 फरवरी से 20 मार्च

इस सप्ताह आप किसी ख़ास मसले पर अपने वरिष्ठों या घर के बुज़ुर्गों से मशविरा कर सकते हैं. लोगों को दिखाने के लिए आपको अपने सभी दरवाजे खोलने होंगे. यदि कोई आपके अंदर विशेष रचनात्मक या क्रिएटिव अंदाज़ देख रहा हो तो यह उसके और आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

बहरहाल, ताजा हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि अमेरिका और चीन के पास दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग हैं.

अमेरिका-चीन संबंध

दिखावे के लिए दुश्मन

विश्व के हालात अब ऐसे हो रहे हैं कि न अमेरिका अकेली विश्व शक्ति बना रह सकता है और न वह पीछे हट सकता है. यह अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण समय है. चीन शक्ति के रूप में अमेरिका का मुक़ाबला करने के लिए विश्व में सबसे प्रबल दावेदार है. चीन के जटिल इतिहास की रोशनी में अमेरिका के लिए यह चुनौती और भी मुश्किल हो जाती है.

राजीव रंजन तिवारी

पाकिस्तान में जब अलक़ायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन मारा गया तो अमेरिका की नज़रें कुछ समय के लिए पाकिस्तान के प्रति टेढ़ी हो गईं. तब चीन ने इशारे-इशारे में कह दिया कि वह पाकिस्तान का बाल बांका नहीं होने देगा. इसके अलावा जब कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में लड़ रहे थे तो अमेरिका दक्षिण कोरिया की मदद में जुटा था, जबकि चीन उत्तर कोरिया का कवच बना बैठा था. न जाने इस तरह के कितने उदाहरण हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि अमेरिका और चीन के बीच ज़बरदस्त कटुता है. लेकिन हक़ीक़त कुछ और है. दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते दुनिया को बरगला रहे हैं. यदि इतिहास पर नज़र डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अमेरिका और चीन के बीच के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं. आज भले दिखावे के लिए दोनों देश एक-दूसरे की समय-समय पर खिंचाई कर दें, लेकिन इनके बीच की प्रगाढ़ता कुछ और ही बयां कर रही है. संदेश यह है कि भारत समेत दुनिया के अन्य तमाम देश यह ग़लतफ़हमी कतई न पालें कि चीन और अमेरिका के रिश्ते तल्ख हैं और इस तल्खी का उन्हें लाभ मिल सकता है. नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में ख़ुलासा किया है कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध में अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन अपनी सेना भेजे. इसके लिए उसने चीन से पहल भी की थी. अमेरिका की पेशकश थी कि पाकिस्तान का साथ देने की स्थिति में रूस अगर चीन पर हमला करता है तो चीन की ओर से अमेरिका भी मैदान में उतर जाएगा. जबकि रूस उस वक़्त भारत का दोस्त था. किसिंजर की किताब ऑन चाइना में हुए इस ख़ुलासे को पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका को पाकिस्तान का पुराना और वफ़ादार दोस्त बताने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित कर रहा है. किताब में इस बात का भी उल्लेख है कि 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में सैन्य मदद मांगने के लिए किसिंजर ख़ुद चीन से मिले थे. उन्होंने चीन से यह वादा किया था कि यदि रूस युद्ध में आता है तो चीन और पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा हो जाएगा. यह पहला मौक़ा था, जब चीन-रूस और अमेरिकी रिश्तों के बीच युद्ध को लाने का ख़तरा उठाया गया था. उस वक़्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन के विरोधी हमेशा उन पर पाकिस्तान की ओर झुके होने का आरोप भी लगाते थे.

अब इस ख़ुलासे को पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका को पाकिस्तान का पुराना दोस्त बताते हुए भुना रहा है. पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर जोर दे रहा है कि हम पाकिस्तानी अपने दुश्मन और दोस्त के बीच फ़र्क़ करना भी नहीं जानते. हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारे दोस्तों की भी अपने मुल्क की आंतरिक राजनीति के चलते कुछ मजबूरियां हैं. उस वक़्त अंतरराष्ट्रीय माहौल भी पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के पक्ष में था. ऐसे हालात में भी अमेरिका और चीन खुलकर पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहे थे. हालांकि कभी चीन को अमेरिका का दोस्त बताने वाले हेनरी किसिंजर की चीन के बारे में राय अब बदल गई है. किसिंजर मानते हैं कि चीन इस समय अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती है. यूं तो अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते पिछले 40 सालों से एक जैसे रहे हैं, लेकिन अब समीकरण बदल रहा है. वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद चीन में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है, जो मानते हैं कि अब दुनिया में विश्व शक्ति की धुरी बदल चुकी है. चीन अब बड़ी शक्ति बनकर उभरा है और अंतरराष्ट्रीय मामलों में चीन के दख़ल में यह बात दिखनी चाहिए. इसे लोगों को अमेरिका की ग़लती के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पिछले दो हज़ार वर्षों में से 1800 वर्षों पर चीन का दबदबा रहा है, जबकि पिछले 40 वर्षों पर ही अमेरिका का दबदबा है.

विश्व के हालात अब ऐसे हो रहे हैं कि न अमेरिका अकेली विश्व शक्ति बना रह सकता है और न वह पीछे हट सकता है. यह अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण समय है. चीन शक्ति के रूप में अमेरिका का मुक़ाबला करने के लिए विश्व में सबसे प्रबल दावेदार है. चीन के जटिल इतिहास की रोशनी में अमेरिका के लिए यह चुनौती और भी मुश्किल हो जाती है. बकौल किसिंजर, चीन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की रणनीति भी साफ है. अमेरिका को चाहिए कि वह चीन के साथ अपनी समझ को बढ़ाए और ऐसे रिश्ते स्थापित करे, जिनमें दोनों देशों को लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है. 23 सितंबर, 2008 को तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वन चापो ने न्यूयार्क में कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद व्हाइट हाउस का स्वामी चाहे कोई बने, लेकिन चीन-अमेरिका के रिश्ते पहले से मधुर रहे हैं और रहेंगे. यह ऐतिहासिक धारा उल्टा नहीं बह सकेगी. वन चापो ने पिछले वर्ष चीन-अमेरिका संबंधों के विकास का सिंहावलोकन किया और दोनों देशों के बीच राजनीति एवं अर्थ-व्यापार के क्षेत्रों में निरंतर मज़बूत हुए सहयोग के तथ्य और आंकड़े पेश किए. यही नहीं, उन्होंने मैत्री की कई कहानियां भी सुनाईं, जिससे वहां मौजूद लोगों में मित्रता की स्नेहपूर्ण याद ताजा हो गई. चीन और अमेरिका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, दोनों सहयोग के साझीदार हैं और हमेशा दोस्त बने रह सकते हैं.

इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि चीन तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे अमेरिका को क्षति पहुंचेगी, बल्कि वह भी चीन के विकास से लाभ पा सकता है. अमेरिका और चीन दोनों एक साथ विकसित हो सकते हैं. चीन की हार्दिक अभिलाषा है कि चीन-अमेरिका मैत्रीपूर्ण सहयोग भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बड़े देशों के मेलमिलाप से सह अस्तित्व होने और समान विकास के रास्ते पर आगे चलने की मिसाल बनेगा. वन चापो ने कहा कि उन्हें इसलिए चीन-अमेरिका संबंधों पर पक्का विश्वास हुआ है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापक समान हित मौजूद हैं. सहयोग के क्षेत्र द्विपक्ष के दायरे से कहीं अधिक विस्तृत हैं और उसका सारे विश्व पर अहम प्रभाव पड़ रहा है. इसलिए दोनों पक्षों को समानता वाली वार्ता के ज़रिए एक-दूसरे के प्रति आशंकाओं को दूर करना चाहिए, आपस में विश्वास बढ़ाना चाहिए. चीन और अमेरिका अब एक-दूसरे से सीख रहे हैं और एक-दूसरे के प्रशंसक बन गए हैं. अमेरिकी श्रम मंत्री एलैइन लान चाओ ने कहा कि चीन-अमेरिका संबंधों की मज़बूती विश्व शांति और स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है. इसलिए अमेरिका को चीन के साथ संपर्क और सहयोग बनाए रखना चाहिए.

बहरहाल, ताजा हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि अमेरिका और चीन के पास दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग हैं. आज पूरी दुनिया में यह संदेश फैला है कि चीन की आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति से अमेरिका चिढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच संबंध ठीक नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ज़रूरत पड़ने पर दोनों एक साथ खड़े हो सकते हैं. दिलचस्प यह भी है कि भारत विरोधी पाकिस्तान की मदद करने की इनमें होड़ लगी हुई है. इसलिए ख़ासकर भारत को चीन और अमेरिका यानी दोनों से ही सचेत रहने की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

तुम्हारे मन में तो मेरे प्रति अविश्वास भरा हुआ था, फिर भी तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म था और मैंने तुम्हें बचा लिया.

मन में हो विश्वास

एक समय तक शिरडी गांव की गिनती पिछड़े गांवों में हुआ करती थी. उस समय शिरडी और उसके आसपास के लगभग सभी गांवों में ईसाई मिशनरियों ने अपने पैर मज़बूती से जमा लिए थे. ईसाइयों के प्रभाव-लोभ में आकर शिरडी के कुछ लोगों ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था. उन्होंने वहां गांव में एक छोटा सा गिरजाघर भी बना लिया था. वहां पर उन्हें यह सिखाया जाता था कि हिंदू या मुसलमान जिन बातों को मानें, चाहे वे उचित ही क्यों न हों, तुम उनका विरोध करो. हिंदू और मुस्लिम जैसा आचरण करें, तुम उसके विपरीत आचरण करो, ताकि तुम उन सबसे अलग दिखाई पड़ो.

उनका एकमात्र उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच वैमनस्य उत्पन्न करना था, जिससे वे अपना मक़सद सिद्ध कर सकें. वे कहते थे कि ईसा मसीह में ही विश्वास करो, केवल वही ईश्वर का सच्चा पुत्र है. उसके अलावा जितने भी अवतार, पैगंबर आदि हैं, वे हिंदुओं और मुसलमानों की अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं. ईसाई संतों का आदर-सम्मान करो, क्योंकि वही एकमात्र सम्मान योग्य हैं. हिंदू साधु-संतों या मुस्लिम फकीरों की बात मत सुनो, वे सब ढोंगी होते हैं. इस प्रकार की द्वेष भावना वे समाज में बराबर फैला रहे थे. आसपास के इलाक़े में जब हैजे की महामारी फैली तो वे लोग भी इस महामारी से अछूते नहीं रहे. ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करने वाली मिशनरियों ने यह देखकर ब्रिटिश सरकार से सहायता प्राप्त करके उस इलाक़े में अस्पताल बनवा दिया. इस अस्पताल में दवा केवल उन्हीं लोगों को दी जाती थी, जो ईसाई थे. जो लोग ईसाई बनने के लिए तैयार हो जाते थे, उनका मुफ्त इलाज करने के साथ-साथ उन्हें रुपये-पैसे भी दिए जाते थे.

मिशनरी अस्पताल के इंजेक्शनों और दवाओं से जब कोई फ़ायदा होता नहीं दिखाई पड़ा तो अनेक ईसाई भी अपने पादरियों की कड़ी चेतावनी को अनसुना करके साई बाबा की शरण में आने लगे. साई बाबा के लिए जातिपांत का कोई महत्व नहीं था. वह सभी मनुष्यों के प्रति समभाव रखते थे. जो भी उनके पास पहुंचता था, वह उसी को अपनी उदी दे देते. उस उदी का तुरंत चमत्कारिक असर होता था और रोगी मौत के मुंह में जाने से साफ बच निकलता था. यह सब देख-सुनकर पादरियों ने पहले तो ईसाइयों को धन का लालच दिया, फिर डराया-धमकाया कि यदि वे साई बाबा के पास दवा लेने के लिए गए तो उनसे सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, पर लोगों पर इन बातों का जरा सा भी असर नहीं हुआ. वे पादरियों की धमकियों में नहीं आए, क्योंकि यह उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था.

साई बाबा की दवा तो रामबाण थी. वह निश्चित रूप से बीमारी का समूल नाश कर देती थी. उस पर सभी लोगों को पूरा विश्वास था. वे स्वयं भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देख रहे थे. इस कारण वे सब साई बाबा के पास आने लगे. उन्होंने रविवार को गिरजाघर जाना भी बंद कर दिया. यह सब देखकर मिस्टर थॉमस के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा. वह शिरडी में अपना पवित्र ईसाई धर्म फैलाने के लिए आए थे. वह एक पादरी थे. बाबा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए थॉमस ने यह निर्णय किया कि साई बाबा को ढोंगी, झूठा सिद्ध कर दिया जाए, बड़े पैमाने पर उनके विरुद्ध प्रचार-प्रसार आरंभ कर दिया जाए. वह सीधे शिरडी गांव पहुंचे. साई बाबा से मिलने, उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आते थे, लेकिन जब तक साई बाबा की आज्ञा नहीं मिल जाती थी, किसी भी व्यक्ति को उनके पास दर्शन, चरण वंदना करने हेतु नहीं जाने दिया जाता था.

थॉमस के साथ भी ऐसा ही हुआ. वह द्वारिका माई मस्जिद में पहुंचे तो साई बाबा के भक्तों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया. थॉमस को मस्जिद के बाहर खड़े-खड़े घंटों हो गए. लोग आते-जाते रहे, बाबा उनसे मिलते रहे, लेकिन थॉमस को उन्होंने नहीं बुलाया. उस जमाने में प्रत्येक अंग्रेज अपने आपको बड़ा आदमी समझता था. थॉमस अंग्रेज थे. साई बाबा ने उन्हें मस्जिद के बाहर रोककर उनका अपमान किया था. वह इस अपमान को कैसे सहन कर सकते थे! उन्होंने साई बाबा के शिष्यों से कहा कि वे बाबा से पूछ लें कि वह मुझसे मिलेंगे या नहीं. यदि वह नहीं मिलेंगे तो मैं अभी लौट जाऊंगा. साई बाबा का एक शिष्य थॉमस की ख़बर लेकर बाबा के पास गया. बाबा ने थॉमस का संदेश सुना और फिर मुस्करा कर कहा, जिन लोगों के मन में शंका, घृणा, क्रोध एवं पक्षपात आदि बुराइयां हैं, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता. मिस्टर थॉमस से कहो कि वह चले जाएं. वैसे मैं उनसे कल मिल सकता हूं, आज की रात वह यहीं ठहरें. यदि वह अनिष्ट से बचना चाहते हैं तो उन्हें आज रात यहीं पर रुकना चाहिए, रुकेंगे तो मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा. बाबा का संदेश थॉमस तक पहुंचाने के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वह रात को यहीं पर ठहरें, उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी, किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी. थॉमस ने उनका आग्रह ठुकरा दिया और वापस चल दिए. वह तांगे में बैठकर शिरडी तक आए थे. उन्हें साई बाबा द्वारा की गई अनिष्ट की भविष्यवाणी ढोंग मालूम पड़ी. उनका तांगा अभी स्टेशन से आधे रास्ते पर ही होगा कि अचानक एक साइकिल सवार तेजी से उनके तांगे के सामने आ गया. तांगे वाले ने घोड़े को रोकने की अपनी ओर से भरपूर कोशिश की, पर घोड़ा नहीं रुका. तांगा उलट गया, मिस्टर थॉमस तांगे से नीचे गिर पड़े और लहूलुहान हो गए. सड़क पर आते-जाते राहगीरों ने उन्हें उठाया और अस्पताल ले जाकर भर्ती करा दिया.

रात को अस्पताल में जब थॉमस बेसुध सोए पड़े थे, अचानक उन्होंने देखा कि साई बाबा पलंग के पास खड़े हैं और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं कि तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था, फिर भी मैंने तुम्हारी रक्षा की. इस दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी. यदि तुम मेरा कहना मानकर वहीं रुक गए होते तो मैं तुम्हें बचने का उपाय बता देता. तुम्हारे मन में तो मेरे प्रति अविश्वास भरा हुआ था, फिर भी तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म था और मैंने तुम्हें बचा लिया. बाबा के अंतर्ध्यान होते ही थॉमस की आंख खुल गई. वह चौंककर इधर-उधर देखने लगे, लेकिन कहीं कोई भी न था, चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था. कुछ दिनों बाद ठीक हो जाने पर डॉक्टरों ने थॉमस को अस्पताल से छुट्टी दे दी. मिस्टर थॉमस तुरंत शिरडी की ओर चल पड़े. साई बाबा के प्रति उनके मन में भरा अविश्वास जाता रहा. धार्मिक कट्टरता भी अब न रही. थॉमस जब शिरडी आए तो साई बाबा ने उनका स्वागत किया. थॉमस ने आते ही साई बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए. वह बार-बार अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे. वहां उपस्थित लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक पादरी साई बाबा के चरणों में नतमस्तक हो रहा है. सबने इसे एक चमत्कार ही माना. थॉमस ने सबके सामने साई बाबा से क्षमा मांगी और कहा, साई बाबा, आप एक महापुरुष हैं, पहुंचे हुए संत हैं. मैंने इस बात का प्रमाण स्वयं देख लिया है. आप मानव जाति का उद्धार करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं. इस घटना के पश्चात शिरडी ही नहीं, आसपास के तमाम गांवों में भी साई बाबा की जय-जयकार होने लगी. साई बाबा के नाम का डंका दूर-दूर तक बजने लगा था. सर्वत्र ही उनके नाम की धूम मच गई. ऐसा था बाबा का चमत्कार!

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साई बाबा के लिए जातिपांत का कोई महत्व नहीं था. वह सभी मनुष्यों के प्रति समभाव रखते थे.

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ ख़ाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

आज़ादी के 64 सालों बाद भी आज हिंदी उपेक्षा की शिकार है. हिंदी अपने ही घर में सौतेला व्यवहार झेल रही है. पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिंदी ही हो सकती है.

अनंत विजय

'सांस्कृतिक क्रांति' पर बवाल

चौथी दुनिया के अपने इसी स्तंभ में कुछ दिनों पहले मैंने बिहार सरकार के कला और संस्कृति मंत्रालय की कॉफी टेबल बुक–बिहार विहार के बहाने सूबे में सांस्कृतिक संगठनों की सक्रियता, उसमें आ रहे बदलाव और सरकारी स्तर पर उसके प्रयासों की चर्चा की थी. अपने उस लेख में मैंने बिहार सरकार के हाल–फ़िलहाल में किए गए कामों को रेखांकित करते हुए लालू–राबड़ी राज को इन कला और सांस्कृतिक संस्थाओं की दुर्गति के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था. मेरे इस लेख पर कई लोगों को सख्त आपत्ति है. उस लेख के जवाब में कई लेख लिखे गए. लेख के बहाने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की गईं. लेकिन प्रतिलेख लिखने वाले विद्वतजनों ने अपनी आपत्ति में जो तर्क दिए, वे उनकी विद्वता के अनुकूल नहीं हैं. मेरे लेख के जवाब में लिखे गए लेख चूंकि प्रतिक्रिया में लिखे गए हैं, इसलिए वे हल्के हैं. हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जब प्रतिक्रिया में बदले की भावना और व्यक्तिगत राग–द्वेष शामिल हो जाए तो वह नरेंद्र मोदी वाली प्रतिक्रिया हो जाती है. लोगों ने मुझ पर ये भी आरोप लगाए कि मैं अपनी सवर्ण ग्रंथि के तहत लालू यादव को बिहार की बदहाली के लिए ज़िम्मेदार ठहराता हूं और नीतीश कुमार को उसी ग्रंथि के तहत शीर्ष पर पहुंचाता हूं. लालू यादव के बारे में लिखी गई मेरी टिप्पणी से वे इतने आहत हो गए कि उन लोगों ने यह भी पता लगा लिया कि मैं कितने पानी में हूं. मेरे लेख को सावधानी से पढ़े बग़ैर मेरी जाति और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर राय बना लेने वाले इन विद्वानों की समझ पर सिर्फ़ मुस्कराया जा सकता है, हंसी तो कतई नहीं आती.

लालू यादव के शासनकाल के दौरान बिहार की क्या दुर्गति हुई थी, इस बारे में किसी को कुछ कहने की या कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है. जिस तरह से हर साल कोसी में बाढ़ आती है और पूरे इलाक़े में तबाही मचा देती है, उसी तरह सरकारी विभागों में चारा, अलकतरा, बीएड घोटालों की बाढ़ ने पूरे सूबे के विकास की राह को तबाह कर दिया था. क्या लालू यादव की जय–जयकार करने वालों को यह बताने की ज़रूरत है कि लालू–राबड़ी शासनकाल के दौरान बिहार में ग्रोथ रेट कहां से कहां तक पहुंच गया था. क्या उन्हें यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि किस तरह से सूबे के अफसरों के दफ्तरों में घुसकर खुलेआम उनके साथ बदतमीज़ी की जाती थी. क्या उन्हें यह याद दिलाना पड़ेगा कि लालू के राज में अपहरण एक उद्योग में तब्दील हो चुका था. क्या उन्हें यह भी याद दिलाना होगा कि लालू की शह पर शहाबुद्दीन जैसे नेता बिहार में फल–फूल रहे थे. क्या उन्हें यह भी याद दिलाना होगा कि उन पंद्रह सालों में अस्पतालों से डॉक्टर, स्कूल से शिक्षक और दफ्तरों से बाबू ग़ायब रहा करते थे. क्या उन्हें यह भी याद नहीं कि पंद्रह साल में बिहार में परिवहन व्यवस्था चंद चुनिंदा लोगों की बपौती बनकर रह गई. बिहार परिवहन निगम की ख़ूबसूरत इमारत खंडहर में तब्दील हो गई. उस वक़्त की क़ानून व्यवस्था की बात करने से शरीर में सिहरन हो जाती है. लालू यादव के शासनकाल में बिहार सिर्फ़ नेगिटिव ग्रोथ और छवि हासिल कर पाया. जिन लोगों को लालू यादव सामाजिक क्रांति और समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों के मसीहा नज़र आते हैं, उनसे मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूंगा कि उन दबे–कुचलों ने ही उनको सत्ता से बाहर कर दिया था.

शासन सिर्फ़ नारों, जुमलों और मसखरेपन से नहीं चलता. उसके लिए ठोस कार्य और

अहम फ़ैसले करने होते हैं. दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की करारी हार के बाद कुछ लोगों को लालू में अपना भविष्य नज़र आने लगा है और वे उनमें संभावना तलाशने लगे हैं. अब अगर मैं यह कहूं कि उनकी जातिवादी मानसिकता उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है तो मैं भी उसी ग्रंथि दोष का शिकार हो जाऊंगा, जिसका आरोप मुझ पर लगाया गया है. मेरे उस लेख की प्रतिक्रिया में जिस तरह से बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उल्लेख किया गया, वह भी बेहद हास्यास्पद और मनोरंजक है. उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता. दूसरी बात जो साबित करने की कोशिश की गई, वह यह कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार में जमकर सांस्कृतिक गतिविधियां होती थीं. इस क्रम में यह बताया गया कि लालू यादव के समय में बिहार विधान परिषद की साहित्यिक गतिविधियां सुगढ़ थी. इस सुगढ़ता के लिए दो उदाहरण दिए गए. पहला यह कि उस वक़्त परिषद की पत्रिकाएं साक्ष्य और संवाद राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रही थीं. अब इस कथन का क्या किया जाए. राष्ट्रीय स्तर की तो बात छोड़िए, मैं तो सिर्फ़ इतना कह सकता हूं कि ये पत्रिकाएं अब भी साहित्यिक हलके में अपनी जगह और पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. जाबिर हुसैन हमारे मित्र हैं, मैं भी उन पत्रिकाओं को लगातार देखता रहा हूं, लेकिन राष्ट्रीय लोकप्रियता का कथन अति उत्साह में दिया गया प्रतीत होता है.

दूसरा यह कि विधान परिषद में राजेंद्र यादव, गुलज़ार एवं सीताराम येचुरी जैसे बौद्धिक वहां की गतिविधियों में शामिल होते थे. यह सच है कि जाबिर हुसैन के बिहार विधानसभा के सभापति रहते परिषद में कुछ साहित्यिक गतिविधियां हुई थीं, उनकी तारीफ़ भी हुई थी. ख़ुद जाबिर हुसैन की किताब पर लिखते हुए मैंने भी उनकी साहित्यिक सक्रियता को सराहा था, लेकिन क्या उतना भर ही काफी है. क्या मुझ पर आरोप लगाने वाले यह जानते हैं कि उस वक़्त कला और संस्कृति मंत्री कौन थे या फिर उस मंत्रालय की पहल पर क्या सार्वजनिक कार्य किए गए. दिल्ली के एक समाजवादी कवि–उपन्यासकार ने भी फोन करके मुझसे बहस की. उनकी पहली लाइन थी, वेबसाइट्स पर चौथी दुनिया में छपे आपके लेख पर ख़ूब बहस हो रही है. मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसा कि लोगों ने मुझे बताया कि आपने बिहार की सांस्कृतिक हलचल पर लिखा है. पहले तो वह फेसबुक पर लिखत–पढ़त में बहस करना चाहते थे, लेकिन बाद में मौखिक बहस हुई. उनका कहना था कि बिहार की अकादमियां बहुत बुरे हाल में है. मैं उनकी राय से सौ फ़ीसदी सहमत हूं. अकादमियों की हालत बुरी है. लेकिन फिर से मैं उसी तर्क पर लौटता हूं कि वर्तमान हालत को पिछले शासनकाल के बरक्श रखकर देखिए, आपको हक़ीक़त का पता चल जाएगा. क्या उन अकादमियों की बेहतरी की दिशा में सोचा नहीं जा रहा, क्या उनके कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार ने धन मुहैया कराने की कार्ययोजना नहीं बनाई और क्या उनको सक्रिय करने की दिशा में पहल नहीं हो रही?

यह सच है कि बिहार सरकार की प्राथमिकता में कला–संस्कृति नहीं है, लेकिन यह प्राथमिकता तो किसी भी सरकार की नहीं रही है और न ही आगे रहेगी. हिंदी के नाम पर राजनीति करने वालों को यह भी याद नहीं कि विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होता है. हम सिर्फ़ बिहार की अकादमियों के बारे में ही क्यों सोचते हैं. आप देश भर की अकादमियों की तफ्तीश करके देख लीजिए, कमोबेश हर जगह आपको एक जैसे हालात नज़र आएंगे, लेकिन इस तर्क पर बिहार की अकादमियों की बदहाली को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है. बिहार सरकार के कला और संस्कृति मंत्रालय की इस बात के लिए तो सराहना करनी ही चाहिए कि उसने सुधार की दिशा में क़दम उठाए हैं. कवि मित्र मुझे यह भी समझाने की कोशिश करने लगे कि वह बिहार की मंत्री सुखदा पांडे की समझ को जानते हैं और उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है. मैंने उनसे निवेदन भी किया कि किसी की व्यक्तिगत क्षमता को उसकी विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि उसके काम के आधार पर आंका जाना चाहिए. लेकिन उनका गुस्सा चरम पर था और वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वही संवाद टूटने की वजह बना. बातचीत ख़त्म होने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने तो बग़ैर मेरे लेख को पढ़े किसी के कहने के आधार पर अपनी राय बना ली. ख़ैर हिंदी की दुर्दशा के लिए यही चीज (बिना पढ़े राय बनाना) बहुत हद तक ज़िम्मेदार है.

अंत में सिर्फ़ इतनी बात कहना चाहूंगा कि किसी विचार पर सार्थक बहस हो, तर्कों का सहारा लेकर एक–दूसरे पर हमले हों, लेकिन लेखन में एक न्यूनतम मर्यादा का पालन तो हो. आजकल वेबसाइट पर हर किसी को गाली–गलौच करने और व्यक्तिगत जीवन पर कीचड़ उछालने की हासिल छूट का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, वह चिंता की बात है. मैं उस तरह के लोगों का नाम लेकर उनको वैधता नहीं प्रदान करना चाहता, लेकिन उन कुंठित लोगों के बारे में हिंदी समाज को गंभीरता से सोचना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में यह लंपटई हम सब पर भारी पड़ सकती है.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

हिंदी की उपेक्षा क्यों और कब तक

एस. बिजेन सिंह

हिंदी, हिंद और हम, एक हिंदुस्तानी की पहचान इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है, लेकिन जिस पहचान को दुनिया मानती है, जानती है, उसे हमारी अपनी सरकार मानने को तैयार नहीं है. शायद तभी केंद्र सरकार ने खुलकर और आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है.

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. हिंदी जन–जन की भाषा है. आज़ादी की लड़ाई में हिंदी ने लोगों को जोड़ने का काम किया, लेकिन यह बात हमारी सरकार और संसद नकारती रही है. पिछले साल गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं. अदालत ने कहा कि भारत में अधिकांश लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया है. बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं और इसे देवनागरी लिपि में लिखते भी हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है. मुख्य न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने यह बात उस समय कही, जब उसे डिब्बा बंद सामानों पर हिंदी में विवरण लिखे जाने से संबंधित एक मामले में फ़ैसला सुनाना था. सुरेश कचाड़िया ने गुजरात हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करके मांग की थी कि डिब्बा बंद सामानों

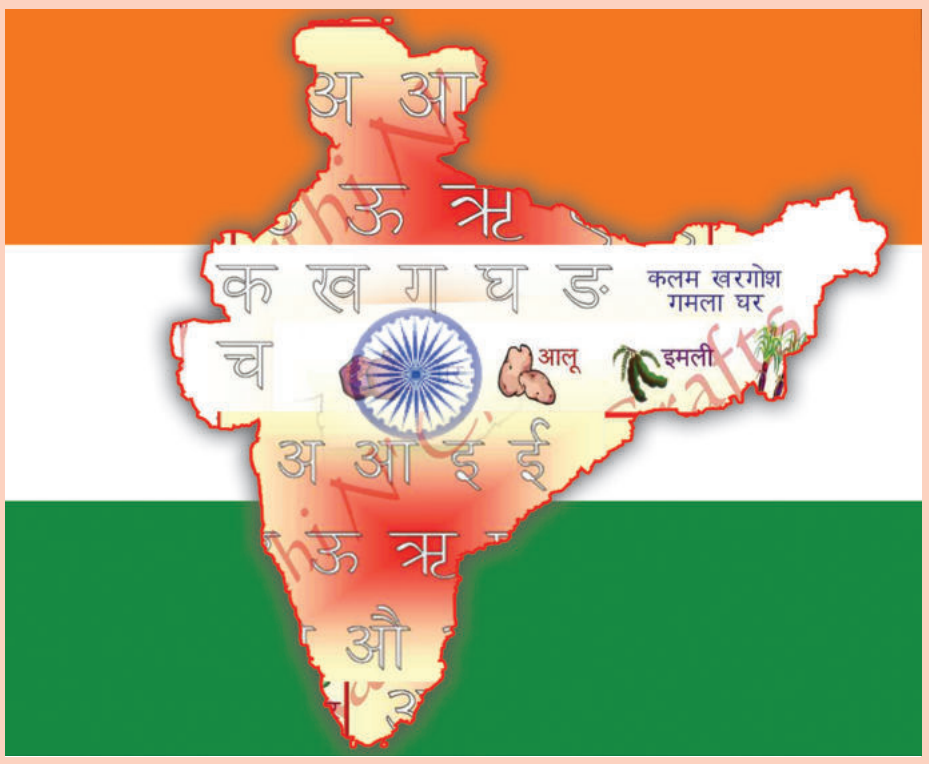

पर हिंदी में उत्पाद संबंधी विवरण लिखा होना चाहिए और यह नियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू कराया जाना चाहिए. पीआईएल में कहा गया था कि डिब्बा बंद सामानों पर क़ीमत आदि जैसी ज़रूरी जानकारियां हिंदी में भी लिखी होनी चाहिए. तर्क यह था कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है और देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, इसलिए यह जानकारी हिंदी में छपी होनी चाहिए. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का कहना था कि क्या इस तरह का कोई नोटिफिकेशन है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी तो अब तक राजभाषा यानी आधिकारिक भर है. सरकार द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन अब तक अदालत में पेश नहीं किया गया है. हिंदी देश के राज–काज की भाषा है, न कि राष्ट्रभाषा.

दूसरी तरफ़ अभी हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से एक ख़बर आई कि संविधान में राष्ट्रभाषा का प्रावधान नहीं है. यह जानकारी विभाग ने सामाजिक कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय को दी है. रॉय ने बीते 6 जून को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय से राष्ट्रभाषा के संबंध में जानकारी मांगी थी. मंत्रालय के जवाब के मुताबिक़ , भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी केंद्र की राजभाषा ज़रूर है, परंतु संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं है.

सामाजिक कार्यकर्ता रॉय ने कहा कि देश को हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया और उर्दू में हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाता है. इसलिए उन्होंने अपनी आरटीआई की अर्जी में पूछा था कि इस देश का आधिकारिक नाम क्या है? बहरहाल, इन दोनों उदाहरणों को देखते हुए इस देश में हिंदी की दशा और दिशा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. वर्ष 1965 में संसद द्वारा हिंदी राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था. तभी से हिंदी को सिर्फ़ राजभाषा का दर्जा हासिल है, लेकिन राष्ट्रभाषा का नहीं? क्यों? जब स्वतंत्रता आंदोलन के वक़्त यह कहा जाता रहा कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है, तब आज़ादी के बाद संविधान में सिर्फ़ राजभाषा का ही उल्लेख क्यों किया गया?

राष्ट्रभाषा कहने के दो तात्पर्य निकलते हैं. एक है राष्ट्र की एकमात्र भाषा. किसी भी बहुभाषिक देश में अन्य सारी भाषाओं की अस्मिता को ठुकराते हुए उनके स्थान पर सिर्फ़ एक भाषा को ही स्वीकार करने वाली बात किसी भी जनतांत्रिक देश में सही नहीं मानी जा सकती. इस कारण कुछ विद्वान राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर विचार करते हुए इस शब्द के अर्थ को विस्तार देकर कहते हैं कि हिंदी, तमिल, तेलुगु और बांग्ला आदि सभी हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं. फिर इस अर्थ में राष्ट्रभाषा का कोई निश्चित अर्थ नहीं रह जाता.

राष्ट्रभाषा का दूसरा अर्थ यह है कि उससे सांकेतिक सम्मान प्रकट होता है, जैसे राष्ट्रगान से. हिंदी भाषा का प्रश्न सम्मान से अधिक उसके प्रयोजनों का है, उसकी भूमिकाओं का है. राजभाषा के तौर पर हिंदी की अहम भूमिका है. इसकी अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी हैं. यह देश की भाषाओं के बीच एक सेतु है, एक संपर्क भाषा है. यह दस से अधिक देशों में बोली जाती है और लगभग 150 विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है. भारतेंदु बाबू की एक पंक्ति आज भी जेहन में ताजा है–

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल॥

आज़ादी के 64 सालों बाद भी आज हिंदी उपेक्षा की शिकार है. हिंदी अपने ही घर में सौतेला व्यवहार झेल रही है. पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिंदी ही हो सकती है. हिंदी राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के तौर पर इस विविधता से भरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम कर सकती है. केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार–प्रसार करे, उसका विकास करे, जिससे वह संपूर्ण भारतवर्ष की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके.

sbijensngh@gmail.com

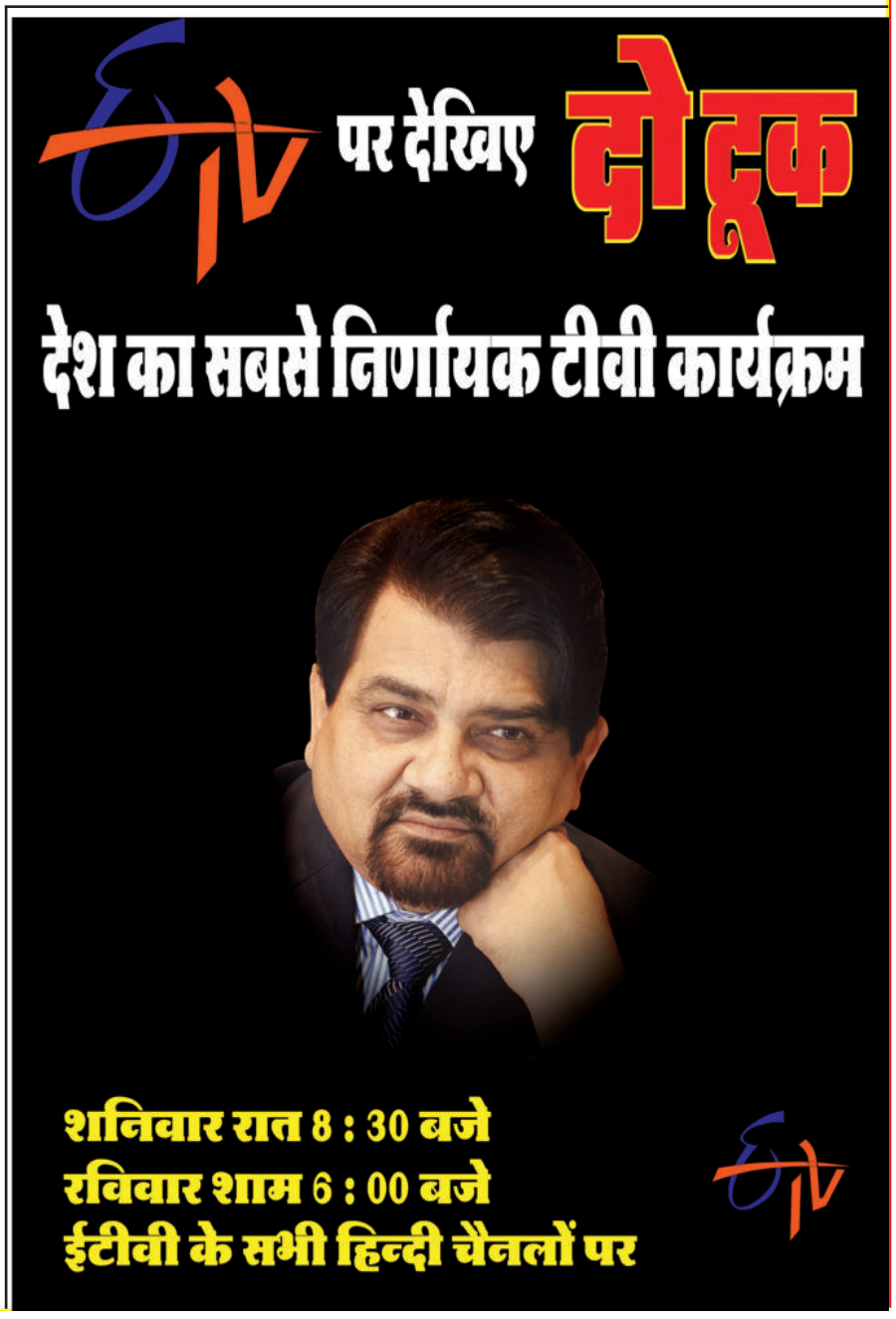

इटैलियन सॉस कलेक्शन में लोकप्रिय इटैलियन ट्रैटोरियाज़ के पास्ता डिश का स्वाद और सुगंध है. प्रत्येक प्रोडक्ट को ख़ास स्वाद के मद्देनज़र तैयार किया गया है.

जेब्रोनिक्स के नए उत्पाद

कंप्यूटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के लिए जेब्रोनिक्स ब्रांड नाम के तहत उत्पाद एवं उपकरण बनाने वाली कंपनी टॉप नॉच इंफोट्रोनिक्स ने अपना प्रीमियम लैपटॉप बैग जेबस्टर पेश किया है. इसमें सामने की ओर आकर्षक ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफिक्स है, जो देखने में काफी स्मार्ट है. बैकपैक स्टाइल वाले जेबस्टर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसे लेकर चलना आसान है. यह 15.4 इंच तक के चौड़े स्क्रीन वाले लैपटॉप के लिए उपयुक्त है. कंधे पर लटकाने के लिए इसके पट्टे बेहद सुविधाजनक हैं. इसके अलावा इसमें एक्सट्रा पैडेड बैक पैनल और हल्की सामग्री का उपयोग किया गया है, जो जेबस्टर बैकपैक को आरामदेह बनाते हैं. इसमें उपलब्ध स्थान को इस तरह बांटा गया है कि उपयोगकर्ता को लैपटॉप और अन्य उपकरण रखने के लिए पर्याप्त जगह मिले. बैग के पट्टे पर ही एक छोटा सुविधाजनक पाउच है, जो सेलफोन या म्यूज़िक एमपी 3 प्लेयर के लिए है. सामने की ओर दोनों तरफ़ इसमें दो कंपार्टमेंट हैं, जो छोटी चीजें रखने के लिए हैं, जैसे पावर सप्लाई, एक्सटर्नल ड्राइव या अन्य उपकरण. दो बड़े मेन कंपार्टमेंट में फुल जिपडाउन लैप हैं. इसके अलावा इसमें दस्तावेज़ों और फाइलों के लिए जिप वाले पॉकेट भी हैं. जेब्रोनिक्स ने इसके साथ-साथ अपने लैपटॉप स्लीव भी पेश किए हैं. इनका उपयोग एक अलग केस के रूप में या फिर अलग बैग में स्लीव केस के रूप में किया जा सकता है. इससे उपयोगकर्ता के लिए अपना लैपटॉप किसी भी ब्रीफकेस या बैकपैक में कभी भी, कहीं भी सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से ले जाना संभव होता है. इन्हें टिकाऊ, मोटे, उच्च गुणवत्ता वाले नियोप्रीन मटेरियल से बनाया जाता है और फिनिशिंग एक्सट्रासॉट इंटीरियर से की जाती है. इस तरह ये स्लीव्स झटकों और कंपन से पूरी सुरक्षा देते हैं. आकर्षक स्लीव अपने सॉट ब्लैक कलर और रेड ट्रिमिंग के कारण अच्छे लगते हैं. ये स्लीव दो साइज़ में आते हैं और 10 व 15 इंच के लैपटॉप के लिए उपयुक्त हैं. जेब्रोनिक्स ने जेबस्टर बैकपैक की क़ीमत 1550 रुपये रखी गई है, जबकि लैपटॉप स्लीव की क़ीमत 10 इंच वाले की 425 रुपये और 15 इंच वाले की 475 रुपये है. ये रेंज अब देश भर में सभी अग्रणी आईटी स्टोर्स में उपलब्ध हैं.

फैशन का टशन

आजकल की फैशनेबल कुड़ियों को स्टाइलिश और फंकी चीजें ही लुभाती हैं, चाहे उनके ड्रेस हों या ड्रेस के साथ पहने जाने वाले एक्सेसरीज. लड़कियों को भारी-भरकम ज्वेलरी के बजाय हल्के-फुल्के स्टड्स और एक्सेसरीज ही पसंद आते हैं, लेकिन फैशन के साथ क़दमताल मिलाकर चलने वाली युवतियों के लिए इन एक्सेसरीज़ का ट्रेंडी होना ज़रूरी होता है और अगर इनके दाम कम हों तो क्या कहने. आधुनिक युवतियों को लुभाने के लिए ब्रॉन्ज ऐज की सिल्वर ज्वेलरी इन दिनों बतौर एक्सेसरी ख़ूब चल रही है. चाहे ड्रेस एथनिक हो या वेस्टर्न, सोबर हो या मॉडर्न, यह जंक ज्वेलरी हर ड्रेस पर ख़ूब जंचती है. यह एक्सेसरीज युवाओं की जेब पर बिल्कुल फिट बैठती है. इसमें बोल्ड और मॉडर्न पैटर्न के साथ अलग-अलग शेप भी उपलब्ध हैं. विभिन्न रंगों में उपलब्ध अलग-अलग टेक्सचर और मटेरियल में बने ब्रेसलेट, नेकलेस, ईयर रिंग और पेंडेंट ख़ास स्टाइल स्टेटमेंट बनाते हैं. मॉडर्न लड़की के हर रूप, जैसे हिपस्टर, टॉमब्यॉय, अपटाउन गर्ल, डिवा या चिक के लिए ऐसे एक्सेसरीज बेस्ट सूटेड हैं.

इन दिनों जब मिक्स एंड मैच के फैशन का जादू चल रहा है तो इसी ट्रेंड पर मिक्स एंड मैच एक्सेसरीज भी इन है. ट्रेंडी बॉबल्स के परफेक्ट चिक ज्वेलरी आपकी पर्सनालिटी में और भी निखार ला देते हैं. ये एक्सेसरीज बदलते फैशन ट्रेंड को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं. इन डिजाइंस को पहन कर आप अपने आपको टफ लुक दे सकेंगे और अपनी हिप-हॉप इमेज भी बरक़रार रख सकेंगे. आमतौर पर देखा जाता है कि ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं के लिए इस तरह की फंकी ज्वेलरी बाज़ार में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन यह ज्वेलरी न सिर्फ़ युवा लड़कियों के लिए तैयार की गई है, बल्कि आधुनिक विचारों वाली उम्रदराज औरतों को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है. इन एक्सेसरीज की क़ीमत 69 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये तक है.

नया नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम

सीगेट ने अपने गोफ्लेक्स होम नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम के लिए गोफ्लेक्स एक्सेस मोबाइल डिवाइस एप्लीकेशन पेश किया है. यह आईट्यूंस स्टोर और एंड्रॉयड मार्केट में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. इस्तेमाल में एकदम आसान यह एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर या अपने आईफोन, आईपैड, आईपॉड टच या एंड्रॉयड पर सीगेट या गोफ्लेक्स सर्च कर पाया जा सकता है. नया गोफ्लेक्स एक्सेस एप्लीकेशन कभी भी, कहीं भी नेटवर्क एक्सेस के ज़रिए फोटो, गाने, मूवीज और डॉक्यूमेंट एक्सेस करने का एकदम आसान जरिया है. गोफ्लेक्स होम नेटवर्क स्टोरेज सर्वर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आसानी से शेयर्ड स्टोरेज ड्राइव सेटअप किया जा सके, जो एक होम नेटवर्क के तहत बैकअप और शेयरिंग की सुविधा उपलब्ध कराए और कहीं दूर बैठकर पर्सनल कंप्यूटर के ज़रिए भी एक्सेस उपलब्ध कराए. इस नए मोबाइल एप्लीकेशन के लांच के साथ गोफ्लेक्स होम नेटवर्क ड्राइव मोबाइल कनेक्टिविटी की दुनिया में शामिल हो गया. आईपैड, आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्ट फोन के ज़रिए अब होम नेटवर्क में स्टोर्ड टेराबाइट डेटा को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इनसे आनंद उठाया जा सकता है. पर्सनल मोबाइल, टेक्नोलॉजी और डिवाइस मीडिया इस्तेमाल के साधन के तौर पर देखे जाते हैं और अब इनका विस्तार होम नेटवर्क ड्राइव तक हो गया है. इस नेटवर्क एक्सेस के अनगिनत फ़ायदे हैं. इसमें शेयर्ड फोटो के स्लाइड शो देखने और म्यूज़िक सुनने का आनंद एक साथ लिया जा सकता है. इसके अलावा 3-जी और 4-जी और वाईफाई के ज़रिए मोबाइल डिवाइस पर वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं. एक्सेल, पावर प्वाइंट, वर्ड डॉक्यूमेंट और पीडीएफ आदि एक्सेस कर सकते हैं. एप्लीकेशन में कंटेंट टाइप फिल्टर का फीचर शामिल है, जो आपके वैसे कंटेंट का एक्सेस आसान बनाता है, जिसमें या तो बड़ी संख्या में फाइलें हों या कई टाइप की फाइलें हों. साथ में म्यूज़िक फाइल के लिए एलबम आर्ट सपोर्ट की सुविधा है. 1 टीबी, 2 टीबी और 3 टीबी की क्षमता में उपलब्ध गोफ्लेक्स होम स्टोरेज सिस्टम में बड़ी मात्रा में कंटेंट स्टोर करने, उसे आसानी से एक्सेस करने, लगातार बैकअप देने और आपके क़ीमती डिजिटल कंटेंट को सुरक्षित रखने की सुविधा मिलती है. यूएसबी पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट करके गोफ्लेक्स होम सिस्टम में अतिरिक्त ड्राइव भी जोड़े जा सकते हैं. इसके अलावा इसी यूएसबी पोर्ट के ज़रिए नेटवर्क के तहत सभी कंप्यूटरों से वायरलेस यूएसबी प्रिंटर भी कनेक्ट किया जा सकता है. गोफ्लेक्स होम नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम सीगेट.कॉम पर और चुनिंदा रिटेलर्स के यहां से ख़रीदा जा सकता है. 1 टीबी की क़ीमत 8,000 रुपये और 2 टीबी की क़ीमत 12,000 रुपये है. फर्मवेयर अपडेट और नया गोफ्लेक्स एक्सेस एप्लीकेशन सभी गोफ्लेक्स होम ग्राहकों के लिए मुफ्त उपलब्ध है. सीगेट डिस्क ड्राइव व स्टोरेज सॉल्यूशन देने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनी है.

घर बैठे इटैलियन डिश

इटैलियन सॉस की रेंज में कई स्वाद शामिल हैं. इनमें ख़ास है अराबियाता पास्ता सॉस-हॉट एंड स्पाइसी क्लासिक, मजेदार पेने पास्ता, मारीनारा पास्ता सॉस, माइल्ड एंड टैंगी सॉस, जिसकी उत्पत्ति नेपल्स में हुई.

लोगों के बीच नए-नए स्वाद और ग्लोबल कुज़ीन की बढ़ती लोकप्रियता के साथ अब घर पर इटैलियन खाना बनाने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन अब इटैलियन खाने के लिए होटल जाना ज़रूरी नहीं रहा. देश के सभी प्रांतों में लाजवाब स्वाद के ऐसे खाने का चलन बढ़ रहा है, जो चुटकी में तैयार हो जाए. इसे देखते हुए डॉ. ओटकर फन फूड्स ने इटैलियन पास्ता सॉस की नई रेंज़ पेश की है. इटैलियन सॉसेज़ की यह रेंज़ ब्रांडेड पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स यूरोपीय कुज़ीन पर अधिक केंद्रित है. डॉ. ओटकर मेयोनेज़, स्प्रैड और ड्रैसिंग के बाज़ार की अग्रणी कंपनी है. इस इटैलियन सॉस की रेंज में कई स्वाद शामिल हैं. इनमें ख़ास है अराबियाता पास्ता सॉस-हॉट एंड स्पाइसी क्लासिक, मज़ेदार पेने पास्ता, मारीनारा पास्ता सॉस, माइल्ड एंड टैंगी सॉस, जिसकी उत्पत्ति नेपल्स में हुई. पेस्तो वर्दे पास्ता सॉस- जेनोवा का प्रसिद्ध सॉस (31 प्रतिशत चुनिंदा बेसिल के साथ), पेस्तो रोसो पास्ता सॉस-धूप में पके टमाटर और इटैलियन ऑलिव ऑयल से तैयार इटली की लाजवाब पेशकश, जो खाने को लजीज़ बना दे, एग्लियो ओलियो पास्ता सॉस-गार्लिक और पेपरोंसीनी से भरपूर. थिन स्पैगेटी (स्पैगेटीनी) के साथ खाने का मज़ा आ जाए, जैसे ट्रैवर्टिनो, इंडिजो, एज्युरो किचेन, कैफे बैले, लैटिट्यूड, पाम ग्रूव कैफे, काफिया, दीवा, स्मोक हाइस ग्रिल, आदि. डॉ. ओटकर के इटैलियन कुज़ीन के तहत पहले से दो सॉस लोकप्रिय रहे हैं-पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा टॉपिंग. इटैलियन सॉस कलेक्शन में लोकप्रिय इटैलियन ट्रैटोरियाज़ के पास्ता डिश का स्वाद और सुगंध है. प्रत्येक प्रोडक्ट को ख़ास स्वाद के मद्देनज़र तैयार किया गया है. अराबियाता पास्ता सॉस हॉट एंड स्पाइसी है तो मारीनारा पास्ता सॉस माइल्ड और टैंगी है, जो बच्चों को ख़ूब भाता है. पेस्टो वर्दे पास्ता सॉस में 31 प्रतिशत चुनिंदा बेसिल लीव्स हैं, ताकि स्वाद में ख़ास ताज़गी आ जाए, जबकि पेस्तो रोसो सॉस में एक नई स्फूर्ति है और इसे ब्रेड-टोस्ट पर लगाकर मज़ेदार ब्रुशेटा बनाया जा सकता है. एग्लियो ओलियो पास्ता सॉस इटली की ख़ास पसंद है और स्पैगेटी के साथ इसका मेल मज़ेदार हो जाता है. सभी पास्ता सॉसेज़ 100 प्रतिशत वेजीटेरियन हैं और इनमें ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं होता. इनकी क़ीमत 99 रुपये से लेकर 159 रुपये तक है. प्रत्येक प्रोडक्ट में इटली के असली मसाले और जड़ी-बूटियां हैं. घर पर होटल की तरह इटैलियन खाने का मज़ा आ जाता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फोटोग्राफी का मज़ा दोगुना

फोटोग्राफी का असली मज़ा तब आता है, जब व्यू फाइंडर से दुनिया देखने का आनंद आए. अब आप भी बेजोड़ कैमरे का आनंद लेते हुए शानदार तस्वीरें उतार सकते हैं, क्योंकि फुजी फिल्म ने पेश किया है नए युग का एक कैमरा फाइनपिक्स एक्स-100, जो इस लिहाज़ से सबसे आगे है कि इसमें दुनिया का पहला हाइब्रिड व्यू फाइंडर लगा है. 12.3 मेगा पिक्सल के इस कैमरे के 23 मिमी फुजीनॉन लेंस से बेजोड़ तस्वीरों की गारंटी है. कैमरे की सबसे बड़ी ख़ासियत है इसका हाइब्रिड व्यू फाइंडर, जिसमें ग्राहक को वे तमाम ख़ूबियां मिलती हैं, जो आम तौर पर एक साथ मुमकिन नहीं हैं. यह दरअसल दो अलग किस्म के व्यू फाइंडर का संयोग है, जो वस्तुत: बेशक़ीमती फिल्म कैमरों और डिजिटल कांपैक्ट कैमरों में होते हैं. इस तरह दो किस्म के व्यू फाइंडर के गुणों के तालमेल से तैयार फाइनपिक्स एक्स-100 के हाइब्रिड व्यू फाइंडर से आप आसानी से तस्वीरें उतारेंगे. पारंपरिक कैमरे की तरह फाइनपिक्स एक्स- 100 की डिज़ाइन की गुणवत्ता देखते ही बनती है. इसके फीचर ग्राहक को अपनी रचनात्मक कला को निखारने की आज़ादी देते हैं. ज़ाहिर है, कैमरे का उपयोग बेहद संतोषजनक होगा. कैमरे में बड़े आकार का उच्च प्रदर्शन वाला एपीएस-सी/सीएमओएस सेंसर है, जो सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा ली गई एक-एक तस्वीर में बेजोड़ सफाई हो और चमक लाजवाब. कैमरे का शक्तिशाली ईएक्सआर प्रोसेसर तस्वीर में सबसे अच्छा रिज़ॉल्यूशन सुनिश्चित करने में सहायक है. एक्स-100 हाई क्वालिटी एचडी (हाई डेफिनेशन) मूवी भी शूट कर सकता है. फुजी फिल्म इंडिया के प्रबंध निदेशक के टनाका के अनुसार, फुजी फिल्म के आर एंड डी के पीछे कुछ नया कर दिखाने का जज़्बा काम करता है. हम समय-समय पर अनूठे फीचरों के साथ अपने प्रोडक्ट पेश करते रहे हैं. हमें फाइनपिक्स एक्स-100 में दुनिया का पहला हाइब्रिड व्यू फाइंडर पेश करने की ख़ुशी है. नए युग की इस तकनीक से लैस यह प्रोडक्ट अवश्य ऐसा अनुभव देगा, जो किसी कैमरे ने न दिया हो. फुजी फिल्म इंडिया के कंट्री जनरल मैनेजर ए राजकुमार ने कहा कि फुजी फिल्म की नज़र में भारत एक महत्वपूर्ण बाज़ार है. हम अपने ग्राहकों, जो आज तमाम जानकारी से लैस हैं, के लिए नई से नई चीजें लाने की इच्छा रखते हैं. हमारा फाइनपिक्स एक्स-100 एक उम्दा डिजिटल कैमरा है, जो फोटोग्राफी के दीवानों के लिए नई तकनीक का तोहफ़ा है. अपनी क़िस्म के इस ख़ास फीचर के साथ यह कैमरा निस्संदेह उन्हें लाभ देगा, जो फोटोग्राफी को केवल हॉबी नहीं, बल्कि बतौर प्रोफेशन देख रहे हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज श्रीसंत के छोटे भाई दीपू संत अपना करियर मलयालम फिल्मों में बनाने की राह पर चल पड़े हैं.

ये बदलाव कितने ज़रूरी हैं

राजेश एस कुमार

व्यापार का एक सिद्धांत यह होता है कि जैसे ही व्यापारी को महसूस हो कि उसके बिजनेस की चमक फीकी पड़ने लगी है, वह या तो अपना बिजनेस बदल दे या उसे जल्द ही रेनोवेशन की प्रक्रिया में लाए. आजकल क्रिकेट के व्यापारीकरण से तो सभी वाकिफ हैं. यह बिज़नेस भी अपनी लोकप्रियता और मुनाफे के शिखर पर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेट टीम ने इतना क्रिकेट खेला कि लोग खेल से ही उकताने लगे. पहले विश्वकप हुआ, उसके तुरंत बाद आईपीएल और फिर वेस्टइंडीज दौरा. बात यहीं खत्म नहीं होती. टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे के बाद इंग्लैंड रवाना होगी. नतीजतन, आईपीएल में क्रिकेट प्रायोजकों और प्रबंधन को उतना फायदा नहीं पहुंचा, जितने की उन्हें उम्मीद थी. हालांकि बिजनेस के टर्म में कम मुनाफे को नुकसान की ही संज्ञा दी जाती है. लगता है कि अब आईसीसी को भी इसका अंदाजा हो चुका है, इसलिए अब वह भी रेनोवेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है. अभी हाल में नियमों के बदलाव को लेकर जो भी विवाद और चर्चाएं हुई हैं, उनसे तो यही लगता है कि क्रिकेट के नियमों में बदलाव करके एक बार फिर से लोगों में क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी पैदा की जाए. गौरतलब है कि लंबी बहस के बाद आखिर में अंपायरों के फ़ैसले की समीक्षा (डीआरएस) करने वाली तकनीकी प्रणाली स्वीकार कर ली गई. अब यूडीआरएस का नया बदला हुआ रूप टेस्ट और वन डे मैचों में लागू हो जाएगा. अब विवादास्पद अंपायर डिसिजन रिव्यू सिस्टम (यूडीआरएस) का संशोधित रूप सभी अंतरराष्ट्रीय मैचों में लागू होगा. उसमें हॉट स्पॉट तकनीक तो होगी, लेकिन हॉक आई नहीं होगी, जिससे गेंद की दिशा का पता चलता है. यानी यूडीआरएस में एलबीडब्ल्यू के फैसले शामिल नहीं होंगे. इसमें अब थर्मल इमेजिंग और साउंड तकनीक शामिल होगी. 2008 के बाद अगले महीने शुरू हो रही इंग्लैंड सीरीज में भारत पहली बार यूडीआरएस के तहत मैच खेलेगा.

एक तरफ जहां आईसीसी इस बात को लेकर संतुष्ट है कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को इसके लिए राज़ी करने में सफल हुआ, वहीं बीसीसीआई ख़ुश है कि सिर्फ़ ट्रैकिंग टेक्नालॉजी के सहारे डीआरएस के इस्तेमाल का उसका विरोध भी मान लिया गया. पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की हांगकांग में हुई बैठक में फ़ैसला हुआ कि समीक्षा करने वाली प्रणाली यानी डीआरएस के तहत इंफ्रारेड कैमरों और विकेट में लगी आवाज़ पकड़ने वाली मशीनों की मदद ली जाएगी. इंफ्रारेड कैमरे यह देख सकेंगे कि अगर विकेट के पीछे कैच या एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है तो कहीं गेंद बल्ले को छूते हुए तो नहीं निकली थी. साथ ही विकेट में लगी आवाज़ पकड़ने वाले उपकरण भी यह बताएंगे कि गेंद के बल्ले से छूने की आवाज़ हुई है या नहीं. बीसीसीआई अब तक इस्तेमाल होने वाली बॉल ट्रैकिंग टेक्नालॉजी के विरुद्ध था और आईसीसी ने भी अब बीसीसीआई के रुख़ पर मुहर लगाते हुए कहा है कि इस तकनीक का इस्तेमाल द्विपक्षीय सीरीज में दोनों टीमों की सहमति पर होगा. यानी अगले महीने होने वाले इंग्लैंड के दौरे में अंपायरों के फ़ैसले की समीक्षा की प्रणाली लागू तो होगी, मगर एलबीडब्ल्यू के फ़ैसलों के लिए यह लागू नहीं होगी, क्योंकि वे फ़ैसले बॉल ट्रैकिंग टेक्नालॉजी के इस्तेमाल पर निर्भर होते हैं. इन तब्दीलियों से इतना तो तय है कि आईसीसी के नए नियम क्रिकेट के स्वरूप को बदल डालेंगे. आईसीसी की बैठक में यह भी फ़ैसला हुआ कि एक दिवसीय मैचों में टीमों को अंपायर के फ़ैसले के विरुद्ध अब दो के बजाय एक बार अपील का मौक़ा मिलेगा और अगर अपील सही हुई तो वह मौक़ा बरक़रार रहेगा. अब बैटिंग और बॉलिंग के पावर प्ले 16 से 40 ओवरों के बीच ही लिए जा सकेंगे. साथ ही गेंदबाज़ों के दोनों छोरों से नई गेंद का इस्तेमाल होगा यानी मैच के बीच में अब गेंद बदलने की ज़रूरत नहीं होगी. साथ ही एक साल के भीतर अगर किसी टीम का कप्तान दो बार धीमे ओवर रेट का दोषी पाया गया तो उसे निलंबन का सामना करना पड़ेगा, पहले इसकी इजाज़त तीन बार की थी. विश्वकप को ध्यान में रखते हुए परिषद ने 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में होने वाले क्रिकेट विश्वकप के लिए एक क्वालिफ़िकेशन की प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है यानी आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी टीमों के इस विश्वकप में शामिल होने की राह खुल गई है. हालांकि यह सिफ़ारिश नहीं की गई है कि विश्वकप में कितनी टीमें शामिल की जाएं, लेकिन इससे इतना तो तय है कि अब अगले विश्वकप में छोटी टीमें भी भाग ले सकेंगी. इसके अलावा एक और बदलाव हुआ है, जिसे लेकर सुनील गावस्कर काफी खफा हैं. दरअसल, बदलाव यह है कि आईसीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि वन डे में घायल बल्लेबाजों को रनर नहीं दिए जाएंगे यानी अब रनर का इस्तेमाल करने का अधिकार बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. जब भी इस तरह के परिवर्तन होते हैं, इन्हें लेकर सहमति और असहमति की स्थिति बनती रहती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. गावस्कर इस बात को लेकर इतने नाराज है कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर बल्लेबाज को रनर नहीं दोगे तो फिर गेंदबाज को मैच के बीच में पानी भी न दिया जाए. उनके मुताबिक, बल्लेबाजों पर लागू होने वाला नियम उतनी ही कड़ाई से फील्डिंग वाली टीम पर भी लागू होना चाहिए. नाराज गावस्कर ने यह सुझाव तक दे डाला कि गेंदबाजों को पानी न दिया जाए. वे एक ओवर डालते हैं और बाउंड्री पर आ जाते हैं, जहां उन्हें एनर्जी ड्रिंक्स दिया जाता है. गावस्कर ने कहा कि अगर आईसीसी को लगता है कि घायल बल्लेबाजों को रनर देना नाइंसाफी है तो उसे ड्रिंक्स ब्रेक भी खत्म कर देने चाहिए और वैकल्पिक फील्डर का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर देना चाहिए. किसी हद तक उनकी यह नाराजगी जायज नजर आती है. लेकिन सवाल अब भी वही है कि इस तरह के बदलावों का क्या औचित्य है? अच्छा तो यह होता कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चर्चा होती, नई प्रतिभाओं के भविष्य को लेकर योजनाएं बनतीं और इस खेल से जुड़े उन कर्मचारियों के विकास की बात होती, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर क्रिकेट के विशाल आयोजनों को कामयाबी की दहलीज तक ले जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट का व्यापार अभी जोरों पर है और सिर्फ रेनोवेशन मात्र से ही पब्लिसिटी बटोरने वालों की कमी नहीं है.

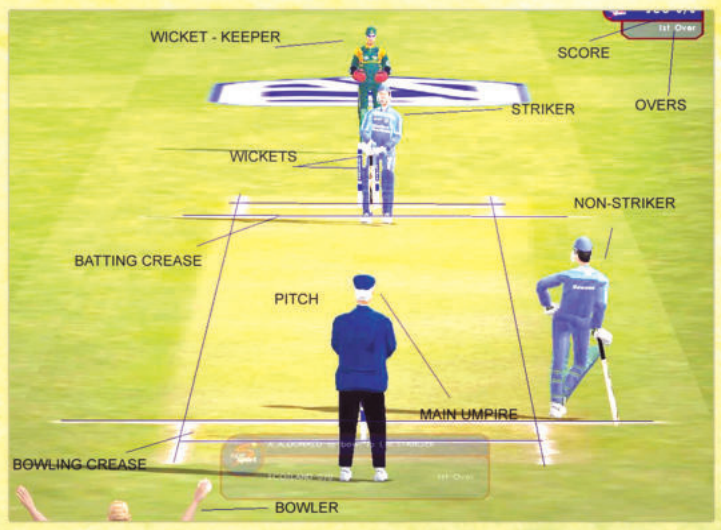

rajeshy@chauthiduniya.com

एक्सट्रा शॉट्स

श्रीसंत का भाई हीरो

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज श्रीसंत के छोटे भाई दीपू संत अपना करियर मलयालम फिल्मों में बनाने की राह पर चल पड़े हैं. पिछले दिनों उनकी पहली फिल्म काना कोमबाथू ने दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. मलयालम भाषा में बनी इस फिल्म के उद्घाटन समारोह में श्रीसंत के पूरे परिवार ने शिरकत की, लेकिन स्वयं श्रीसंत बंगलुरू में चल रहे क्रिकेट टीम के फिटनेस शिविर में व्यस्त होने के कारण शामिल नहीं हो सके.

अब मनोवैज्ञानिक जिताएंगे

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को मशहूर खेल मनोवैज्ञानिक रूडी वेबस्टर का सहारा मिल गया है. वेबस्टर भारत के साथ खेले जाने वाले टेस्ट मैच

से पहले खिलाड़ियों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे. बारबाडोस के मूल निवासी वेबस्टर ने अभ्यास सत्र के दौरान कैरेबियाई खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए उन्हें व्याख्यान दिए. वेबस्टर वर्ष 2006 में भारतीय टीम के साथ काम कर चुके हैं. वेस्टइंडीज टीम केखिलाड़ियों को इससे कितना फायदा होगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि वेबस्टर के लिए यह काम चुनौतीपूर्ण है.

करे कोई और भरे कोई

आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच जारी विवाद के कारण भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है. आईपीएल संचालन परिषद के सदस्य के तौर पर उनके काम का अब तक भुगतान नहीं किया गया है. गावस्कर 2008 से 2010 तक आईपीएल की संचालन परिषद के सदस्य रहे और उन्हें प्रत्येक वर्ष चार करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन मौजूदा प्रशासन ने अब तक इसे पूरा नहीं किया. तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष शरद पवार ने हालांकि तब गावस्कर को बोर्ड में शामिल होने के लिए एक करोड़ रुपये की पेशकश की थी. बीसीसीआई का कहना है कि इतनी राशि देने का आईपीएल के तत्कालीन आयुक्त ललित मोदी का फैसला गलत था. मोदी ने इस विवाद को खुद तूल दिया, जब उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष शशांक मनोहर ने गावस्कर केप्रति प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं किया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 11 जुलाई–17 जुलाई 2011

ज़रीन कहती हैं कि उन्होंने कभी एक लड़की की तरह ज़िंदगी को नहीं जिया, वह हमेशा टॉम ब्वॉय रही हैं. तभी तो उन्हें सिंपल रहना अच्छा लगता है.

हिट शो के लिए तरसते शो मैन-3

ज़रीन टिपिकल लड़की नहीं

हालिया रिलीज फिल्म रेडी के हिट आइटम नंबर कैरेक्टर ढीला में सलमान ख़ान के साथ धूम मचाने के बाद ज़रीन ख़ान के हौसले बुलंद हैं. उनकी अगली मंजिल है प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला और डायरेक्टर साजिद ख़ान की हिट फिल्म का सीक्वल हाउसफुल-2. वह ख़ुद बताती हैं कि रेडी के आइटम नंबर ने उन्हें फिर से सुर्ख़ियों में ला दिया है, नई पॉपुलैरिटी दे दी है. इस एक आइटम नंबर ने उनके करियर के लिए नया रास्ता खोल दिया. क्या कभी असल ज़िंदगी में आपका किसी लूज कैरेक्टर वाले आदमी से सामना हुआ? इस सवाल पर ज़रीन कहती हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ और इसकी वजह है उनके हाथ, क्योंकि उनके हाथ बहुत बड़े हैं और इतने बड़े हाथ देखकर लड़कों की हिम्मत नहीं हो पाती. ज़रीन कहती हैं कि वह टिपिकल लड़कियों जैसी नहीं हैं, एक्ट्रेस हैं, इसलिए उन पर रहने वाली पुरुषों की निगाहें उन्हें परेशान नहीं करतीं, उन्हें इससे कोई फ़र्क़ ही नहीं पड़ता. लोगों की अटेंशन पाने की आदत हो चुकी है. एक्ट्रेस बनने से पहले उनका वजन 100 किलो था, इसलिए अलग तरह की अटेंशन मिलती थी. पहले लड़के उन्हें देखकर उनके मोटापे को लेकर फब्तियां कसते थे. कम से कम अब तो इससे बेहतर है, क्योंकि अब पुरुषों का नज़रिया बदल गया है. ज़रीन कहती हैं कि उन्होंने कभी एक लड़की की तरह ज़िंदगी को नहीं जिया, वह हमेशा टॉम ब्वॉय रही हैं. तभी तो उन्हें सिंपल रहना अच्छा लगता है. उन्हें बग़ैर मेकअप के जींस, टी-शर्ट और चप्पल पहना पसंद है और वह बहुत ज़रूरी होने पर ही सजती-संवरती हैं. ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते सजने-संवरने में यक़ीन तो रखना ही होगा. वह कहती हैं कि उनकी स्किन बहुत सेंसेटिव है, इसलिए वह ज़्यादा मेकअप नहीं करतीं. वैसे भी उनका मानना है कि मेकअप जितना कम हो, उतना ही बेहतर है. नेचुरल ब्यूटी की बराबरी मेकअप नहीं कर सकता. ज़रीन कहती हैं कि वह आईने पर सबसे ज़्यादा यक़ीन करती हैं, क्योंकि वह दूसरों के बजाय ख़ुद पर ज़्यादा यक़ीन करती हैं.

राम गोपाल वर्मा : अति आत्मविश्वास महंगा पड़ा

सुषमा गुप्ता

बेहतरीन और बेहूदा एक-दूसरे के विलोम शब्द हैं. जिसे आप बेहतरीन से परिभाषित करेंगे, उसके लिए बेहूदा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते...और जो बेहूदा है, उसके साथ बेहतरीन शब्द नहीं जोड़ सकते. लेकिन फिल्मकार राम गोपाल वर्मा की फिल्में सिर्फ़ इन्हीं दो शब्दों से परिभाषित की जा सकती हैं. या तो उन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई हैं या फिर बेहूदा. अगर सत्या, कंपनी, रंगीला बेहतरीन फिल्में हैं तो निःशब्द, दौड़ और राम गोपाल वर्मा की आग बेहूदा. दरअसल, राम गोपाल वर्मा की ख़ूबी है कि वह प्रयोगधर्मी फिल्मकार हैं और प्रयोग करते हुए कभी वह एक फिल्म बनाकर फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज कर देते हैं तो कभी प्रयोग में हाथ जला बैठते हैं. हालांकि उसके बाद भी उनका प्रयोग जारी रहता है. काफी दिनों से राम गोपाल वर्मा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक धराशायी हो रही हैं. वह अलग-अलग विषयों पर अमिताभ जैसे स्टार के साथ फिल्में बना रहे हैं. ऐसे में सवाल उठना लाज़िमी है कि आख़िर रामू क्यों चूक रहे हैं.

राम गोपाल वर्मा के फिल्मों में आने की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है. फिल्मों में आने से पहले वह वीडियो पार्लर चलाते थे. फिल्में देखने का चस्का था. बार-बार देसी-विदेशी फिल्मों को वीसीआर पर ही देख-देखकर उन्होंने सिनेमा की तकनीक को समझा और एक पटकथा लिखी, जिसे निर्माता ने पसंद किया और उन्हें फिल्म बनाने का अवसर दिया. और वह बन गए निर्देशक. शुरुआत की शिवा से. यह फिल्म उस दौर की फिल्मों से काफी हटकर थी. केंद्र में था कॉलेज और वहां की राजनीति. फिल्म हिट रही. यह भारतीय फिल्मों में एक नए ट्रेंड की शुरुआत थी. मेनस्ट्रीम सिनेमा में यह पहली बार था कि कहानी मेलोड्रामा के दौर से बाहर निकल गई और रियलिटी के साथ शानदार तकनीक के इस्तेमाल ने ग़ज़ब का रोमांच पैदा किया. दर्शकों के लिए लाइट और प्रभावोत्पादक साउंड इफेक्ट देखना एक नया अनुभव था. यह फिल्म पाथब्रेकिंग फिल्म साबित हुई, जिसने दिखाया कि फॉर्मूला से हटकर सधी हुई कहानी, शानदार अभिनय, नए किस्म के साउंड इफेक्ट और कसी हुई एडिटिंग के ज़रिए भी दर्शकों को सिनेमाघर तक खींचा जा सकता है.

राम गोपाल वर्मा की अगली फिल्म रात भी पाथब्रेकिंग साबित हुई. यह फिल्म सुपर नेचुरल थ्रिलर थी. भारतीय दर्शकों के लिए यह एक नया तजुर्बा था, जिसमें रामसे ब्रदर्स के भूत नहीं हैं, फिर भी फिल्म दर्शकों को डराने की कूव्वत रखती है. तकनीक के तौर पर यह फिल्म भी ज़बरदस्त थी. इसके साथ ही राम गोपाल वर्मा इंडस्ट्री के ऐसे फिल्मकार बन गए, जिनकी तकनीक पर पकड़ कमाल की थी. किसी के लिए यक़ीन करना मुश्किल था कि वीडियो पार्लर चलाने वाले इस निर्देशक ने न फिल्मों की पढ़ाई की है और न कभी किसी का असिस्टेंट बनकर सिनेमा सीखा है. यह नए दौर का एकलव्य था, जिसने फिल्में देख-देखकर फिल्म बनाने में महारथ हासिल कर ली. इसके बाद रामू अपनी नई फिल्म आमिर और उर्मिला के साथ लेकर आए. यह फिल्म थी रंगीला, जो कि ख़ूब चली. एक सुपर नेचुरल, एक रियलिस्टिक और एक रोमांटिक. अ ा म तौर पर निर्देशक की पकड़ एक ही थीम पर होती है. उनकी अलग-अलग थीमों पर ज़बरदस्त पकड़ थी. दरअसल यह रामू की तीन बेहतरीन फिल्मों का दौर था, जिसकी छाप उनकी अगली फिल्मों में भी नज़र आई. रामू की तमाम फिल्मों पर नज़र डालने से पता चलेगा कि उनकी सारी फिल्में इन्हीं तीन थीमों पर आधारित हैं. या तो रामू की फिल्म सुपर नेचुरल होगी या खुलेपन वाली रोमांटिक या फिर रीयल. हालांकि इसके बाद उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पाईं और वह बेहतरीन फिल्में बनाने के चक्कर में कई बार बेहूदा फिल्में बना बैठे. इसके बाद का दौर उनके लिए मिला-जुला रहा. कभी उनकी फिल्में फ्लॉप होती तो कभी हिट. हालांकि इसके बाद उनके करियर की दो बेहतरीन फिल्में कौन और सत्या आईं, जिन्होंने सिनेमा को एक नए दौर में पहुंचा दिया. इन फिल्मों के साथ मेनस्ट्रीम में रामू ने डार्क शेड वाले कैरेक्टर पेश किए, जो न तो अच्छा था और न ख़राब.

लेकिन आज राम गोपाल वर्मा का जादू ग़ायब है. रामू ने एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की जगह बनाई, जिस पर कई डायरेक्टरों ने बॉलीवुड में पैर जमाए, पर रामू ख़ुद आज अपनी जगह तलाश रहे हैं. रामू को किसी ने मौक़ा दिया तो रामू फिल्म इंडस्ट्री में आए. इसलिए रामू भी ऐसे फिल्मकार के तौर पर देखे जाते हैं, जो दूसरों को मौक़ा देते हैं. चाहे वह अभिनेता हो, डायरेक्टर हो या अभिनेत्री. रामू के अभिनेत्रियों के साथ कई किस्से मशहूर हुए. एक के बाद एक अभिनेत्रियों को उन्होंने मौक़ा दिया. इसी तरह रामू ने कई निर्देशकों को भी मौक़ा दिया. लगातार कामयाबी के बाद रामू को यह गुमान हो गया था कि वह ख़ुदा हैं. वह जिसे चाहें बना सकते हैं, जिसका चाहें बिगाड़ सकते हैं. इस बात को उनके जेहन में बैठाने वाले आसपास के ही लोग थे, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए रामू का इस्तेमाल किया. इन लोगों को स्थापित करने के लिए रामू ने फिल्में बनाईं, जो न तो दर्शकों को पसंद आईं और न समीक्षकों को. रामू के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद मूडी, अकेले में मस्त रहने वाले और असामाजिक हैं. ऐसे आदमी आलोचनाओं की परवाह नहीं करते. रामू भी अपने आलोचकों की परवाह किए बग़ैर फिल्में बनाते चले गए. रामू यह भी कहते हैं कि वह फिल्म बनाने के बाद भूल जाते हैं. यानी वह फिल्म बनाने के बाद यह नहीं देखते कि फिल्म कैसी बनी है, उसमें क्या कमी रह गई है, जिससे अगली फिल्म के लिए वह ग़लती न दोहराई जाए. राम गोपाल वर्मा ओवर कांफिडेंस के शिकार हो गए. वह हमेशा से नई प्रतिभाओं को मौक़ा देते रहे हैं, लेकिन नई खोज ने ही उन्हें भरमा दिया. नया बनाने के चक्कर में वह दूसरी तरफ़ एक्सपेरिमेंट करते गए और उन्होंने निःशब्द एवं राम गोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्में बना दीं, जिनकी ख़ूब आलोचना हुई. रामू सामाजिक मान्यताओं पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सच्चाई यह है कि रामू को यह भी समझना पड़ेगा कि किस हद तक दर्शक फिल्मों को पचाएगा. निःशब्द चाहे जैसी भी फिल्म हो, लेकिन कोई अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार को 16 साल की लड़की के साथ प्यार करते नहीं देखना चाहेगा. इसके अलावा फिल्म के प्रचार के लिए अपनाए गए उनके तरीक़ों से फिल्मों की विश्वसनीयता भी ख़त्म होने लगी. फूंक के लिए उन्होंने दावा किया कि यह अब तक की सबसे डरावनी फिल्म है, लेकिन यह फिल्म बच्चों को भी डराने में असफल रही.

रामू की फिल्में पिटने लगीं तो वह अपनी फिल्मों की कहानियों को एक्सट्रीम पर ले जाने की कोशिश करने लगे. अपनी फिल्मों में हर वह चीज़ बढ़ाते गए, जिससे उन्हें लगता था कि यह उनकी कामयाबी का कारण है. अब उनकी फिल्में इतनी लाउड हो गईं कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया. चाहे वह रक्त चरित्र का बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या फिर ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर का डार्क ब्लैक हो जाना. दरअसल, रामू का जादू उनकी फिल्मों से ग़ायब है. वह जो भी फिल्में बना रहे हैं, वे बेहूदा की श्रेणी में ही गिनी जा रही हैं. कई के विषय दर्शकों को समझ में नहीं आए तो कई की कहानी. उनकी हारर फिल्मों ने डराना छोड़ दिया और रियलिस्टिक फिल्में इतनी रियल हो गईं कि उन्हें देखकर आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भर जाए. लेकिन लोग फिल्में मनोरंजन के लिए देखने जाते हैं, यह भी रामू को समझना होगा.

feedback@chauthiduniya.com

नई जंग की शुरुआत

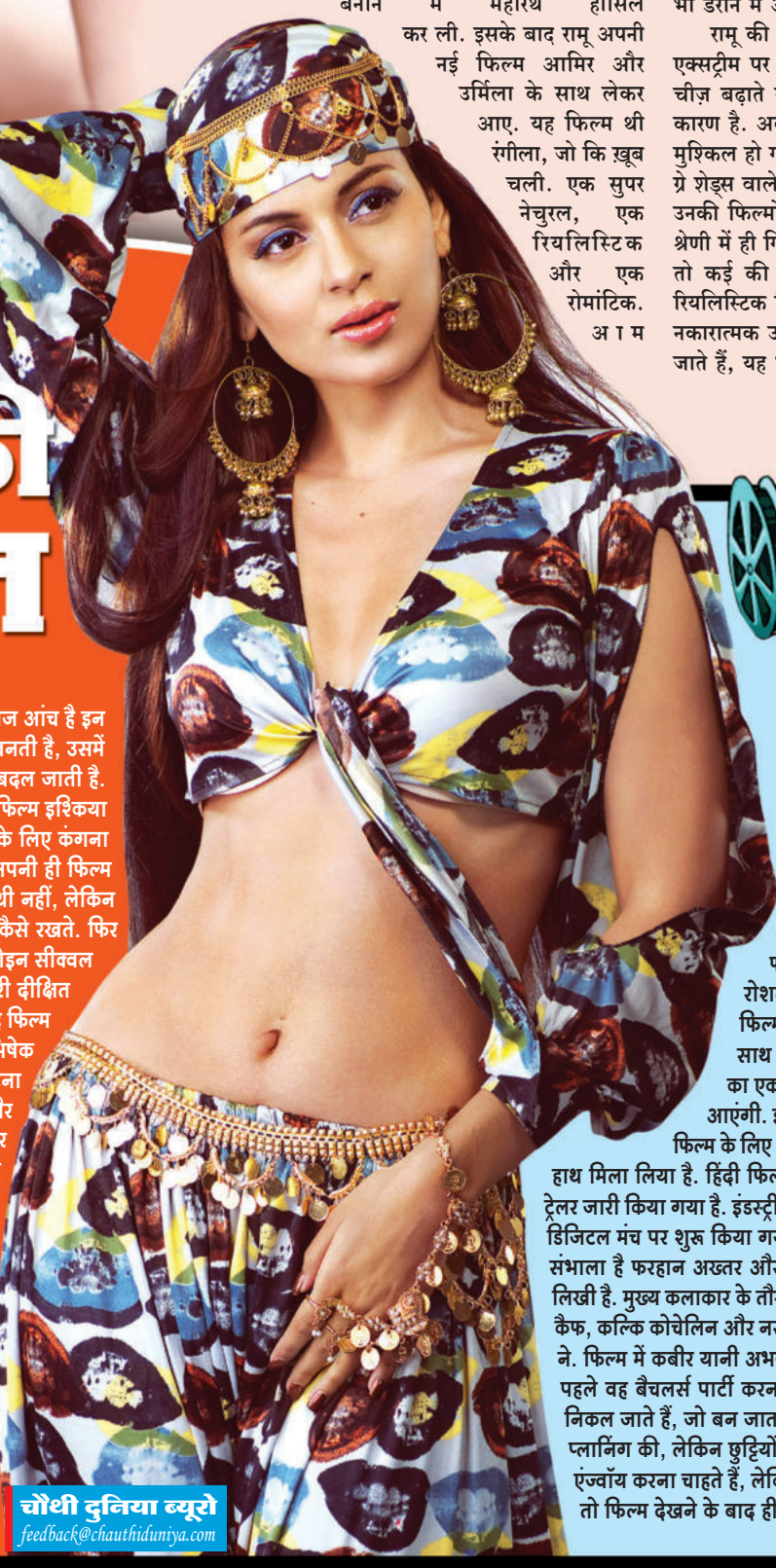

इंडस्ट्री में सीक्वल फिल्मों की आंधी जितनी तेज चली है, उतनी ही तेज आंच है इन फिल्मों में हीरोइन को रीप्लेस करने की. जिस फिल्म की सीक्वल बनती है, उसमें हीरो बेशक वही पुराने हों, लेकिन देखा गया है कि हीरोइन ज़रूर बदल जाती है. हीरोइन बदल कर सीक्वल बनाने का जो दौर चल रहा है, उसका प्रभाव हिट फिल्म इश्किया के सीक्वल पर भी पड़ा है. दरअसल इश्किया के सीक्वल डेढ़ इश्किया के लिए कंगना का नाम फाइनल कर दिया गया है. ग़ौरतलब है कि विद्या बालन अपनी ही फिल्म का सीक्वल नहीं कर रही हैं. वैसे विद्या के काम में कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन हीरोइन बदलने के फैशन से प्रोड्यूसर-डायरेक्टर ख़ुद को बाहर कैसे रखते. फिर जैसे ही बॉलीवुड की हीरोइनों को पता चला कि इश्किया की हीरोइन सीक्वल से बाहर है, उनमें इस फिल्म को झपटने की होड़ मच गई. माधुरी दीक्षित को लिए जाने की चर्चाएं चल रही थीं, फिर रानी मुखर्जी ने भी यह फिल्म करने की इच्छा ज़ाहिर की, लेकिन बाजी मारी कंगना ने. अभिषेक चौबे के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि कंगना के नाम पर मुहर लग गई है, लेकिन शायद एक और हीरोइन को कंगना के साथ लिया जा सकता है. अरशद वारसी और नसीर की जोड़ी एक बार फिर सीक्वल में नज़र आएगी. तभी तो आसमान में विचर रही हैं कंगना. ख़बर है कि कंगना ने एक फिल्म शूट के दौरान सिंगर मीका सिंह के साथ लिप-लॉक करने से मना कर दिया. यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन कंगना ने इससे आगे बढ़कर इस मामले में राखी का नाम घसीट लिया. बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा, मैं कोई राखी सावंत नहीं हूं, जो इस तरह की हरकत करूं. यह बात राखी तक पहुंच गई, जो उन्हें उकसाने के लिए काफी थी. राखी ने अपनी आदत के मुताबिक़ फ़ौरन हमला किया. उन्होंने कहा, कंगना में इतनी हिम्मत कहां से आ गई. प्रचार पाने के लिए उन्होंने मेरे कंधे पर रखकर बंदूक़ चलाई है. मैंने कभी मीका को किस नहीं किया. जैसा कि सभी जानते हैं कि मीका ने जोर-ज़रदस्ती से यह किया था. कंगना को प्रचार पाने की इतनी ही भूख है तो उन्हें गाने में मीका को किस करना चाहिए, ताकि पब्लिसिटी मिल सके, मेरा नाम घसीट कर वह प्रचार क्यों पाना चाहती हैं? अब तो एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है. लगता है कि कंगना को राखी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा

फरहान अख्तर की फिल्म ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा में रितिक रोशन कैटरीना कैफ के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नज़र आएंगे. इस फिल्म में वह बार्बी डॉल के साथ लिप-लॉक भी करेंगे. कैटरीना के साथ पहली बार काम करते हुए रितिक काफी उत्साहित हैं. इस फिल्म का एक सीन कैट पर स्पेन में फिल्माया गया, जिसमें वह टॉपलेस नज़र आएंगी. इस फिल्म में अभय देओल, फरहान अख्तर और कल्कि भी हैं. इस फिल्म के लिए एक्सएल एंटरटेनमेंट ने एयरसेल और पान इंडिया ऑपरेशन केसाथ हाथ मिला लिया है. हिंदी फिल्म ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा का पहला डिजिटल और मोबाइल ट्रेलर जारी किया गया है. इंडस्ट्री के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी फिल्म का पहला ट्रेलर डिजिटल मंच पर शुरू किया गया हो. फिल्म के निर्देशक जोया अख्तर हैं और निर्माण का कार्य संभाला है फरहान अख्तर और रितेश सिध्वानी ने. फिल्म की पटकथा ख़ुद जोया अख्तर ने लिखी है. मुख्य कलाकार के तौर पर इसमें रितिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल, कैटरीना कैफ, कल्कि कोचेलिन और नसीरुद्दीन शाह नज़र आएंगे. संगीत दिया है शंकर-एहसान-लॉय ने. फिल्म में कबीर यानी अभय देओल की छह महीनों में सगाई होने वाली होती है और उससे पहले वह बैचलर्स पार्टी करना चाहते हैं. अपने दोनों दोस्तों के साथ वह एक लंबी छुट्टी पर निकल जाते हैं, जो बन जाता है उनकी लाइफ का ट्विस्ट. कॉलेज के दौरान उन्होंने कई बार प्लानिंग की, लेकिन छुट्टियों पर निकल नहीं सके. इस बार तीनों दोस्त छुट्टियों को पूरी तरह एंज्वॉय करना चाहते हैं, लेकिन क्या है उनकी छुट्टियों के दौरान घटित घटनाओं का राज, यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 11 जुलाई–17 जुलाई 2011

www.chauthiduniya.com

स्वार्थतंत्र में लोकतंत्र गुम

फोटो–प्रभात पाण्डेय

महाराष्ट्र की राजनीति में स्वार्थ का पलड़ा इतना भारी हो चुका है कि राजनेता राज्य की जनता के मुद्दों को छोड़कर आपसी गुटबाज़ी और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए साम-दाम-दंड-भेद की नीतियों में ही उलझे रहते हैं. भले ही उनकी इस तरह की गतिविधियों से लोकतंत्र का मखौल ही क्यों न बनकर रह जाए.

मुंडे के हालिया क़दम से राजनीतिक विश्लेषक हतप्रभ हैं. किसी के गले यह बात नहीं उतर रही है कि मुंडे बिना किसी ठोस और सार्वजनिक कारण के इतना बड़ा क़दम उठा लेंगे कि वे कांग्रेस में शामिल होने तक की बात अंदर ही अंदर करने लगेंगे.

प्रवीण महाजन

लगता है महाराष्ट्र सहित समूचे देश में स्वार्थतंत्र की आड़ में लोकतंत्र कहीं गुम हो गया है और व्यक्तिवाद की आड़ में राष्ट्रवाद काफ़ी पीछे छूट गया है. आज़ादी के बाद से अब तक जनता ने कई नेता देखे. अब तो जनता की हालत भी कुछ ऐसी हो गई है कि वह राजनीति के मामले में ज़्यादा कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं है. अगर सोचने की स्थिति में है तो उसे अभिव्यक्त करने की स्थिति में नहीं है. हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़ी घटनाएं हुईं. पहली शिवशक्ति-भीमशक्ति गठजोड़, कुल मिलाकर रामदास आठवले का शिवसेना के साथ हाथ मिलाना और उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्रचारित करना. दूसरी बड़ी घटना थी कभी भाजपा की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले नेता गोपीनाथ मुंडे का रूठ जाना. दोनों ही घटनाओं की अपनी अलग चाल, चरित्र और चेहरा है मगर दोनों ही मामलों में एक बात समान है और वह है लोकतंत्र की क़ीमत पर स्वार्थतंत्र का हावी होना.

पहले बात भाजपा के लोकसभा उपाध्यक्ष गोपीनाथ मुंडे की. दरअसल, पहले मुंबई अध्यक्ष और फिर पुणे अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे में ख़ासी ठन गई थी. अब जबकि अगले साल फ़रवरी में राज्य के 9 स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होने हैं, सभी राजनीतिक दलों और राजनेताओं ने अपनी-अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली हैं.

गोपीनाथ मुंडे के हालिया क़दम से राजनीतिक विश्लेषक हतप्रभ हैं. किसी के गले यह बात नहीं उतर रही है कि मुंडे बिना किसी ठोस और सार्वजनिक कारण के इतना बड़ा क़दम उठा लेंगे कि वे कांग्रेस में शामिल होने तक की बात अंदर ही अंदर करने लगेंगे. अब सवाल यह उठता है कि आख़िर मुंडे को उकसाया किसने. मामला साफ़ है. उमा भारती के भाजपा में शामिल होते ही दिल्ली में भाजपा की जनाधारविहीन तिकड़ी तिलमिला गई. अंदर ही अंदर खिचड़ी पकने लगी. इधर महाराष्ट्र में कभी कांग्रेस पर तो कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पर आरोप पर आरोप लगने लगे. दिल्ली में चल रहे घटनाक्रमों से भी कांग्रेस को यह बात साफ़ समझ में आ गई है कि रामदेव बाबा और अन्ना हज़ारे को कमज़ोर करने से पहले विपक्ष को कमज़ोर करना ज़रूरी है. साम-दाम-दंड-भेद के इस खेल में कांग्रेस माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है. अब सवाल भाजपा की दिल्ली की तिकड़ी का. तो जैसे ही तिकड़ी को लगा कि उमा भारती भाजपा में आ चुकी हैं, अब वह पुराना हिसाब-किताब बराबर न कर लें, तो इस तिकड़ी ने मुंडे को हथियार बना लिया. मुंडे भी महाराष्ट्र में अपनी लगातार हो रही अवहेलना से काफ़ी दुखी थे. मुंडे पिछड़े वर्ग के नेता हैं. उमा भारती भी पिछड़े वर्ग की नेता हैं. यह बात अलग है कि मुंडे की दूर-दूर तक कोई तुलना उमा भारती से नहीं हो सकती. ख़ैर, महाराष्ट्र में मनपा के चुनाव भी सिर पर हैं. अगर इसमें भी मुंडे की नहीं चली तो उनके राजनीतिक भविष्य पर ही सवालिया निशान लग जाएंगे. गडकरी दिन-प्रतिदिन मज़बूत होते जा रहे हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उनको वरदहस्त प्राप्त है. पहले जसवंत सिंह और फिर उमा भारती का भाजपा-प्रवेश दिल्ली की तिकड़ी के लिए अच्छी सीख है. वैसे मुंडे को बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी योजना तैयार कर ली गई थी. मुंडे ने भी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की मार्फ़त अहमद पटेल तक अपनी पैठ जमा ली थी, लेकिन कहते हैं न, कांग्रेस में गरम खाना खाने की आदत नहीं है. कांग्रेस में प्रवेश कांग्रेस की शर्तों पर होता है प्रवेश करने वालों की शर्तों पर नहीं. रात डेढ़ बजे तक चर्चा हुई. वैसे भी एक बड़े नेता का मुंडे के कांग्रेस में प्रवेश पर विरोध था. नारायण राणे को कांग्रेस में आकर क्या मिला, यह सभी को मालूम है. जब भी ज़्यादा बयानबाज़ी करते हैं, उनके पर कतर दिए जाते हैं. जब कांग्रेस में बात नहीं बनी तो मुंडे भी नरम पड़े और दिल्ली की तिकड़ी में एक सुषमा स्वराज से मिले. ख़ैर, इस बीच आख़िरी क्षणों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तेवर भी नरम हुए और मामला आगे के लिए टाल दिया गया. इस बीच गोपीनाथ मुंडे ने दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाक़ात की. बताते हैं कि आडवाणी ने मुंडे को इस समूचे घटनाक्रम के लिए भरपूर फटकार लगाई, लेकिन राजनीतिक हलक़ों में आश्चर्य तो इस बात का है कि दिल्ली में कांग्रेस के दरवाज़े से बुरी तरह बेइज़्ज़त होकर लौटे मुंडे की जब सुषमा स्वराज से मुलाक़ात हो गई और फिर मुंबई में जब रात का भोजन गडकरी के साथ तय हो गया तो उसके बाद भी मुंडे ने इसे भाजपा की कमज़ोरी मानकर मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच परोक्ष रूप से गडकरी पर निशाना साध दिया कि उन्हें नीचा दिखाने वालों को एक दिन ख़ुद नीचा देखना पड़ेगा. सूत्र बताते हैं कि मुंडे की-रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई-जैसी हरकत के बाद न सिर्फ़ गडकरी नाराज़ हो गए, बल्कि संघ व भाजपा का वह कोर ग्रुप भी नाराज़ हो गया जो कांग्रेस द्वारा ठुकराए जाने के बाद उन्हें वापस अपनाने के लिए नरम पड़ गया था. यही कारण था कि गडकरी के साथ मुंडे का प्रस्तावित रात्रिभोज भी रद्द कर दिया गया. इस समूचे घटनाक्रम में किसका व्यक्तिगत स्वार्थ सधा और जनसामान्य को क्या मिला, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे.

अब बात रामदास आठवले की. डॉ.बाबासाहब आंबेडकर के नाम पर जिस आंबेडकरी जनता को समूचे देश में ही नहीं वरन विश्व में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है, उनकी अनुयायी के रूप में स्वयं को स्थापित करने वाली राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (कई घटकों में विभक्त) का इतिहास भी अजीब ही रहा है. जब आंबेडकरी विचारधारा की बात आती है तो सुर एक होते हैं, मगर जब राजनीति और सत्ता की बात आती है तो कई गुट हो जाते हैं. और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब कहना ही क्या, उनका कई गुटों में बंटना राजनीतिक विश्लेषकों के साथ-साथ आम जनता के लिए मखौल बन जाता है. ख़ैर, इस समय बात महाराष्ट्र में भीमशक्ति और शिवशक्ति की हो रही है. बता दें कि आंबेडकर, गवई, कवाड़े, आठवले, कांबले (पार्टियों के नाम अलग-अलग) के साथ कई अन्य समूहों में रिपब्लिकन आंदोलन विभक्त है. सभी का जनाधार एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है. अन्य क्षेत्रों में गिने-चुने कार्यकर्ता इन नेताओं के हैं. महाराष्ट्र को अगर अपवादस्वरूप छोड़ दिया जाए तो रिपाइं ने हमेशा किसी न किसी से गठजोड़ किया ही किया है. रिपब्लिकन पार्टी का समूचा राजनीतिक करियर गठबंधन और सत्ता की राजनीति पर टिका हुआ है. कुछ लोगों को इससे अलग किया जा सकता है. आठवले गुट ने तो पहले कांग्रेस-राष्ट्रवादी फिर रिडालोस के माध्यम से गठजोड़ किया. दोनों ही प्रयोग विफल रहे. मज़े की बात यह है कि रिपाइं (आठवले) का अपने दम पर चुनाव लड़ना संभव ही नहीं है. इसलिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत उसे पड़ती है. भारतीय राजनीति में अटलबिहारी वाजपेयी के समय से शुरू हुई गठजोड़ की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य सत्ता की राजनीति ही है. अगर इस पर शिवशक्ति और भीमशक्ति अपने आपको समूचे राज्य का प्रतिनिधि बता रहे हैं तो कुछ भी ग़लत नहीं कर रहे हैं. ग़लत तो तब होगा, जब मनपा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे. दरअसल शिवसेना को भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की काट चाहिए और इसके लिए उसे अतिरिक्त वोट चाहिए. कमोबेश आठवले गुट का वोट बैंक कुछ हद तक उन्हीं क्षेत्रों में सीमित है जहां मनसे का वोट बैंक है. शिवशक्ति और भीमशक्ति को इतना अधिक प्रचारित करने के पीछे फिर भी कोई कारण समझ में नहीं आया. जनता की तो बस यही अपेक्षा है कि रिपब्लिकन पक्ष के किसी भी नेता को कोई भी क़दम उठाने से पहले आंबेडकरी आंदोलन को ध्यान में रखना चाहिए और राजनीति दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो गई है : वानखेड़े

वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत वानखेड़े का कहना है कि अब राजनीति लोक केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित हो गई है. कई साल से सत्ता कांग्रेस के पास है. इसके पहले लोगों ने भाजपा-शिवसेना को भी मौक़ा दिया. उन्होंने भी वही किया जो कांग्रेस ने किया. वहां भी परिवारवाद हावी रहा. आज लोगों को विपक्ष से कोई अपेक्षा नहीं रह गई है. यही कारण है कि गले तक भ्रष्टाचार में डूबी केंद्र की सरकार के प्रति जनता उदासीन है. अन्ना हज़ारे के लिए जो समर्थन दिखा तो मीडिया और कार्पोरेट हाउस की देन थी. आम जनता की नहीं. सामान्य जनता उनके आंदोलन के समय भी सड़क पर नहीं आई. अन्ना ने भी व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं की. उन्होंने सिर्फ़ लोकपाल बिल लाने की बात की. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हर जगह शांति है, क्योंकि इस मामले में विपक्ष भी शांत है. विपक्ष की जो भूमिका दिखनी चाहिए, वह नहीं दिखती है. जब मुंडे ने देखा कि मनपा चुनाव के टिकट वितरण में महत्व नहीं मिल रहा है तो दबाव बनाना शुरू कर दिया. कोई जनहित की बाद नहीं करता है.

असंभव को कर दिखाया संभव

मध्य वर्ग की पारिवारिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति का भी राजनीति में यथोचित स्थान बनाना मुश्किल नहीं है. महाराष्ट्र में एक ऐसा ही व्यक्तित्व है जिसने न सिर्फ राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है बल्कि अपनी स्पष्ट कार्यशैली की वजह से आज पार्टी के इर निर्णय में उसका विशेष स्थान है. जी हां, हम बात कर रहे हैं, राज्य केजल संपदा मंत्री और राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आधार-स्तंभ बन चुके सुनील तटकरे की. कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद उनकी ख़ासियत है. वे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के दाहिने हाथ और केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार केख़ास सिपहसालारों में शुमार हैं. दूरदृष्टि संपन्न, पक्के इरादों वाले, कुशल प्रबंधक और कुशल राजनीतिज्ञ जैसे विशेषणों से प्रभावशाली कोई और भी विशेषण होता तो वह भी तटकरे पर सटीक बैठता. मंत्रिमंडल में किसी भी विभाग की ज़िम्मेदारी संभालते हुए उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में उनकी परिपक्वता और ज़मीनी पकड़ साफ़ झलकती है. 10 जुलाई को उनका जन्मदिन है. चौथी दुनिया, महाराष्ट्र की ओर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.

राजनेता कम, जननेता अधिक - जनसेवा की ख़ूबियों की कसौटी पर यदि कसा जाए तो कोंकण केश्रीवर्धन निर्वाचन क्षेत्र का विधानसभा में नेतृत्व करने वाले जल संपदा मंत्री सुनील तटकरे सोलह आने ख़रे उतरते हैं. वे अपने क्षेत्र के घोर गरीब, दीन-दुर्बलों की सेवा का संकल्प लेकर राजनीति के क्षेत्र में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हुए. अपने कृतित्व के दम पर पहले ज़िला परिषद अध्यक्ष बने और फिर विधायक बन विधानसभा पहुंचे. वे दो दशकों से अधिक समय से अपने विधायी और जनहितकर के कार्यों को बख़ूबी निभा रहे हैं.

उन्होंने निर्विवाद राजनीति की साफ़-सुथरी तस्वीर पेश की है. उन्होंने अपने क्षेत्र में विविध विकास कार्यों व विधायक निधि से संचालित उपक्रमों को हमेशा बढ़ावा दिया है. खेल, शिक्षा, समाजसेवा, सांस्कृतिक, कला क्षेत्र में कुछ अलग करने की इच्छा रखने वाले अनेक लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया और समय-समय पर आर्थिक व अन्य प्रकार की मदद करते रहते हैं. इन्हीं ख़ूबियों की वजह से आज उन्होंने जन-जन के लोकप्रिय नेता के रूप में अपनी विशिष्ट जगह बनाई है.

अन्ना की चाहत थी चिकित्सक बनें - सुनील तटकरे का जन्म 10 जुलाई 1955 को रोहा तहसील के कोलाड नाम के छोटे से गांव में हुआ था. उनके पिता दत्तात्रेय तटकरे उर्फ अन्ना की आर्थिक-सामाजिक स्थिति बेहतर थी. ऐसे वातावरण में पले-बढ़े तटकरे की जीवनचर्या अलग ही थी. जाति, धर्म, पंथ का विचार न करते हुए सभी से विनम्रता से मिलने और हमेशा सभी के काम करने को तत्पर रहते थे. इसे ही उन्होंने अपने जीवन का सूत्र बना लिया. विद्यार्थी जीवन में एक अत्यंत कुशाग्रबुद्धि वाले छात्र के रूप में उनका सम्मान था और वे प्रत्येक परीक्षा में सदा प्रथम स्थान हासिल करते रहे. अन्ना की प्रबल इच्छा थी कि उनकेपुत्र चिकित्सक बनकर जनता की सेवा करें परंतु सुनील के दिमाग में कुछ और ही पल रहा था. उनका मानना था कि डॉक्टर बनकर काग़ज़ पर दवा लिखने से क्षेत्र विशेष की ही जनसेवा हो सकती है जबकि वे महाराष्ट्र के साथ-साथ समग्र भारत की जनता की सेवा करना चाहते थे. लोगों के जीवन-स्तर में कैसे सुधार लाया जाए, उनके जीवन-स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए यही उनके सरोकारों का विषय था. इन्हीं मूलभूत ज़रूरतों पर उनका ज़ोर था. तटकरे ने इसी दिशा में कार्य करना शुरू किया. 1962 में रोहा पंचायत समिति के सभापति बनने के बाद पूरे 14 वर्षों तक अन्ना इस पद पर रहे. इस दौरान जनता के दुख-दर्द और समस्याओं को नज़दीक से जानने के लिए लगातार उनके दौरे होते थे. दौरे के दौरान सुनील अक्सर उनके साथ रहते थे जिससे उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनकी राजनीति में रुचि बढ़ती चली गई. जब सुनील तटकरे के मन में जनसेवा की नई-नई संकल्पनाएं आकार ले रही थीं तभी अचानक 1984 में उनके पिता का दुःखद निधन हो गया. परिणामतः परिवार की सारी जवाबदारी सुनील और अनिल के कंधों पर आ गई. बीच में ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने बीस वर्ष की उम्र में निर्माण कार्य के व्यवसाय में क़दम रखा.

यूं शुरू हुआ राजनीतिक सफ़र - सुनील तटकरे का राजनीतिक सफ़र कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ. वे 1984 से 1992 तक रायगढ़ ज़िला युवक कांग्रेस और रोहृ तालुका कांग्रेस समिति के सचिव रहे. 21 मार्च 1992 से 1995 की समयावधि में वे रायगढ़ ज़िला परिषद के अध्यक्ष रहे. 1995 में वे पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए. उस समय कोंकण क्षेत्र में जब कांग्रेस के सभी उम्मीदवार पराजित हो गए थे तब एकमात्र सुनील तटकरे ही ऐसे कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो कोंकण क्षेत्र से विजयी होकर विधानसभा पहुंचे थे. अक्टूबर 1999 से जनवरी 2003 के मध्य नगरविकास राज्यमंत्री के रूप में उन्होंने नगर विकास कार्यों में अपना सहयोग दिया. 2004 में उन्हें मंत्रीमंडल में पदोन्नत कर नागरिक आपूर्ति मंत्रालय देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया और इस पद पर वे 2008 तक बने रहे. 10 दिसंबर 2008 को उन्हें राज्य के ऊर्जा मंत्रालय की ज़िम्मेदारी दी गई. जिस समय उन्होंने ऊर्जा मंत्री का पदभार संभाला, उस वक्त बिजली की कमी से जनता त्रस्त थी. यह समस्या जादू की छड़ी घुमाने से एक दिन में हल होने वाली नहीं थी, परंतु इस विकट समस्या से निपटने की ज़िम्मेदारी तटकरे ने स्वीकार की. ऊर्जा मंत्रालय संभालते ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और पूरे राज्य में बिजली के उत्पादन और खपत की जानकारी हासिल की. तदुपरांत उन्होंने हर क्षेत्र में जाकर क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की. निजी क्षेत्र द्वारा बिजली बनाने के लिए राज्य व देश के शीर्ष उद्योगपतियों से विचार-विनिमय किया. उसके बाद 2013 तक राज्य को लोडशेडिंग मुक्त बनाने की दृष्टि से एक ब्ल्यू प्रिंट तैयार किया. परिणामस्वरूप केवल दो वर्षों में बिजली की तस्वीर बदलने लगी. वर्ष 2009 में तटकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में श्रीवर्धन निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विजयी रहे. प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को सुलझाने की उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें राज्य के खजाने की चाबी सौंपी गई यानी वित्त मंत्री बनाया गया. 2010 तक वित्त मंत्रालय संभालने के बाद पृथ्वीराज चव्हाण के मुख्यमंत्री बनने पर तटकरे को अजीत पवार का पुराना जलसंपदा मंत्रालय का दायित्व दिया गया जिसे वे वर्तमान में संभाल रहे हैं. तटकरे प्रखर बुद्धिवादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं. वे समर्थ व शक्तिशाली महाराष्ट्र की संकल्पना के कट्टर समर्थक हैं.

जब रातों रात तैयार हुआ कबड्डी मैदान - राजनीति में आज समर्पित जननेताओं की कमी से जनता में राजनीतिक क्षेत्र को लेकर नकारात्मक विचार तेजी से बढ़ रहा है पर तटकरे का जीवन जनता की इस धारणा को तोड़ता है. तटकरे एक सुलझे और जनता के प्रति समर्पित नेता हैं. वे जनता से जुड़े कार्यों को किस समर्पण के साथ अंजाम देते हैं इसका पता यहां उल्लिखित एक घटना से चलता है. क्रीब छह-सात वर्ष पहले यह घटना रायगढ़ ज़िले के रोहा गांव में घटित हुई थी. अवधूत तटकरे मित्र मंडल ने अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धा आयोजन करने की जवाबदेही अपने कंधों पर ली थी. प्रतियोगिता प्रारंभ होने में मात्र चार दिन बचे थे. मैदान को दुरुस्त करने का काम शुरू था. फावड़े, गैंती और तगाड़ी की कर्कश ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी. इतने में कबड्डी के महर्षि शंकरराव उर्फ बुवा सालवी की कड़कड़ाती आवाज सुनाई दी- तुम लोगों को जमता नहीं तो स्पष्ट बताओ. एक क्षण में यह स्पर्धा दूसरी जगह आयोजित करता हूं. इस तरह का हुलमुल रवैया मुझे पसंद नहीं है. उनका रौद्र रूप देख कर सभी लोग हक्के-बक्के रह गए. एक युवा कार्यकर्ता ने भाग कर संस्था के सर्वेसर्वा सुनील तटकरे को इसकी जानकारी दी. परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए तटकरे तत्काल बुवा सालवी के सामने उपस्थित हुए और विनम्रतापूर्वक हंसते-हंसते बोले- कल शाम छह बजे तक पूरा स्टेडियम तैयार कर दिया. बुवा सालवी ने इस घमत्कार को देखकर कहा-तटकरे साहब ने कमाल कर दिया. यह कमाल तटकरे की समर्पित भाव से जनहित में कार्य करने की भावना और उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है. आज़िद शरद पवार के शार्गिद जो ठहरे तटकरे. आदमी को अपने साथ जोड़ने की कला उन्होंने वसंतदादा पाटिल से सीखी है. इसलिए वसंतदादा पाटिल और शरद पवार की परंपरा को अब तटकरे आगे बढ़ा रहे हैं. उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का भाई तुल्य समर्थन. इसे ही उनकी सफलता का राज कहा जा सकता है.

दीन-दुखियों के नेता - पिता के साथ गांव-गांव दौरा करने के दरम्यान उन्होंने ग़रीब ग्रामवासियों की पीड़ा-समस्या का अवलोकन किया. वे हमेशा अपने आस-पास के दीन-दुर्बलों की समस्याओं को लेकर चिंतित रहते थे और उनके समाधान के विषय में सोचते रहते थे. अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के बीच उन्होंने कभी ग़रीबों को नहीं भुलाया. इसकी छाप उनकेविविध पदों पर रहते हुए किए गए कार्यों में दिखाई देती है. रत्नागिरी ज़िले के पालकमंत्री रहते हुए जिस तरह से नागरिकों की समस्याओं को समझा, सुलझाया वह उनकी जनसेवा, समाजसेवा और राजनीतिक दक्षता का ही उदाहरण है. आज भी जब वे अपने क्षेत्र या अन्य कहीं दौरे पर जाते हैं तो विश्राम गृह में ही ठहरते हैं जहां आकर कोई भी सामान्य नागरिक अपनी समस्या उनकेसमक्ष रख देता है. वे उसकी समस्या को ध्यान से सुनते हैं और समाधान के उपाय करते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि कोई व्यक्ति समस्या या मांग लेकर सुनील तटकरे के पास जाए और कुछ न मिले, ऐसा हो नहीं सकता है. समस्या का समाधान किया जाता है और मांग पर मांग की उपयोगिता के आधार पर पर्याप्त सहयोग मिलता है. तटकरे ने नागरिक आपूर्ति मंत्री रहने के दौरान यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अंत्योदय योजना और बीपीएल परिवारों को उनके हक़ का अनाज समय पर मिले. इसकेलिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को दुरुस्त किया.

पद को सम्मान दिलाने वाला नेतृत्व - राजनीतिक क्षेत्र में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनका पद मिलने से सम्मान बढ़ जाता है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकेपद संभालने से पद का मान बढ़ जाता है. पद का मान बढ़ाने वाले नेता विरले ही होते हैं, क्योंकि वे अपने कार्य से लोककल्याण करते हैं. ऐसे ही कुछ विरले नेताओं में से एक हैं सुनील तटकरे. तटकरे ने रायगढ़ ज़िला परिषद अध्यक्ष के पद से लेकर विधायक, नगरविकास राज्यमंत्री, नागरिक आपूर्ति मंत्री, ऊर्जा मंत्री और वित्तमंत्री का पद संभाला है. वर्तमान में वे जलसंपदा मंत्रालय का कामकाज देख रहे हैं. उन्होंने राज्य व जनता के हित में कार्य करके हर पद के साथ न्याय किया है. कभी भी पद का उपभोग स्वयं के हित में न करते हुए उन्होंने जनकल्याण को ही वरीयता दी है. रायगढ़ ज़िला परिषद का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ज़िला परिषद प्रशासन को अधिक से अधिक लोकाभिमुख बनाया. विकास से वंचित जिले के दुर्गम क्षेत्रों में विकास की गंगा प्रवाहित करने का काम कर ज़िला परिषद अध्यक्ष होने का सही अर्थ सिद्ध किया. जिले के सभी तहसीलों में विकास के समान रूप से अवसर उपलब्ध कराए, यही वजह है कि जब 1995 के विधानसभा चुनाव में कोंकण क्षेत्र में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी पराजित हो गए थे तब एक मात्र विजयी उम्मीदवार सुनील तटकरे ही थे. वह उनकी दूरगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने से बनी सर्वस्वाही छवि का कमाल ही था कि तब उन्होंने कोंकण में अकेले कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा. उन पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता पूर्ण विश्वास रखते हैं और तटकरे अपने मतदाताओं का विश्वास कभी टूटने नहीं देते. वे सच्चे जनप्रतिनिधि की कसौटी पर ख़रे उतरते हैं इसलिए वे विवादों से परे रह कर अपने कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं और जिस पद पर रहते हैं उस पद का मान स्वतः बढ़ जाता है.

कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद - किसी नेता के लिए राजनीति में सफलता की पहली सीढ़ी है समर्पित कार्यकर्ताओं का साथ होना. इसके लिए ज़रूरी है अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना. सुनील तटकरे अपनी पार्टी व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं, उनकेविचार, सुझाव को आदरपूर्वक सुनते हैं. उनकेयोग्य विचार व सुझाव पर अमल भी करते हैं. रायगढ़ हो या रत्नागिरी या अन्य कोई ज़िला, कार्यकर्ता उनसे निर्भीक होकर मिलते हैं. रायगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे तटकरे साहब कार्यकर्ताओं और नागरिकों के बीच जाने में किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं लेते हैं. वे हमारे जनप्रिय नेता हैं और हम उनसे बिना किसी संकोच के अपनी बात कहते हैं.

निष्पक्ष भूमिका - सुनील तटकरे ऐसे नेता और मंत्री के रूप में जाने जाते हैं जो जनहित या विकास केमामले में निष्पक्ष निर्णय लेते हैं. विकास के मामले में वे दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर कार्य करते हैं. जब तटकरे नगरविकास मंत्री थे तब एक बार रत्नागिरी के खेड तालुका स्थित पोखरण ग्राम के अपने ससुराल में आए. उस समय खेड नगर परिषद में शिवसेना का कब्जा था. उस दरम्यान खेड नगर परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष विपिन पाटणे तटकरे के पास आए और नाट्यगृह के लिए उनसे निधि उपलब्ध कराने की मांग की. इस पर तटकरे ने यह सोचते हुए कि नाट्यगृह का लाभ खेडवासियों को मिलेगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर विधायक निधि से इसके लिए रुपए उपलब्ध कराने का वचन दिया. आज तटकरे की विधायक निधि से निर्मित स्व. मीनाताई नाट्यगृह खेड की शोभा बढ़ा रहा है. ऐसे कई उदाहरण रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में देखने को मिलते हैं. जनप्रिय नेता सुनील तटकरे जनहित-विकास के मुद्दे पर कोई पक्षपात नहीं करते इसीलिए कोंकण में उन्हें जन-जन का नेता कहा जाता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthidunya.com

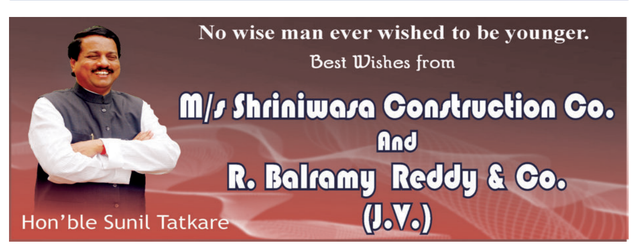

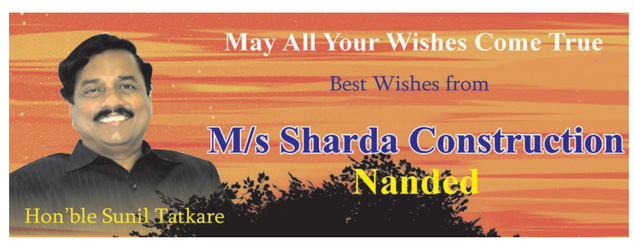

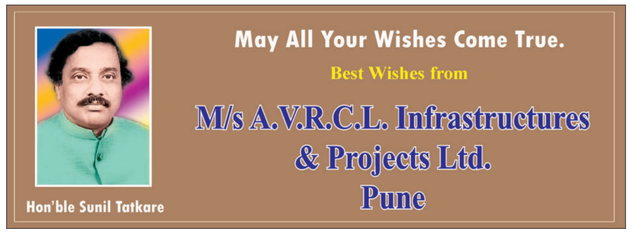

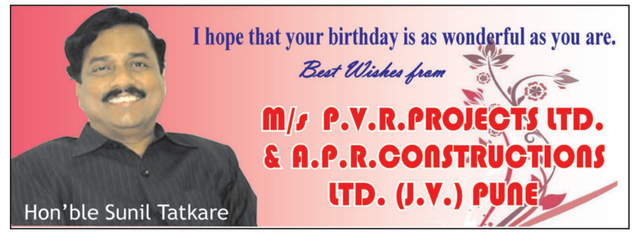

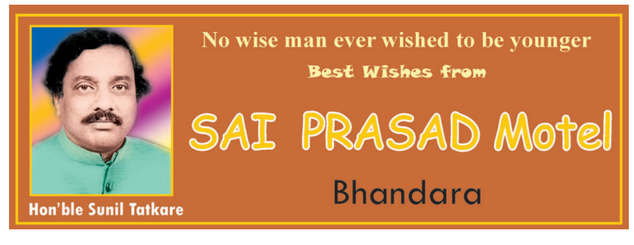

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

सब गोलमाल है. सोनिया मैडम के तो हाल इतने बेहाल हैं कि आज कोई पक्ष का हो या विपक्ष का, किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई उनसे गुस्ताख़ी कर सके.

महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री सुनील तटकरे की चौथी दुनिया से ख़ास बातचीत

पानी पर पहला अधिकार खेतों का

अजीत पवार के कार्यकाल के दौरान हुए कार्य

- पिछले कार्यकाल में (2004-05 से 2008-09 के बीच) सिंचाई विकास केलिए 22,300 करोड़ रुपये का निवेश किया गया.
- सिंचाई विकास के लिए होने वाले व्यय में निर्देशानुसार क्षेत्रीय संतुलन बनाया गया.
- निर्देशांक व अनुशेष समिति के 1 अप्रैल 2002 केबाकी आर्थिक अनुशेष वर्ष 2009-10 में दूर किए गए.
- इन 5 वर्षों में 7.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का निर्माण हुआ.
- इन 5 वर्षों में 4,182 टीएमसी पानी स्टोर करने की क्षमता में वृद्धि हुई.
- पिछले 5 वर्षों में सिंचन क्षमता का उपयोग करने में 10.33 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई.
- वर्ष 2002 से अब तक जलविद्युत प्रकल्प की स्थापित क्षमता में 657 मेगावाट बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई.

महाराष्ट्र सिंचन पद्धति के कृषकों द्वारा व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के तहत सिंचाई व्यवस्थापन के माध्यम से किसानों के साथ सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से प्रावधान किए गए हैं.

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों पानी का स्थान महत्वपूर्ण होता जा रहा है. राज्य के जल संपदा मंत्री सुनील तटकरे ने अपनी परंपरागत प्रबंधन शैली और राजनीतिक शैली में जल संकट से निपटने के साथ-साथ जल-संग्रह बढ़ाने के भी कई सराहनीय प्रयास किए हैं. वे ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें मालूम है कि राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए पानी की कितनी ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जल-संग्रहण कितना ज़रूरी है. यही कारण है कि जल संपदा विभाग की परियोजनाओं के जिन कामों में अजीत पवार के आने से तेज़ी आई थी, अब उनके जल संपदा मंत्री बनते ही वह संपूर्णता की ओर अग्रसर हैं. चौथी दुनिया महाराष्ट्र ने सुनील तटकरे से राज्य की जल स्थिति पर ख़ास बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश-

प्रश्न: जल संपदा मंत्री पद की बागडोर संभालने के बाद आपने कौन-से महत्वपूर्ण निर्णय लिए?

तटकरे: राज्य की जल नीति में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति को उद्योगों से पहले प्राथमिकता दी गई. जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण अधिनियम में बिना पानी आरक्षण अधिकार बाबत सुधार विधेयक विधानमंडल में पारित कराया गया. आदिवासी क्षेत्र व नक्सल प्रभावित ज़िला गड़चिरोली में शुरू होने वाली नई योजनाओं के अलावा कहीं भी कोई नया प्रकल्प शुरू नहीं किया जा सकता. निर्माणाधीन प्रकल्पों को पूरा करने, सिंचन निर्मित व पानी स्टोर के कार्य को प्राथमिकता देने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. शासन के निर्देशों के अनुसार दी गई सूचना के तहत अंतिम चरण में पहुंच चुके प्रकल्पों को प्रधानता दी गई है. राज्य में सिंचाई के लिए 6,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसकी मदद से 2 लाख 60 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई और 67 अरब घनफुट पानी संग्रह करने के लिए 2010-11 में 329 प्रकल्प पूरे किए गए. इन प्रकल्पों के बाक़ी बचे कार्यों व दायित्वों को पूरा करने हेतु बजट में 87.0526 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्यपाल के निर्देशों पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने विचार-विमर्श कर उपलब्ध प्रस्ताव का समुचित नियोजन करने का प्रयत्न किया है.

प्रश्न: सिंचन विस्तार व सुधार के लिए विदर्भ की दृष्टि से क्या निर्णय लिए हैं?

तटकरे: राष्ट्रीय प्रकल्प गोसीखुर्द के लिए राज्य सरकार ने 508 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल के तहत 278 परियोजनाएं चल रही हैं. इनके अंतर्गत सन 2011-12 में 2814.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. एआईबीपी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का काम जारी है. इसके लिए सन 2011-12 में राज्य के बजट संकल्प के अंतर्गत 1585.21 करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसमें केंद्रीय सहायता के तौर पर 1251.31 करोड़ रुपये की सहायता अपेक्षित है.

प्रश्न: जल सिंचन के अंतर्गत राज्य का कितना क्षेत्रफल आता है?

तटकरे: जून 2010 के अंत तक राज्य में राज्यस्तरीय प्रकल्प से 47.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास हुआ. वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त 1.5 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता निर्मित होने की आशा है.

प्रश्न: सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कौन-से प्रयत्न किए जा रहे हैं?

तटकरे: वर्तमान स्थिति में राज्य में 763 प्रकल्प प्रगति पर हैं. 1 अप्रैल तक उनकी उर्वरित लागत 75 हज़ार करोड़ रुपये थी जिससे 38.79 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षेत्र विकसित होगा. केंद्र सरकार की ए.आई.बी.पी. योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र को दो-तीन वर्षों से काफ़ी आर्थिक मदद मिल रही है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और उसके लिए सिंचाई अति आवश्यक है-इस बात को ध्यान में रखकर सरकार अच्छी-ख़ासी निधि उपलब्ध करा रही है.

प्रश्न: बंजर खेती को सिंचाई क्षेत्र में लाने के लिए किस तरह का नियोजन किया जा रहा है?

तटकरे: ए.आई.बी.पी., नाबार्ड, विश्व बैंक व अन्य संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सिंचाई प्रकल्पों को पूरा करना या फिर नई सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर अधिक से अधिक बंजर ज़मीन को सिंचन क्षेत्र में लाने का सरकार का प्रयत्न रहेगा.

प्रश्न: पीने के पानी और खेती के पानी को बांटने का फार्मूला क्या है?

तटकरे: पानी वितरण की व्यवस्था बांधों में उपलब्ध पानी के हिसाब से की गई है. पानी वितरण का फार्मूला इस तरह है- जलाशय में उपलब्ध पानी का 15 प्रतिशत पीने के लिए, 10 प्रतिशत उद्योगों के लिए और 75 प्रतिशत पानी का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा. सरकार की पहले की नीति के अनुसार पीने के पानी सहित सभी प्रकार के बगैर सिंचन कार्यों उद्योग, औष्णिक विद्युत प्रकल्प आदि कार्य करने वाली संस्थाओं को पानी का आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव जलसंपदा विभाग को प्राप्त हुए, जिसके लिए जलसंपदा विभाग के जलाशय में उपलब्ध पानी के 15 प्रतिशत से कम होने पर जलसंपदा विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता, 15 प्रतिशत अथवा 15 से 25 प्रतिशत से कम पानी के आरक्षण का प्रस्ताव होने पर मंत्रालयीन अंतरविभागीय सचिव-स्तरीय समिति और 25 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पानी आरक्षण के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की उपसमिति, जलसंपदा मंत्री (कृखोपाम को छोड़कर) की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति मान्यता दे सकती थी. महाराष्ट्र सिंचाई अधिनियम 1976 और महाराष्ट्र जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 द्वारा सिंचाई प्रकल्पों के पानी का सिंचन व बगैर सिंचन प्रयोजन के लिए बांटने का प्रावधान किया गया है. महाराष्ट्र सिंचन पद्धति के कृषकों द्वारा व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के तहत सिंचाई व्यवस्थापन के माध्यम से किसानों के साथ सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से प्रावधान किए गए हैं. उपरोक्त तीनों अधिनियमों के प्रावधान पर विचार करके राज्य सरकार व महाराष्ट्र जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण के नियमत: अधिकार कौन से हैं, इसको लेकर भ्रम होने से महाराष्ट्र जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण (संशोधन व आगे लागू रखने) अधिनियम 2011 को 22 अप्रैल 2011 को मंज़ूर किया गया.

प्रश्न: जलसंपदा विभाग में साढ़े आठ हज़ार पद भरने का अनुशेष बाक़ी है, अनुशेष को भरने के क्या उपाय किए जा रहे हैं?

तटकरे: जलसंपदा विभाग में 43,971 पद मंज़ूर किए गए हैं. वर्तमान स्थिति में 35,625 पदों पर अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं. 8,292 पद रिक्त हैं. वित्त विभाग के तहत 5 जून 2010 के सरकारी निर्णय के अनुसार गट क व गट ड संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती पर रोक लगाई गई है. इसके बावजूद 13 अप्रैल 2011 को लिए गए निर्णय में पिछड़े वर्ग के अनुशेष की समीक्षा कर भर्ती के संदर्भ में प्रस्ताव पेश करने की सूचना दी गई जिसके आधार पर विभागीय कार्यवाही शुरू है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य

1- अतिरिक्त सिंचन क्षमता: 12 लाख हेक्टेयर
2- अतिरिक्त पानी स्टोर: 6000 टीएमसी
3- गोसीखुर्द प्रकल्प को राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित किए जाने के बाद केंद्रीय सहायता से यह प्रकल्प 5 वर्ष में पूरा हो जाएगा.
4- पूरे होने वाले सिंचाई प्रकल्पों की संख्या: 821
5- निर्माण करने केलिए पानी का उपयोग करने वाली संस्था की संख्या: 2500
6- पानी उपयोग करने वाली संस्था को हस्तांतरित होने वाले क्षेत्र: 10 लाख हेक्टेयर
7- जल विद्युत प्रकल्पों की अतिरिक्त स्थापित क्षमता: 250 मेगावाट
8- बड़े व मझोले सिंचाई प्रकल्पों पर 1.50 लाख हेक्टेयर को लाभान्वित करने के लिए विकास कार्य पूर्ण होने की संभावना.
9- अंतरराज्यीय व राज्यांतर्गत नदी जोड़ परियोजनाओं का अध्ययन किया जा रहा है.
10- पुराने बांधों व जलाशयों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना की जाएगी.
11- अत्याधुनिक ठिंबक व तुषार सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग के माध्यम से प्रयास किए जाएंगे.
12- पुराने मालगुजारी तालाबों (134) का पुनर्निर्माण व पुन:स्थापना की जाएगी.
13- विविध कार्यों के लिए ई-निविदा निकालने से निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और ठेकेदारों को निविदा पुस्तिका प्राप्त करने और भरने में सुविधा होगी.
14- शासकीय योजनाओं का लाभ लेने केलिए नागरिकों को ई-पेमेंट द्वारा पैसे भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
15- कृष्णा व भीमा नदी के मध्य में बाढ़ का अनुमान लगाने हेतु रियल डाटा टाइम उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की जाएगी.
16- कृषकों की सिंचन व्यवस्थापन में सहभागिता को बढ़ावा देने केलिए शासन ने महात्मा फुले पानी वापर संस्था अभियान शुरू किया है. इसके तहत पुण्यलोक अहिल्या देवी होलकर पानी वापर (उपयोग) संस्था व्यवस्थापन

ये क्या हो रहा है...

मदमस्त सरकार पस्त विपक्ष

आख़िर महंगाई को घटाने के लिए सोनिया और गडकरी की राज्य सरकारें क्या कर रही हैं. कुछ रुपए या पैसे गैस सिलेंडर या डीजल पर कम कर देने से ट्रक भाड़ा तो कम नहीं हो जाएगा न.

लोकतंत्र की यह कौन-सी बानगी है भाई... पेट्रोल के बाद अब डीजल, केरोसिन और रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए. साफ़ है कि सरकार यहां मदमस्त हो चली है और विपक्ष पूरी तरह पस्त हो चुका है. हर जगह यही हाल है. फिर चाहे वह केंद्र हो या राज्य. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार... हर जगह एक ही खेल... यानी चोर-चोर मौसेरे भाई. जो सरकार में उसका हिस्सा ज़्यादा और जो विपक्ष में है, उसका हिस्सा कम. जो मीडिया में है या फिर किसी एनजीओ से जुड़ा है, जो थोड़ा बहुत होहल्ला कर सकता है, उसकी तरफ़ भी एकाध रोटी उछाल दी यानी हर जगह बंदरबांट. कोर्ट ने ज़्यादा सख़्ती दिखाई तो एक-आध को जेल में डाल दिया पर वहां भी सीबीआई और पिटीशन दायर करने वाले का संदिग्ध चरित्र... क्या हो रहा है यह सब... घोटालों पर घोटाले. केंद्र सरकार के मनमाने निर्णय. महाराष्ट्र सरकार के मनमाने निर्णय.

भूविस्थापितों के मामले में गोसीखुर्द के लिए अलग मापदंड, जैतापुर के लिए अलग. आदर्श घोटाले में रोज़ नए-नए विरोधाभास. विलासराव देशमुख के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के तल्ख़ तेवर के बाद भी कुछ नहीं होता है. और महंगाई पर लगाम लगना तो दूर वह तो सुरसा की तरह मुंह फाड़े जा रही है. उस पर भी सरकार शांत है. विपक्ष छिटपुट विरोध प्रदर्शन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है. भाई, यह लोकतंत्र है. कोई भाड़तंत्र नहीं है. यहां जनता को जवाब तो देना होगा न. मगर जवाब देगा कौन और जनता जवाब मांगेगी किससे. दो ही मठाधीश हैं. एक एनडीए और एक यूपीए. यूपीए नहीं तो एनडीए, एनडीए नहीं तो यूपीए. सबमें मिलीभगत, सब राजनीति में व्यस्त. किसको फ़िक्र है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आधी रात को सो रहे निहत्थे लोगों को सशस्त्र कमांडो घेर लेते हैं. उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं. लाठियां बरसाई जाती हैं. विपक्ष राजघाट पर धरना देता है. रामदेव अनशन पर रहते हैं. उनका अनशन बाद में टूट जाता है. अन्ना हज़ारे का लोकपाल विधेयक राजनीति के गलियारे में भिखमंगे की मुद्रा में खड़ा हो जाता है. क्या है यह सब. मायावती कांग्रेस को गरियाती हैं. जब संसद में विश्वासमत की बारी आती है तो समर्थन दे देती हैं. यही काम मुलायम सिंह भी करते हैं. आख़िर जनता विश्वास करे तो किस पर करे. किसे अपना रहनुमा समझे. कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी को या फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को. सब गोलमाल है. सोनिया मैडम के हाल तो इतने बेहाल हैं कि उनसे गुस्ताख़ी करने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता. अगर की तो हाल रामदेव जैसा होगा. यह संदेश पूरे देश में जा रहा है. आख़िर महंगाई को घटाने के लिए सोनिया और गडकरी की राज्य सरकारें क्या कर रही हैं. कुछ रुपए या पैसे गैस सिलेंडर या डीजल पर कम कर देने से ट्रक भाड़ा तो कम नहीं हो जाएगा न. विपक्ष केपास आज भरपूर लोकतांत्रिक हथियार हैं. भ्रष्टाचार, घोटालों और महंगाई जैसे मुद्दों पर उसे पूरे देश का समर्थन हासिल है फिर भी वह कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाता. आख़िर क्यों. सबको मालूम है, चुनाव अभी दूर हैं. लेकिन मेरे राजनीति केसूरमाओ... उत्तर प्रदेश के चुनाव तो नज़दीक हैं. महाराष्ट्र की 9 स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव भी तो नज़दीक हैं. उनकी तो चिंता करो. कहीं ऐसा न हो कि एक बार हारने का क्रम शुरू हो जाए तो फिर रुके ही न. आज कांग्रेस और भाजपा के बीच ऐसी तिकड़म हो गई है कि न चाहते हुए भी जनता यह सोचने को मजबूर है कि दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं. जो कार्रवाई आज तक हुई है, वह कोर्ट के आदेश पर हुई है. सो आगे भी होने दो और ख़ुश रहो. हमें क्या... हम तो यही कहते रहेंगे कि भाई, ये क्या हो रहा है...

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 11 जुलाई–17 जुलाई 2011

www.chauthiduniya.com

Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY Argora-Kathalmore Road, Ranchi — PLOT 6 LAC / DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY Sidhu Kanhu Park, Kanke Road — PLOT 13 LAC / DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY Ranchi Patna Highway Road — PLOT 3 LAC / BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP 4 Lane, Kanke Road, Ranchi — PLOT 3 LAC / BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION BIT Pithoria, Road, Ranchi — PLOT 3 LAC / BUNGLOW 10 LAC

9661337777 / 9472722024

9472727767 / 9162779209

महादलित आयोग का पुनर्गठन

अधर में लटका है

सरोज सिंह

यूज एंड थ्रो यानी ऐसा हथकंडा जिसका लगभग हर खेल में इस्तेमाल होता है. राजनीति का खेल भी इसका अपवाद नहीं है. हर नेता व हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कुछ लोगों का पहले इस्तेमाल करती है और बाद में उसे हाशिये पर डाल देती है. नीतीश सरकार भी इस खेल में महारत हासिल कर चुकी है. महादलितों का चुनावी इस्तेमाल कर सरकार इसे भूल गई. एनडीए के इस नवसृजित कथित वोट बैंक एक करोड़ बिहारी महादलित की सुध लेने की फ़ुर्सत शायद ही अब किसी को है, तभी तो अजेय बहुमत के साथ उनके दोबारा सत्तासीन होने के ठीक तीसवें दिन 25 दिसंबर, 2010 को बिहार राज्य महादलित आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया. लेकिन छह माह बीतने के बाद भी इसका पुनर्गठन नहीं हुआ है. ग़ौरतलब है कि कभी महादलित आयोग के गठन को बिहार सरकार की अनूठी अनोखी पहल बता, इसे उपलब्धि के तौर पर ख़ूब प्रचारित कर ढिंढोरा पीटा गया था. लेकिन इस आयोग को राजनीतिक बिसात के प्रपंच के मोहरे के तौर पर भरपूर उपयोग किया गया. देश में शायद यह पहला आयोग था जिसने सत्ताधारी दल के लिए रैली भी आयोजित की. 2007 में गठित इस आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य थे. विश्वनाथ ऋषि अध्यक्ष, बबन रावत, राजेंद्र प्रसाद नट और छोटेलाल राजवंशी को सदस्य बनाया गया था. लगभग आधा कार्य काल बीतने के बाद पुन: इसका विस्तार करते हुए रामचंद्र राम को इसका सदस्य बनाया गया था.

महादलित आयोग के प्रति राज्य सरकार के वर्तमान रवैये से यह मखौल बनकर रह गया है. वैसे भी इसमें तुग़लकी तरीक़े से ख़ूब प्रयोग हुआ, जिससे यह बात स्पष्ट रूप से उभरकर आई कि महादलित आयोग चुनावी राजनीति से प्रेरित एजेंडा मात्र था. इसका दलितों के बीच अत्यधिक उपेक्षित पीड़ित तबक़े के उद्धार से कोई लेना देना नहीं था. नीतीश सरकार में महादलितों के प्रति नीतिगत मामलों में तुग़लकी तौर–तरीक़े ही आज़माये गए हैं. सबसे पहले महादलित आयोग गठित कर दलित समुदाय का एक नया वर्गीकरण किया गया था, जिसमें अनुसूचित जातियों में से मोची, पासवान, धोबी एवं पासी बिरादरी के अलावा अन्य जातियों को महादलित घोषित कर दिया गया. दलित समुदाय का यह पृथक्करण राजनीतिक स्वार्थसिद्धी में बाधक साबित होता दिखा था. लिहाज़ा, महादलित आयोग की तथाकथित सिफ़ारिशों के आधार पर पहले धोबी एवं पासी को भी दलित से महादलित का चोला ओढ़ा दिया गया. इसके बाद भी मन में कुछ फांस रह गई थी. उसके बाद पुन: मोची समुदाय को भी दलित से महादलित के तौर पर रूपांतरित कर दिया गया. बिहार में सिर्फ़ पासवान जाति ही आधिकारिक तौर पर दलित कहलाने का हक़दार रह गई. कुर्सीजनित राजनीति का विद्रुप चेहरा तब उजागर हुआ, जब पासवान समुदाय को भी संतुष्ट करने की नीयत से भविष्य में उन्हें भी महादलित का दर्जा प्रदान करने का मुलम्मा दिया गया. हालांकि, दलितों के बीच उपेक्षित तबक़े को उनका वास्तविक हक़ दिलवाने के बहुप्रचारित मक़सद से बिहार में उनका पुन: वर्गीकरण किया गया था. इसके लिए पहली बार देश में महादलित आयोग बनाया गया था. इसके माध्यम से दलितों के बीच के इस तबक़े की पहचान का कथित प्रयास किया गया, जो तमाम सरकारी सहूलियतों के बावजूद विकास की दौड़ में अभी भी सबसे निचले पायदान पर मूक दर्शक की ही भूमिका में जड़वत खड़े हैं. अनुसूचित जातियों के लिए चलाई गई योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा. जिस प्रकार पिछड़ी जातियों के लिए कार्यान्वित कार्यक्रमों का फ़ायदा आमतौर पर तीन–चार जातियों को ही मिल पाया, बल्कि कमोबेश उन्हीं तक सीमित रहा. इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं से कुछ ही जातियां लाभन्वित हो पाईं. इन जातियों का बड़ा वर्ग इससे वंचित रहा. लिहाज़ा, सिर पर मैला ढोने को विवश मेहतर समुदाय के लोगों के लिए इक्कीसवीं सदी का भारत और इसके विकास की अंधी दौड़ कोई मायने नहीं रखती है. महादलित आयोग को पुन: पुनर्गठित करने में देरी के कई कारण गिनाए जाते हैं. एक वजह महादलित आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष विश्वनाथ ऋषि हैं, उनका पुत्र मनोज कुमार गत विधानसभा चुनाव में लोजपा के टिकट पर कोढ़ा सुरक्षित चुनाव लड़ गया था.

यद्यपि वह चुनाव हार गया एवं वहां से सत्ताधारी गठबंधन का अधिकृत भाजपा प्रत्याशी महेश पासवान ही विजयी हुए, लेकिन राज्य सरकार के मुखिया इससे काफ़ी आहत हैं. वहीं पहले महादलित की श्रेणी में धोबी, पासी और मोची समुदाय शामिल नहीं था. लिहाज़ा राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत कम प्रभावशील जातियों को इस आयोग में प्रतिनिधत्व दिया गया था. वर्तमान यह तीनों बिरादरी भी महादलित क़रार दी गई है. इसलिए, दुविधा यह है कि अंतिम पायदान की दलित जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए या, संख्या बल से मज़बूत बिरादरी को स्थान प्रदान कर अपनी राजनीतिक दुकान चमकाई जाए. इस सिलसिले में राज्य सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि महादलित आयोग का पुनर्गठन राज्य के मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. जब उन्हें फ़ुर्सत मिलेगी तब इस पर विचार कर पुनर्गठन करेंगे. एक सदस्य रामचंद्र राम का कार्यकाल बचा हुआ है, हो सकता है इस कारण भी बिलंब हो रहा हो. वैसे भी रामचंद्र राम सर्वाधिक जनसंख्या वाली महादलित बिरादरी मोची समुदाय से आते हैं. चुनावी हित साध महादलितों को भुला दिए जाने के सवाल पर कहते हैं कि यह दिमाग़ी दिवालियापन है. राज्य सरकार महादलितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. पहले की सरकारों ने उसकी सुध क्यों नही ली. जानकारों की राय गत वर्ष अप्रैल महीने में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जन जाति आयोग के अध्यक्ष बूटा सिंह ने महादलित आयोग को असंवैधानिक क़रार दिया था. इस कारण भी राज्य सरकार इससे पल्ला झाड़ सकती है, लेकिन इस वक़्त राज्य की राजग सरकार के तमाम सियासी भोंपू बूटा सिंह पर टूट पड़े थे. उनके उक्त बयान की कड़ी निंदा की थी. मंत्री जीतनराम मांझी को भी यह तर्क अनुपयुक्त लगा. वह कहते हैं कि कतिपय लोग इस मुद्दे पर न्यायालय भी गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली थी. बहरहाल, वजह जो हो लेकिन महादलितों की एक करोड़ से अधिक आबादी ख़ुद को ठगा महसूस कर रही है. सियासी फुटबॉल की तरह दोनों ओर से पीट रहे हैं. उनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की सुस्त रफ्तार और महादलित आयोग के मृतप्राय: होने से इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण और निरीक्षण भी ठप्प है. जदयू से निलंबित राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश कुमार को महादलितों के विकास से कोई सरोकार नहीं है. उनकी यह नौटंकी वोट की राजनीति जनित खेल मात्र है. महादलित आयोग को पुन: बहाल नहीं किए जाने उनकी कुत्सित मंशा बेनक़ाब हो गई है. उन्हें तो महादलितों को भड़काकर सिर्फ़ वोट लेने से मतलब था. चुनाव ख़त्म, चिंता ख़त्म. लिहाज़ा, वह महादलितों को भूल गए. इसलिए विधानसभा चुनाव के ठीक एक महीने बाद महादलित आयोग के समाप्त हो रहे कार्यकाल की उन्हें याद ही नहीं रही. महादलितों के कल्याण के लिए उनके ही द्वारा घोषित योजनाओं के हश्र से भी उनके राजनीतिक स्वार्थ के दुर्गंध की बू आती है. युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद आलोक मेहता आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक रैली आयोजित करवाकर इस आयोग की निष्पक्षता को संदेह के घेरे में डालने का श्रेय भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जाता है. वह इसके उद्देश्यों के प्रति कभी गंभीर नहीं रहे हैं. यह क्रेडिट लूटने का ज़रिया बनकर रह गया. राज्य सरकार की नीयत सिर्फ़ इससे राजनीतिक लाभ उठाना था. महादलितों के कल्याण के लिए घोषित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का स्तर राज्य सरकार के चेहरे पर तमाचे के समान है. 80 फ़ीसदी घोषणाएं सिर्फ़ फाइलों तक सीमित होकर रह गई. महादलित आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया है, यह भी आम जनता के बीच उद्घाटित नहीं किया गया है. सिर्फ़ राजनीतिक लाभ का हथकंडा बनकर रह गया यह आयोग. दूसरी तरफ़ बबन रावत कहते हैं कि सरकार ने महादलितों के लिए जो किया वह अपने आप में एक मिसाल है.

नीतीश कुमार महादलितों के दर्द से वाक़िफ़ हैं और उनके कल्याण के लिए सारे काम किए जा रहे हैं. बहरहाल नेताओं के तीर चल रहे हैं, पर सूबे के महादलित चाहते हैं कि उनकी देखभाल के लिए बना आयोग एक बार फिर अस्तित्व में आए.

feedback@chauthiduniya.com

शिव चंद्र राम

रमई राम

बबन रावत

सरकार ने महादलितों के लिए जो किया वह अपने आप में एक मिसाल है. नीतीश कुमार महादलितों के दर्द से वाक़िफ़ हैं और उनके कल्याण के लिए सारे काम किए जा रहे हैं.

आलोक मेहता

राजनीतिक रैली आयोजित करवाकर इस आयोग की निष्पक्षता को संदेह घेरे में डालने का श्रेय भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जाता है. वह इसके उद्देश्यों के प्रति कभी गंभीर नहीं रहे हैं. यह क्रेडिट लूटने का ज़रिया बनकर रह गया.

उपेंद्र कुशवाहा

नीतीश कुमार को महादलितों के विकास से कोई सरोकार नहीं है. उनकी यह नौटंकी वोट की राजनीति जनित खेल मात्र है. महादलित आयोग को पुन: बहाल नहीं किए जाने से उनकी कुत्सित मंशा बेनक़ाब हो गई है.

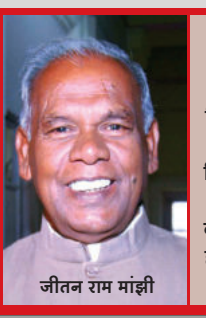

जीतन राम मांझी

महादलित आयोग का पुनर्गठन राज्य के मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. जब उन्हें फ़ुर्सत मिलेगी तब इस पर विचार कर पुनर्गठन करेंगे. एक सदस्य रामचंद्र राम का कार्यकाल बचा हुआ है, हो सकता है इस कारण भी विलंब हो रहा हो.

Ph:0612-3296829, 9334252869, 9386941721

Approved by Govt. of India ... The Way to Grow

SKY CONSULTANCY SERVICE PVT. LTD

DIRECT & CONFIRM ADMISSION

Contact : 604, 6th Floor LUV-Kush Tower Exhibition Road, Patna-1

Ph: 0612-3296829 9334252869 9386941721

2010 Admission Report

Bangalore Chennai Delhi/NCR Punjab Pune Bhopal

Engineering MBA/PGDBM MBBS MCA B.Ed

B.Pharma Polytechnic BBA ITI

Branch: Yadav Market, Near Circuit House Pakri Chowk Ara, Mob;9798662051, 9334006756, Muzaffarpur Chhapra

Email : consultancy.sky.patna@gmail.com

Our Copration with you from 2001 to 2011

SCSPL

जमुई से देवघर को जाने वाली रोड से होकर गुज़रने वाले लोगों के चंचल मन में हर क्षण एक भावुक उम्मीद की स्थिति बन रही थी ...... लगा दादा आए हैं .

फ़र्ज़ीवाड़े और धोखाधड़ी के सहारे वि.वि. शिक्षक बने लोगों ने छात्रों को जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान किया, उसे हासिल कर छात्रों ने क्या मुकाम हासिल किया होगा.

एक नज़र

प्राणायाम से कई फ़ायदे : सुलभ

गहरी सांस भरने से मन स्थिर होता है. इससे ऑक्सीजन को शरीर के भीतर सभी अंगों में प्रवेश करने का पर्याप्त समय मिलता है. ऑक्सीजन एक सफ़ाईकर्मी की तरह शरीर के अंदर की सारी गंदगी और विजातीय तत्वों को अपने साथ बाहर निकाल देती है. इससे शरीर के सभी रोग दूर होते हैं. उपरोक्त बातें यहां गांधी मैदान स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल सभागार में आयोजित तनाव मुक्ति विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में प्रसिद्ध शिक्षाविद समाजसेवी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने कहीं. इसके पूर्व संगोष्ठी का उद्घाटन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने किया. डॉ. मिश्र ने जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला तथा इसे सबको अपनाने का आग्रह किया. संगोष्ठी में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजय पासवान, विधायक अरूण कुमार सिन्हा तथा प्रमोद कुमार प्रेम ने भी संबोधित किया. नवजीवन योग केंद्र के संस्थापक आचार्य विपीन पंतजलि ने इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को स्मरण-शक्ति बढ़ाने तथा शक्ति प्रदान करने वाले प्राणायाम के कई अभ्यासों का प्रशिक्षण प्रदान किया. मंच का संचालन अजय कुमार ने किया. *– चौथी दुनिया ब्यूरो*

जमुई में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा

शिक्षा के क्षेत्र में अब यह ज़िला किसी से कम नहीं रहेगा, क्योंकि यहां जल्द ही पालिटेक्निक कॉलेज का निर्माण होगा. इस कार्य हेतु राशि भी भवन निर्माण आयोग को मुहैया करा दी गई है. इस ज़िले के छात्र-छात्राओं के लिए स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा अब यहां के छात्रों को अन्य ज़िलों में जाना नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही जिलेवासियों को रोज़गर के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे. इस संबंध में जमुई के एडीएम परशुराम राम ने बताया कि पालिटेक्निक कॉलेज का निर्माण जमुई स्थित कल्याणपुर के हनुमान घाट पर बनाने का निर्णय लिया गया है. जिलेवासियों को अब आस लगा हुई है कि कब तक इस भवन का निर्माण होगा और यहां के छात्र-छात्राओं को अपनी पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होगा. *–इमरान ख़ान*

थानेश्वर मंदिर में बाल विवाह होते हैं

समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर प्रत्येक वर्ष दो हज़ार से अधिक जोड़े परिणय सूत्र में बंधते हैं. समस्तीपुर नगर थाना, मुफ्फसिल थाना से बिल्कुल सटे हुए और जिलाधिकारी कार्यालय से पांच सौ मीटर की दूरी पर यह शिव मंदिर अवस्थित है. इसके बावजूद मंदिर में खुलेआम बाल विवाह कराया जाता है. कभी-कभी पुलिस के द्वारा इसे रोकने के लिए कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन मंदिर के पंडे और बिचौलियों की मिलीभगत से बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा है. लोग क़ानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मंदिर में शादी कराते हैं, क्योंकि यहां न तो उम्र देखी जाती है और न ही नाम जिस कारण बिचौलियों की मंदिर परिसर में चांदी कटती है. *– मुकेश कुमार राय*

ऋण सुविधा
वाहन ऋण, सावधि ऋण, कैश क्रेडिट, पैक्सों के वास्ते
ऋण, सुविधा सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध है
विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें
दि कोशी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड
प्रधान कार्यालय - साहू मार्केट, गांधी पथ सहरसा
फोन - 06478-224763, मुकेश - 9709695125, संजय - 9128668231, सौरभ - 9431864426

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
1 YEAR WARRANTY शर्ते लागू
आइये आनन्द उठाएँ प्रकृति के संग
प्रकृति की गोद में और करें बातें अपनी, अपनों से....
मजबूती और खूबसूरती का शानदार नमूना बस 'नेचर' की ही हो सकती है जो रखती है आपके लिए खास ख्याल।
Mfd. By: CENTURY POLYPLAST INDUSTRIES
For trade enquirey Contact
9386595926, 9334115955 or e-mail:centurypolyplast@gmail.com
NATURE MOULDED FURNITURE

BALMUKUND SUPER
TMT ही नहीं SUPER TMT
When red hot steel bar is passed through our unique TMT process (Thermo Mechanically treated), it's outer layer becomes HARD thereby making it extra strong corrosion & fire resistant and the inside part or the steel bar becomes SOFT AND DUCTILE-just like a Cocunut. it makes BALMUKUND SUPER TMT Steel bar the best choice to build your dream home.
Business excellance Award
मेरा मकान... सुरक्षित और सॉलीड निर्माण !!
TMT ही नहीं SUPER TMT
EXTRA STRONG-ECONOMICAL-CORROSION RESISTANT-FIRE RESISTANT

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Estd. 2000
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
- ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of
- Patna University & Magadh University get Practical Training.
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday
Excellent Placement with Handsome Salary
Website : www.psfsm.com
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-6455019, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

लगा शायद दादा आ गए

ज्यों सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने दादा की प्रतिमा का अनावरण किया हज़ारों लोगों की आंखें नम हो गईं. समाधि स्थल के एक छोर पर जेएनयू में दादा के सहपाठी रहे रमेश दीक्षित खड़े थे. सामने दादा की पत्नी पुतुल देवी बैठी थीं. अपनी मां को साहस देती दादा की बड़ी बेटी मानसी कभी अपनी मां का चेहरा तो कभी दादा की कांस्य प्रतिमा को निहार रही थी.

[illegible]

सुशील दीक्षित
feedback@chauthiduniya.com

फारबिसगंज गोलीकांड
रामविलास ने मोर्चा खोला

लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने फारबिसगंज गोलीकांड के दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए संघर्ष का ऐलान कर दिया है. इसके लिए वह लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और देश दुनिया को घटना की गंभीरता से अवगत करा रहे हैं. 6 जून को रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशकित पार्टी एवं राजद की टीम ने घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवारों से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की. 10 जून को फारबिसगंज गोलीकांड के विरोध में पासवान के नेतृत्व में दिल्ली के राजघाट पर लोजपा द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया. इसी घटना के विरोध में 13 जून को पूरे बिहार में ज़िला स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया गया, जिसमें पटना के आर ब्लॉक पर धरना का नेतृत्व स्वयं रामविलास पासवान ने किया. इसके बाद 7 जून को लोजपा और राजद नेताओं द्वारा मांगों से संबंधित एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया. लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 19 जून को पासवान के नेतृत्व में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन से उनके 5 तुग़लक रोड आवास पर मिला. पासवान ने ग्राम भजनपुरा, फारबिसगंज ज़िला अररिया में निर्दोष लोगों की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या को मानवाधिकार का हनन बताया. लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधिमंडल रामविलास पासवान के नेतृत्व में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वज़ाहत हबीबुल्लाह से भी मिला. पासवान ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को यह जानकारी दी कि इस घटना को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है जिसके तहत बिहार की जनता के बीच सद्भावना एवं भाईचारे को ख़त्म कर बिहार में हिन्दू मुसलिम के बीच तनाव पैदा कर गुजरात के मॉडल को अंजाम देना है. वज़ाहत हबीबुल्लाह ने आश्वासन दिया कि वह स्वयं ही घटनास्थल का दौरा करेंगे. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने 21 जून को घटनास्थल का दौरा भी किया. घटना की गंभीरता को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने 22 जून को रामविलास पासवान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से उनके आवास 7 रेसकोर्स पर मुलाक़ात की. घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया. प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे एवं एक जांच टीम तुरंत घटनास्थल पर भेजी जाए. चूंकि राज्य सरकार अभी तक मृतक के परिवारों को कोई मुआवज़ा नहीं दे रही है. इसलिए केंद्र सरकार से आग्रह है कि पीड़ितों को आर्थिक मदद दी जाए, घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए. बंद रास्ते को खोला जाए और पुलिस फायरिंग में संलिप्त अररिया एसपी एवं एसडीओ फारबिसगंज के ख़िलाफ़ 302 का मुक़दमा दर्ज किया जाए तथा अविलंब निलंबित कर अररिया ज़िले से बाहर स्थानांतरित किया जाए. लोजपा ने मांग की है कि बिहार सरकार मृतक परिवारों को 20-20 लाख रुपये और घायलों को 5-5 लाख रुपये मुआवज़ा दे. प्रधानमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया और कहा कि इस संबंध में गृहमंत्री को आवश्यक निर्देश देंगे और वैधानिक रूप से जो भी संभव होगा वह करेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पूर्णिया जिप अध्यक्ष चुनाव
सीमा के लिए दलीय सीमाएं टूटीं

नीरज कुमार सिंह

कहा जाता है राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है. कब कौन नेता पाला बदल ले या कब कौन किसी को समर्थन कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता. कुछ इसी तरह का नज़ारा पूर्णिया में जिप अध्यक्ष के चुनाव में देखा गया जब ज़िला जद (यू) अध्यक्ष आशीष कुमार बब्बू की पत्नी सीमा देवी ने रूपौली के पूर्व विधायक शंकर सिंह की पत्नी प्रतिमा देवी को मात्र दो मतों से हराकर जिप अध्यक्ष का ताज अपने सिर कर लिया. घंटे भर पहले साथ देने की क़समें खाने वाले कुछ सदस्यों ने पल भर में ही दलीय दीवार को तोड़ने हुए अपना पाला बदल लिया और अपने वरिष्ठ नेताओं के फ़रमान पर किसी ख़ास प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाने में अपना मत डाला.

मालूम हो कि पूर्णिया में ज़िला परिषद की 34 सीटें हैं जिसमें से जिप के अध्यक्ष पद के लिए कुल 32 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया, जबकि चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में दो सीटों का प्रमाण पत्र जीत दर्ज करने वाले पूर्व जिप उपाध्यक्ष नीरज सिंह उर्फ़ छोटू सिंह एवं ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष इंदू सिन्हा को नहीं मिला, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र पंचायत एवं नगर निगम के पेंच में फंसा हुआ है. पूर्व के जिप अध्यक्ष के चुनाव में पूर्णिया भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ़ पप्पू सिंह की चली थी. परिणामस्वरूप अपने क़रीबी महिला समर्थक क्रांति सिंह को जिप अध्यक्ष एवं नीरज सिंह उर्फ़ छोटू सिंह को जिप उपाध्यक्ष का पद दिलाने में कामयाबी मिली, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लगता है धमदाहा जद (यू) विधायक लेसी सिंह की ख़ूब चली. परिणामस्वरूप सीमा देवी को अध्यक्ष पद एवं राजेश कुमार सिंह को उपाध्यक्ष का पद मिला. सूत्र बताते हैं कि जिप अध्यक्ष के चुनाव में परदे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका पप्पू यादव एवं पूर्व विधायक रूकमुद्दीन द्वारा निभाया गया और उन्हीं के निर्देश पर जिप सदस्यों ने मतदान किया. परिणामस्वरूप सीमा देवी को कुल 17 मत मिले, वहीं प्रतिमा देवी को 15 मत मिले. मिली जानकारी के अनुसार विगत लोकसभा चुनाव में शंकर सिंह ने पार्टी लाइन से अलग सांसद उदय सिंह के पक्ष में काम किया था जिससे शंकर सिंह को आशा थी कि जिप अध्यक्ष के चुनाव में सांसद की ओर से उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन उनकी आशा पर तुषारापात हो गया.

अगर दो सदस्यों छोटू सिंह एवं इंदू सिन्हा के चुनाव परिणाम पर रोक नहीं लगती तो जिप अध्यक्ष का चुनाव और अधिक रोमांचक होता.

प्रतिमा देवी सीमा देवी उदय सिंह

सूत्र बताते हैं कि अगर दो सदस्यों छोटू सिंह एवं इंदू सिन्हा के चुनाव परिणाम पर रोक नहीं लगती तो जिप अध्यक्ष का चुनाव और अधिक रोमांचक होता. इससे पहले पूर्णिया नगर निगम के मेयर पद पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष शाहिद राजा की पत्नी को मेयर पद मिला वही पप्पू यादव के क़रीबी संतोष यादव को उपमेयर का ताज मिला. इन सभी चुनाव परिणाम को देखते हुए स्थानीय लोग पूर्णिया सांसद कि किरकिरी और राजनीतिक पकड़ ढीली के रूप में देख रहे हैं और आने वाले समय में नए राजनीतिक समीकरण उभरने की बात कर रहे है.

feedback@chauthiduniya.com

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय
गड़बड़-घोटालों की भरमार

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के छात्र-छात्राओं के सपनों पर पानी फिर गया है. सर्वत्र भ्रष्टाचार ने ऐसी आग लगाई है कि विश्वविद्यालय को विकास की पटरी पर आने में वर्षों लग जाएंगे. छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में भारी पैमाने पर गड़बड़ी है. फ़र्ज़ीवाड़े और धोखाधड़ी के सहारे वि.वि. शिक्षक बने लोगों ने छात्रों को जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान किया उसे हासिल कर छात्रों ने क्या मुक़ाम हासिल किया होगा, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है. वि.वि. के पूर्व परीक्षा नियंत्रक, सीनेट सदस्य एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, कई पी.जी. विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ-साथ वि.वि. के रजिस्ट्रार जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोगों की नियुक्ति संदेह के घेरे में है. वि.वि. के अंकेक्षणद ल ने कुल 19 वि.वि. शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया है. ऐसे लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कर दी है. अंकेक्षण दल की आपत्तियों के बाद वि.वि. के शैक्षणिक गलियारों में भूचाल सा आ गया है. अफ़रा-तफ़री के बीच अंकेक्षण दल को मैनेज कर मामले को दबाने के प्रयास तेज़ कर दिए गए हैं.

विश्वविद्यालय शिक्षक की नियुक्ति में शिक्षकों ने संबद्ध महाविद्यालयों के अंगीभूतीकरण के समय बिना पद के (पदरहित) अंगीभूत कॉलेज में स्थानांतरण कर वेतन का भुगतान लिया है. ऐसे शिक्षकों की शासी निकाय (जी.बी.) द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं की गई है. स्वीकृत पद पर नहीं रहते हुए वेतन का भुगतान किया गया है. यही नहीं बिहार विश्वविद्यालय सेवा अयोग द्वारा नियक्ति में सहमति नहीं ली गई है. अंकेक्षण दल की आपत्तियों के बाद संबंधित 19 वि.वि. शिक्षकों को वि.वि. के रजिस्ट्रार ने नोटिस थमा दिया है. रजिस्ट्रार ने अंकेक्षण दल की आपत्तियों के निराकरण के लिए चारों बिंदुओं से संबंधित काग़ज़ात प्रस्तुत करने का निर्देश 19 लोगों को दे दिया है. वि.वि. के ज्ञापांक 301/स्थापना/11 दिनांक 11 मार्च 2011 के माध्यम से जारी किए गए नोटिस के बाद ऐसे आपत्ति के घेरे में आए शिक्षकों ने एकजुट होकर यह कह दिया है कि कोई काग़ज़ात नहीं दिया जाएगा. हालांकि एक दो शिक्षकों ने वि.वि. के कुल सचिव को कुछ जवाब तो सौंपे हैं, लेकिन आपत्तियों के चार बिंदुओं से संबंधित काग़ज़ात नहीं सौंपे गए. महीनों बीत जाने के बावजूद ऐसे वि.वि. शिक्षकों को आपत्तियों का निराकरण नहीं हो सका है. एक शिक्षक के एम कॉम में मात्र 50.5 प्रतिशत अंक ही हैं, जबकि इस समय व्याख्याता में नियुक्ति के लिए 52.5 प्रतिशत अंक निर्धारित थे. इसके अलावा वह संबद्धता प्राप्त कॉलेज में अंगीभूत कॉलेज में स्थानांतरण कराकर आए थे. दोनों ही मामलों में उनकी नियुक्ति गड़बड़ है. जिस संबद्धता प्राप्त कॉलेज में ये अपनी प्रथम नियुक्ति दर्शाते हैं इस कॉलेज में उनकी कभी नियुक्ति हुई ही नहीं. ऐसा वहां के कॉलेज प्रशासन का दावा है. एक अन्य मामले में एक शिक्षिका की नियुक्ति भी गड़बड़ियों की नींव पर है. उन्होंने तो जालसाज़ी की ऐसी लकीर खींच दी कि सुनने वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं. व्याख्याता से रीडर में प्रोन्नति के लिए अपनी प्रथम नियुक्ति तिथि 06.01.1979 को 09.01.1978 बना डाला.

तीन चारणों में प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति के लिए कराए गए स्क्रीनींग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ. वी.के.एस.यू. में फैले सर्वत्र भ्रष्टाचार के कारण छात्र-छात्राओं पर सीधे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वि.वि. के पी.जी. विभागों में कुछ को छोड़कर बाक़ी सब जगह भयावह स्थिति है. वि.वि. कार्यालय का और बुरा हाल है. परीक्षा और पंजीयन शाखा के कर्मचारी तो छात्रों से बिना पैसा लिए काम ही नहीं करते. सासाराम, कैमूर, मोहनिया, रामगढ़, बक्सर, डुमरावं डेहरी डालमिया नगर आदि क्षेत्रों से कार्यवश आनेवाले छात्रों से वसूली कर काम करना इन कर्मचारियों की नियति बन गई है. बैग, अटैची, झोले से ही ये छात्रों के बाहरी होने की पहचान कर लेते हैं. सबसे विकट समस्या तो व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को लेकर है. वि.वि. प्रशासन ने पैसा कमाने के उद्देश्य के साथ धड़ाधड़ कई वोकेशनल कोर्सेज तो खोल दिए, नामांकन करा दिए, रिजल्ट भी प्रकाशित करा दिए गए, लेकिन छात्रों को यह बताया ही नहीं गया कि इन पाठ्यक्रमों की मान्यता ए.आई.सी.टी.ई. से नहीं ली गई है. राजभवन से भी अनुमति लिए बना ऐसे पाठ्यक्रम चलाए गए. अब राजभवन ने ऐसे पाठ्यक्रमों के नामांकन पर रोक लगा दी है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को कोचिंग कराने के लिए दिए जाने वाले पैसे की लूट जारी है. वी.के.एस.यू. में रेमिडियल कोचिंग हाथी दांत बन कर रह गई है. यू.जी.सी की राशि से बना विवि. के एकमात्र गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस थाना खोल दिया गया है. छात्राएं आवास को लेकर परेशान हैं उनकी सुविधा का ख्याल विवि. प्रशासन को नहीं है. हालांकि कमीशन अच्छा देने वाले एक आपूर्तिकर्ता से छात्राओं के लिए पलंग व फर्नीचर की थर्ड क्लास आपूर्ति करा लिया गया है. भवन निर्माण के लिए टेंडर भी चालाकी से कराये जाते हैं. इस समाचार पत्र में टेंडर निकाला जाता है जो अखबार तो आरा शहर में बिकता है लेकिन प्रकाशित टेंडर के अखबार का संस्करण अन्य जिलों का होता है. यह सिर्फ इसी ठेकेदार को पता होता है जिसके साथ वि.वि. प्रशासन मोटी रकम लेकर डील करने वाला होता है वी.के.एस.यू. में भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी लकीर खिंच दी गई है जिसे मिटाना साधारण बात नहीं है. फिलहाल अंदर ही अंदर छात्रों में आक्रोश की चिंगारी सुलग रही है. अगर आक्रोश बढ़ा तो बड़े छात्र आन्दोलन की पृश्ठभूमि तैयार हो जायेगी.

डॉ. सुरेन्द्र सागर
feedback@chauthiduniya.com

करियर दुनिया

आई.आई.टी. में सफलता का कोई शॉट-कट नहीं : वर्मा

आई.आई.टी. परीक्षा की तैयारी कैसे करें

भौतिकशास्त्रविद् एच.के. वर्मा की मानें तो भौतिक शास्त्र में सबसे पहले थ्योरी पर कमांड करें, तब आप से न्यूमरिकल बन सकता है, क्योंकि थ्योरी से न्यूमरिकल बनाया जा सकता है, न्यूमरिकल से थ्योरी नहीं. क्योंकि थ्योरी सर्टन है न्यूमरिकल अनगिनत. सर्टन पर कमांड किया जा सकता है, लेकिन असर्टन पर कमांड नहीं किया जा सकता है . सर्टन से असर्टन को सर्टन बनाया जा सकता है. भौतिक शास्त्र में 70 प्रतिशत प्रश्न बिल्कुल आसान होते हैं. 20 प्रतिशत प्रश्न कठिन होते हैं और 10 प्रतिशत प्रश्न जटिल होते हैं. लेकिन आई.आई.टी. में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 70 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से प्रश्न से नहीं होते हैं. आई.आई.टी. में 10 प्रतिशत जो जटिल प्रश्न होते हैं, उसी से पूछे जाते हैं. इसलिए आप हर टॉपिक के जटिल प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दें.

जटिल प्रश्न कैसे करें हल? – सबसे पहले सभी प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ें. इसके बाद देखें की कौन सी थ्यौरी से प्रश्न हल होगा, उसका प्रयोग उचित तरीके से करें. प्रश्न हल करते समय जिस फॉर्मूला का प्रयोग कर प्रश्न को हल करते हैं, उस समय यह ध्यान दें कि फॉर्मूला में जितने टर्म हैं, उसकी न्यूमरिकल वैल्यू अन्त में रखें.

निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न कैसे हल करें?– निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न पर दो बिन्दुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा. पहला गलती की संख्या कम हो और दूसरा समय की बचत. निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न में गलती कम तब होगी जब आप उतने ही प्रश्नों का जबाब दें जितना आप 100 प्रतिशत जानते हैं. इस प्रश्न को हल न करें जिसे आप नहीं जानते हों. समय बचाने के लिए आप कैलकुलेशन फास्ट करें और प्रश्न पढ़ते समय यह ध्यान दें कि प्रश्न को एक ही बार में पढ़ कर समझने का प्रयत्न करें. तब जाकर आपको आईआईटी की परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी.

सफलता के लिए रणनीति कैसे बनायें? – अगर आप कुल प्रश्नों में से 30 प्रतिशत के उत्तर सही जानते हैं तो फिर आपका चुनाव आईआईटी की परीक्षा में नहीं हो रहा है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को टच कर सकते हैं. लेकिन अगर आप 40 प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर जानते हैं तो आप वैसे प्रश्न का उत्तर नहीं दें जिसमें कुछ भी शक हो. 40 प्रतिशत प्रश्न सही होने पर आपके चुनाव की सम्भावना बढ़ जाती है. अगर आप 60 प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर जानते हैं तब आप समझें कि आपका चुनाव आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में हो रहा है. तब आप 10 प्रतिशत प्रश्न वैसे हल कर सकते हैं जिन पर आपको थोड़ा गलत होने की सम्भावना कम है. अगर 10 प्रतिशत प्रश्नों में से 5 प्रतिशत सही हो जाता है और 5 प्रतिशत अगर गलत हो जाता है तब भी आपका प्रतिशत 60 से अधिक हो जायेगा. यानी आपकी रैंक और अच्छा हो सकता है.

एच.के. वर्मा

भौतिक शास्त्र में किस अध्याय पर ज़्यादा ध्यान दें?

सर्वप्रथम आप देख लें कि कौन से अध्याय में आपकी ज़्यादा रूचि है, उस अध्याय पर ज़्यादा ध्यान दें. भौतिक शास्त्र में सबसे ज़्यादा आसान प्रश्न Light, Current, Electrostatic, sound Heat, Modern Physics से होते हैं. इस टॉपिक से ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं बनाए जा सकते हैं. इस टॉपिक का निरंतर अभ्यास से आईआईटी प्रवेश परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है. लेकिन मिकीनिक्स से जटिल प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जिसके उत्तर देने में आपको कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है.

अध्ययन के लिए कितना समय दें – सबसे पहले आपकी प्रत्येक दिन की दिनचर्या सही होनी चाहिए. एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे का लेखा-जोखा होना चाहिए. अर्थात रुटीन के अनुसार अध्ययन करें. सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब भी आप रुटीन बनाते हैं तो आपका रुटीन सफल नहीं हो पाता है तो आप क्यों नहीं जांचते हैं कि आपका रुटीन क्यों नहीं सफल हो पाता है. आपका रुटीन सफल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप रुटीन बनाकर इसके बाद अध्ययन करते हैं. पहले आप एक सप्ताह अध्ययन करके तब उसके अनुसार रुटीन तैयार करेंगे तब जाकर आपका रुटीन असफल नहीं होगा. ऐसे प्रत्येक दिन आप कोचिंग करने के बाद सेल्फ स्टडी पर 6 घंटा अध्ययन करें तो आपको आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में सफलता मिल सकती है. छात्रों के मन में अगर कोई सवाल हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9430221784 और 9234388457 पर संपर्क कर सकते हैं.

रोज़गारोन्मुखी शिक्षा का केंद्र देवघर हिन्दी विद्यापीठ – देवघर स्थित हिन्दी विद्यापीठ राष्ट्रभाषा हिन्दी को जन-जन तक पहुंचाने में विगत 6 दशकों से निरंतर कार्यरत है. हिन्दी विद्यापीठ की परीक्षाओं को भारत सरकार एवं देश की कई राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है. यहां से हर वर्ष सैकड़ों विद्यार्थी मैट्रिक स्तर की प्रवेशिका, इंटर स्तर की साहित्यभूषण एवं स्नातक स्तर की साहित्यालंकार डिग्री प्राप्त कर देश के कई सरकारी एवं ग़ैर सरकारी संस्थानों में नौकरी कर सुखी जीवन बिता रहे हैं. हिन्दी विद्यापीठ की एक ख़ास विशेषता यह है कि यहां ग़ैर हिंदी प्रदेशों के सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं परिसर में ही छात्रावास में रहकर पढ़ाई पूरी करते हैं और डिग्री प्राप्त कर उच्च पदों पर नौकरी कर रहे हैं. पूरा हिन्दी विद्यापीठ परिवार संस्थान की गरिमा को बढ़ाने में सदैव कृतसंकल्पित हैं. संस्थान के व्यवस्थापक व पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा के अनुशासित मार्गदर्शन में हिन्दी विद्यापीठ वैश्वीकरण के युग में ज्ञान विज्ञान को जनसाधारण तक हिन्दी के माध्यम से पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत है. डॉ मोहनानंद मिश्र द्वारा रचित पत्रिका समस्त भारत में हिन्दी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है.

अवसर – संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमान्डेन्ट) के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. रिक्तियों की संख्या –

परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जानेवाली रिक्तियों की अस्थायी संख्या निम्नलिखित है–

1) बीएसएफ	-	111
2) सीआरपीएफ	-	213
3) सीआईएसएफ	-	15
4) आईटीबीपी	-	36
5) एसएसबी	-	122

कैसे आवेदन करें – उम्मीदवार वेबसाइट– http://www.upsconline.nic.in में पद का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नए सामान्य आवेदन प्रपत्र (फॉर्म- ई) का प्रयोग करके ऑफलाइन मोड के ज़रिये भी आवेदन कर सकते हैं. यह प्रपत्र 30 रुपये के नकद भुगतान पद देश भर के निर्दिष्ट किसी भी प्रधान डाकघरों से ख़रीदे जा सकते हैं.

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ – ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र 18 जुलाई 2011 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक भरे जा सकते हैं. जबकि ऑफ लाइन आवेदन प्रपत्र डाक/स्पीड पोस्ट से 25 जुलाई 2011 तक संघ लोक सेवा अयोग का कार्यालय पहुंच जाना चाहिए.

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – बैचलर या समकक्ष डिग्री

प्रवेश सूचना

नेशनलपावर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट
वेबसाईट – www.npti.in
पाठ्यक्रम – पी जी डिप्लोमा इन जी आईएस एंड रिमोट ट्रेनिंग
योग्यता – बैचलर डिग्री या समकक्ष
अंतिम तिथि – 13 जुलाई

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट –
वेबसाइट – www.nipccd.nic.in
पाठ्यक्रम – एडवांस्ड डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग
योग्यता – सोशलवर्क या साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट में मास्टर डिग्री इन विषयों में ग्रेजुएट होने पर पांच साल का कार्यानुभव होना चाहिए. चार वर्ष के अनुभव वाले बीएड अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं.
अंतिम तिथि – 5 जुलाई

पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी –
वेबसाईट – www.updu.ac.in
पाठ्यक्रम – एमटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग
योग्यता – पेट्रोलियम या केमिकलइंजीनियरिंग से जुड़े किसी भी विषय में मास्टर्स डिग्री
अंतिम तिथि – 8 जुलाई

लखनऊ विश्वविद्यालय –
वेबसाईट – www.lkouniv.ac.in
पाठ्यक्रम – एमए इन ज्योग्राफी
योग्यता – बीए इन ज्योग्राफी
अंतिम तिथि – 20 जुलाई

नेशनलइंस्टीच्यूट ऑफ टूरिस्ट एंड हॉस्पैटलिटी मैनेजमेंट, हैदराबाद
वेबसाईट – www.nithm.ac.in
पाठ्यक्रम – एमबीए इन टूरिस्ट एंड हॉस्पिटिलिटी मैनेजमेंट
योग्यता – 50 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर डिग्री

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय
वेबसाईट – www.hindivishwa.org
पाठ्यक्रम – एमबीए/बीबीए/डिप्लोमा इन मैनेजमेंट/पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट
अंतिम तिथि – 31 अगस्त

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

क्विज इस हफ्ते

- इस वर्ष मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज देने की घोषणा की गई – फिलिप रोथ
- वह नगर जहां अल्पविकसित देशों का चौथा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मई 2011 में सम्पन्न हुआ – इस्तांबुल
- मई 2011 में एलिफैंट-8 मिनिस्ट्रियल मीट कहां आयोजित किया गया – भारत
- वह बल्लेबाज जिसने सबसे पहले आईपीएल क्रिकेट आयोजन के सभी संस्करणों में दो शतक बनाकर रिकॉर्ड स्थापित किया – क्रिस गेल
- वे शेरपा जिसने मई 2011 में 21 वीं बार एवरेस्ट आरोहरण का रिकॉर्ड बनाया – शेरपा अप्पा
- वह स्थान जहां आसियान का 18वां शिखर सम्मेलन मई 2011 में संपन्न हुआ – जकार्ता
- मानवाधिकार संबंधी वह अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका मई 2011 को भारत सदस्य निर्वाचित हुआ – यूएन.ह्यूमन राइटस काउंसिल
- वह नाम जो भारत की थलसेना तथा वायुसेना के मई 2011 में सम्पन्न संयुक्त युद्ध अभ्यास को दिया गया – विजयी भव
- लांग वॉक टू फ्रीडम के लेखक का नाम है – नेल्सन मंडेला
- ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन हैं – वीएस नायपाल

हिंदी विद्यापीठ की परीक्षाओं को भारत सरकार एवं देश के कई राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है. यहां से हर वर्ष सैकड़ों विद्यार्थी मैट्रिक स्तर की प्रवेशिका, इंटर स्तर की साहित्यभूषण एवं स्नातक स्तर का साहित्यालंकार डिग्री प्राप्त कर देश के कई सरकारी एवं ग़ैर सरकारी संस्थानों में नौकरी कर सुखी जीवन बिता रहे हैं. हिन्दी विद्यापीठ की एक ख़ास विषेशता यह है कि यहां ग़ैर हिन्दी प्रदेशों के सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं परिसर में ही छात्रावास में रहकर पढ़ाई पूरी करते हैं और डिग्री प्राप्त कर अपने प्रदेशों में उच्च पदों पर नौकरी कर रहे हैं.